47वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

.:18/2, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टिट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू), नई दिल्ली, भारत - 110067

.: 011-26569303, 26569780, 26569784

.: https://www.nipfp.org.in

47वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

01 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023

प्रकाशक:

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)

18/2, सत्संग विहार मार्ग,

विशेष इंस्टिट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू),

नई दिल्ली 110067

दूरभाष.: 011 26569303, 26569780, 26569784

फैक्स: 91-11-26852548

ई-मेलI: policy.communications@nipfp.org

वेबसाइट: www.nipfp.org.in

संकलनकर्ता: अमिता मनहास

डिजाइनकार: रोहित दत्ता

मुद्रक:: कुमार ब्रदर्स

ई-मेल:: krbrotherdelhi@gmail.com

विषय-सूची तालिका

प्रस्तावना 7

संस्थान का परिचय 7

शासी निकाय 7

परियोजनाओं का सारांश : पूर्ण की गईं और चल रहीं 8

क्षमता-निर्माण कार्यक्रम 9

आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर रिपोर्ट 10

घटनाक्रम 11

नियुक्तियां 11

सेवानिवृत्ति 11

त्यागपत्र 11

अनुसंधान क्रियाकलाप 12

पूर्ण किए गए अध्ययन 12

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप 12

वित्त मंत्रालय के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप 15

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप 20

चल रहे अध्ययन 24

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए चल रहे अध्ययन 24

वित्त मंत्रालय के लिए चल रहे अध्ययन 26

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए चल रहे अध्ययन 32

आरंभ की गईं नई परियोजनाएं 36

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नई परियोजनाएं 36

वित्त मंत्रालय के लिए नई परियोजनाएं 36

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए नई परियोजनाएं 37

कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन 39

प्रशिक्षण कार्यक्रम 41

प्रकाशन और संचार 43

पुस्तकालय और सूचना केंद्र..... 44

संकाय क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं 50

अनुबंध..... 75

अनुबंध I: अध्ययनों की सूची 2022-23..... 77

पूर्ण अध्ययन 77

चल रहे अध्ययन 81

आरंभ किए गए नए अध्ययन 86

अनुबंध II: एनआईपीएफपी: कार्यकारी पत्र श्रृंखला 87

अनुबंध III: एनआईपीएफपी: आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला 88

अनुबंध IV: शासी निकाय सदस्यों की सूची 89

अनुबंध V: समूल्य प्रकाशनों की सूची..... 93

अनुबंध VI: एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री..... 98

अनुबंध VII: 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार स्टाफ सदस्यों की सूची..... 105

अनुबंध VIII: 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक, निगमित, स्थायी और सामान्य सदस्यों की सूची 109

अनुबंध IX: वित्त और लेखे..... 111

1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट संस्थान में किए गए कार्यों का सिंहावलोकन प्रस्तुत करती है और यह इसके शासी निकाय और जनता के प्रति इसकी जवाबदेही का प्रतिबिंब है। 47वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के दौरान एनआईपीएफपी द्वारा संचालित क्रियाकलापों का अवलोकन कराती है। वर्तमान और पिछली वार्षिक रिपोर्ट की डिजिटल प्रति का अवलोकन संस्थान की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

संस्थान का परिचय

एनआईपीएफपी की स्थापना 1976 में लोक अर्थशास्त्र और नीतियों के क्षेत्र में एक अनुसंधान के केंद्र के रूप में की गई थी। संस्थान की स्थापना वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, अनेक राज्य सरकारों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की संयुक्त पहल पर एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। एनआईपीएफपी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। संस्थान सार्वजनिक वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, नीतिगत परामर्श और क्षमता निर्माण का कार्य करता है। संस्थान के मुख्य अधिदेशों में से एक साक्ष्य-आधारित नीति इनपुट प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों को तैयार करने और उनका सुधार करने में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की सहायता करना है।

अपने 47 वर्षों के अस्तित्व में, संस्थान भारत में एक प्रमुख परामर्श केंद्र के रूप में उभरा है और इसने सरकार के सभी स्तरों पर नीति सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने सदैव ही केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध बनाए रखा है, तथा भारत और विदेश, दोनों में अन्य शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के साथ भी संबंध स्थापित किए हैं। यद्यपि संस्थान को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है, यह अनुसंधान और नीति के अन्वेषण में अपनी एक स्वतंत्र गैर-सरकारी प्रकृति बनाए रखता है।

शासी निकाय

संस्थान के शासी निकाय ने 18 जून 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अपना पुनर्गठन आगे चार वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 5 अप्रैल 2020 से 4 अप्रैल 2024 तक किया। डॉ. उर्जित पटेल अध्यक्ष के रूप में शासी निकाय के प्रमुख हैं। वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री संजय मल्होत्रा, राजस्व सचिव, श्री अजय सेठ, सचिव (आर्थिक मामले) और डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजीव रंजन और नीति आयोग का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय द्वारा किया जाता है। प्रायोजक राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं:

श्री एन. मुरुगानंदम, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार; श्री विशाल कुमार देव, आईएएस, प्रधान सचिव (वित्त विभाग), ओडिशा सरकार; और श्री जे.पी. गुप्ता, आईएएस, प्रधान सचिव, गुजरात सरकार। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों श्री समीर कुमार सिन्हा, आईएएस, प्रधान सचिव, असम सरकार, श्री संजय एम. कौल, आईएएस, सचिव (वित्त-व्यय), केरल सरकार, और श्री मनोज सौनिक, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार ने शासी निकाय में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने श्री बी. प्रसन्ना, ग्लोबल हेड - मार्केट्स (सेल्स, ट्रेडिंग एंड रिसर्च) को शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया है। श्री सुमंत सिन्हा, अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), और श्री सुभ्रकांत पांडा, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) संस्थाओं से नामांकित सदस्य हैं।

शासी निकाय में तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी शामिल हैं - डॉ. एम. गोविंदा राव, पूर्व सदस्य, चौदहवां वित्त आयोग; डॉ. ज्योत्सना जालान, अर्थशास्त्र की प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता; और डॉ. माला लालवानी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रोफेसर, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई।

सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं - डॉ. पूनम गुप्ता, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), और सुश्री यामिनी अय्यर, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)। सीए (सुश्री) केमिशा सोनी, परिषद की सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शासी निकाय की सह-चयनित सदस्य हैं।

डॉ. आर. कविता राव शासी निकाय की वर्तमान निदेशक और पदेन सदस्य हैं। डॉ. प्रताप रंजन जेना, प्रोफेसर मंडल में एनआईपीएफपी संकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शासी निकाय में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं - श्री नितिन गुप्ता, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, और श्री विवेक जौहरी, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। (विवरण के लिए अनुबंध IV देखें।)

परियोजनाओं का सारांश : पूर्ण की गईं और चल रहीं

वर्ष 2022-23 में, एनआईपीएफपी ने अनेक विषयों पर अध्ययन पूर्ण किए। कार्य के व्यापक क्षेत्रों में माल और सेवा कर (जीएसटी), स्वास्थ्य पर व्यय, मध्यम अवधि की व्यय योजना, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि का अनुपालन, वृहद आर्थिक मूल्यांकन, उप-राष्ट्रीय सरकारों का वित्त, सतत विकास लक्ष्य, एमएसएमई और उपभोक्ता वित्त शिकायत निवारण शामिल हैं।

एनआईपीएफपी ने अपने दायरे में जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त, क्रिप्टोकरेंसी का विश्लेषण, प्रत्यक्ष कर से संबंधित मुकदमेबाजी प्रबंधन और राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के संकलन के मुद्दों को भी शामिल किया है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वर्ष 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या पक्षकारों के सम्मेलन (कॉप-27) और भारत के पहले राष्ट्रीय अनुकूलन संचार के लिए सार्वजनिक व्यय पर एक अध्ययन भी संचालित किया गया था। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए वित्त में तेजी लाने के लिए उप-राष्ट्रीय कार्यों पर विशिष्ट अध्ययन, प्रत्यक्ष करों के मामले में मुकदमेबाजी प्रबंधन और पुडुचेरी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का तीसरे पक्षकार का मूल्यांकन संचालित की गई कतिपय नई पहलें थीं।

मुख्य लोक वित्त के क्षेत्र में, राज्यों के राजस्व पर जीएसटी का प्रभाव, राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजे की वापसी का प्रभाव, राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अनुपालन पर तृतीय पक्षकार की लेखापरीक्षा, राजकोषीय स्थिरता विश्लेषण और ऋण प्रबंधन, पर अध्ययन जारी हैं ताकि संस्थान की अनुसंधान प्रोफ़ाइल का ध्यान-केन्द्रण और अधिदेश को सुदृढ़ किया जा सके। अन्य सामयिक क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विश्लेषण और महामारी से प्रेरित मुद्दे शामिल हैं जो नीतिगत दृष्टि से ध्यान आकर्षित करते रहते हैं।

अर्थव्यवस्था की स्थिति और विषयगत शोध पत्रों पर त्रैमासिक रिपोर्ट के संदर्भ में संस्थान के पास प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के लिए अनुसंधान आउटपुट का निरंतर प्रवाह विद्यमान था। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के साथ हमारे निरंतर जुड़ाव ने क्रिप्टोकरेंसी, ऋण प्रबंधन, वित्तीय तनाव, बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की निगरानी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मात्रा में अनुसंधान और नीतिगत आउटपुट का सृजन किया है।

राज्य वित्त की निगरानी के हमारे प्रयास हर साल जारी रहते हैं क्योंकि हम एनआईपीएफपी में अपने राज्य वित्त डेटा बैंक को नियमित रूप से अद्यतन बनाते रहते हैं और भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी की तैयारी में भी योगदान देते हैं। (सभी परियोजनाओं के विवरण के लिए अनुसंधान क्रियाकलाप का अवलोकन करें और अनुबंध I देखें)।

क्षमता-निर्माण कार्यक्रम

एनआईपीएफपी ने अपने अधिदेश की प्रासंगिकता के मुद्दों पर वर्ष के दौरान अनेक कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए।

संस्थान ने 3-4 नवंबर 2022 को एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में 'क्रेडिट मार्केट्स' पर दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

एनआईपीएफपी द्वारा निम्न का संचालन भी किया गया:

- एनआईपीएफपी में 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव' पर दो-दिवसीय सम्मेलन, 28-29 नवंबर 2022.
- एनआईपीएफपी में 'वैश्विक कर संगोष्ठी - 2022' पर एक वेबिनार, 1-2 दिसंबर 2022.
- एनआईपीएफपी में 20 दिसंबर 2022 को 'भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व-बजट (वित्त वर्ष 2023-24) समीक्षा, 2022-23' पर एक विशेषज्ञ विश्लेषण और वार्ता।
- 22 दिसंबर 2022 को एनआईपीएफपी में 'महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में लैंगिक बजटिंग का संस्थागतकरण' पर कंबोडिया के एक प्रतिनिधिमंडल के लिए एक कार्यशाला।
- एनआईपीएफपी में 'क्रिप्टो चैलेंज को नेविगेट करने के लिए नीति ढांचा' पर डीईए पैनल चर्चा, 23 जनवरी 2023.
- पांच संस्थानों अर्थात सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर), इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ), नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और एनआईपीएफपी द्वारा एनसीएईआर परिसर, नई दिल्ली में 'केंद्रीय बजट 2023-24 का अवलोकन' विषय पर सत्रहवीं पांच संस्थान बजट संगोष्ठी 2023 का आयोजन, 6 फरवरी 2023.
- नई दिल्ली में 'भारत में संधारणीय वित्त' पर आधे दिन का सम्मलेन, 10 फरवरी, 2023.

- धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में 'वित्त बाजारों में उपभोक्ता परिवाद निवारण' विषय पर सम्मलेन, 10-11 फरवरी 2023.
- एनआईपीएफपी में 'यह जानने के लिए कि #जस्ट ट्रांजीशन के लिए वित्तीय विचारण क्या हैं, #वैश्विक आईटी वार्ता पर हमारे पावर-पैक्ड और फाइनल पैनल प्रारम्भ करना' विषय पर कार्यशाला, 23 मार्च 2023.

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

- वित्त विभाग, असम सरकार के सहयोग से 'राजकोषीय नीति: परिदृश्य और राजकोषीय पूर्वानुमान/अनुमान' विषय पर असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।, 25-29 अप्रैल 2022.
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं (2021 बैच के 12 अधिकारी और 2020 बैच का एक अधिकारी) के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2-7 मई 2022.
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2-13 मई 2022.
- असम सरकार के वित्त विभाग के सहयोग से विभाग के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएम) के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6-10 जून 2022.
- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'परिणाम बजट पर केंद्रित बजट प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 अगस्त - 1 सितंबर 2022.
- पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10-12 नवंबर 2022.
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के सहयोग से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवाकालीन मध्य-कैरियर अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2-6 जनवरी 2023.
- गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 11-13 जनवरी 2023.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 जनवरी - 10 फरवरी 2023.
- भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13-17 फरवरी 2023.
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20-24 मार्च 2023.

आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर रिपोर्ट

एनआईपीएफपी को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अपने मुख्य कर्मचारियों के वेतन व्यय के 90 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है। वेतन व्यय का शेष भाग और अन्य प्रशासनिक और पूंजीगत व्यय संस्थान के अपने संसाधनों से पूरा किया जाता है। अनुदान के अलावा, संस्थान विभिन्न मंत्रालयों के लिए परियोजनाएं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करके राजस्व भी उत्पन्न करता है। संस्थान के स्वयं के संसाधनों से किए गए व्यय का प्रतिशत 2021-22 में 47.14 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर 58.30 प्रतिशत हो गया।

घटनाक्रम

नियुक्तियां

- डॉ. सुप्रियो डे ने 11 जुलाई 2022 को प्रोफेसर (आरबीआई अध्यक्ष) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
- डॉ. प्रताप रंजन जेना 27 अक्टूबर 2022 को प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
- डॉ. मीता चौधरी ने 27 अक्टूबर 2022 को प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
- डॉ. सच्चिदानंद मुखर्जी ने 2 नवंबर 2022 को प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
- डॉ. रॉली कुकरेजा ने 14 नवंबर 2022 को सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
- डॉ. मालविका महेश ने 16 नवंबर 2022 को सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
- डॉ. पियाली दास ने 16 दिसंबर 2022 को सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

सेवानिवृत्ति

- श्री प्रवीण कुमार, निजी सचिव, 31 मई 2022 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त हुए
- श्री किशन सिंह, छात्रावास सहायक, 30 जून 2022 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त हुए

त्यागपत्र

- सुश्री अलका मट्टा, सचिव ने त्यागपत्र दिया और 26 अक्तूबर 2022 को कार्यमुक्त हो गईं

2 अनुसंधान क्रियाकलाप

पूर्ण किए गए अध्ययन

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप

1. कॉप-27 और भारत के प्रथम राष्ट्रीय अनुकूलन के लिए लोक व्यय, अप्रैल-दिसंबर 2022

प्रायोजक: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

दल: लेखा चक्रवर्ती, अजय नारायण झा, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बलामूर्ति बी.

उद्देश्य: मिस्र में कॉप-27 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में, हमने भारत के प्रथम राष्ट्रीय अनुकूलन संचार के लिए मौजूदा संसाधनों को तैयार करने के लिए जलवायु-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएम) के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण लागू किया। राष्ट्रीय अनुकूलन संचार (एनएसी) के लिए वित्तीय संसाधनों की पहचान करने के लिए विश्लेषणात्मक मैट्रिक्स के भीतर, हमने भारत में अनुकूलन उत्तरदायित्व के लिए 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए क्षेत्रों द्वारा अनुदान की मांग में जलवायु परिवर्तन घटकों की तीव्रता का फसल सुधार और अनुसंधान, सूखा निवारण और बाढ़ नियंत्रण को शामिल करने वाले आठ घटकों अर्थात वन संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और आजीविका संरक्षण, ग्रामीण शिक्षा और अवसरंचना, स्वास्थ्य, जोखिम वित्तपोषण और आपदा प्रबंधन के आधार पर परिकलन किया है। हमने पाया कि 40 से अधिक क्षेत्रीय मंत्रालयों का अनुकूलन-संबंधित व्यय भारत में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 प्रतिशत है। ओपन-एंडेड दृष्टिकोण पर आधारित यह विश्लेषण एनएसी बेसलाइन परिदृश्य अनुमानों की पहचान करने के लिए अनिवार्य है। बजट विश्वसनीयता विश्लेषण ने मोटे तौर पर कुछ क्षेत्रों में भिन्नताओं को छोड़कर, मूल्य 1 के साथ एक आदर्श राजकोषीय परिनिर्धारण का प्रकटीकरण किया। 'राजकोषीय नियमों' के भीतर, सरकारों के उप-राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अनुकूलन के लिए विवेकाधीन राजकोषीय स्थान का एक समग्र विश्लेषण किया जाता है, जिसमें कुछ राज्यों में गैर-विकासात्मक व्यय 40 प्रतिशत के सीमा अनुपात को पार कर जाता है।

2. आंध्र प्रदेश राज्य में राजस्वों पर जीएसटी प्रतिकर की वापसी का प्रभाव, जनवरी-मई 2022

प्रायोजक: वाणिज्यिक कर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना, दिनेश कुमार नायक, भाबेश हजारिका और श्री हरी नायडु ए.

उद्देश्य: यह अध्ययन आंध्र प्रदेश राज्य के राजस्व पर जीएसटी प्रतिकर की वापसी के संभावित प्रभावों का समग्र मूल्यांकन करता है। यह जून 2022 से आगे जीएसटी प्रतिकर को जारी रखने के संभावित डिजाइनों पर भी प्रकाश डालता है, जिससे राज्य के वित्त पर प्रभाव की गंभीरता और केंद्र पर बोझ को कम

करने के साथ-साथ विशेष रूप से आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखते हुए दर को तर्कसंगत बनाया जा सकता है।

3. प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) डिजाइन रूपरेखा, उभरते पैटर्न और सरकार के लिए लागत, नवम्बर 2022

प्रायोजक: राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए)

दल: मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता

उद्देश्य: यह पत्र पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल होने, दावों और राज्य-विशिष्ट मॉडलों पर उभरते साक्ष्यों का पूरक है। यह सार्वजनिक-निजी जुड़ाव के विभिन्न राज्य-विशिष्ट मॉडलों पर भी प्रकाश डालता है जो पीएमजेएवाई के मूल छत्रक मॉडल के अंतर्गत उजागर हुए हैं।

4. उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी की तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा जुलाई 2022 - जनवरी 2023

प्रायोजक: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

दल: आर. कविता राव, सुकन्या बोस और गौरव

उद्देश्य: भारत सरकार के अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थाओं (एचईआई) में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए वित्त-पोषण में पर्याप्त वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ 2017-18 में उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना की गई थी। एचईएफए का घोषित मिशन भारत की शैक्षणिक संस्थाओं में पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर समय पर वित्त प्रदान करना है और इसे कॉरपोरेट्स से सीएसआर फंड और अन्य लोगों से दान के माध्यम से अनुदान के साथ पूरक करना है। स्वतंत्र मूल्यांकन के उद्देश्य त्रिआयामी हैं: क) एचईएफए के घोषित उद्देश्यों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का आकलन करना; ख) अल्पउपलब्धि के कारणों का विश्लेषण करना; और ग) अधिदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के साथ-साथ उत्पाद परिवर्तन शुरू करने के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों की सिफारिश करना। मूल्यांकन रिपोर्ट केंद्र द्वारा वित्त-पोषित एचईआई से एकत्र किए गए प्राथमिक डेटा पर आधारित है।

5. पंडित दीन दयाल उपाध्याय लोक प्रशासन प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड सरकार, देहरादून को अनुसंधान और परामर्श सहयोग, अगस्त 2021 – जुलाई 2022

प्रायोजक: उत्तराखंड सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना, दिनेश नायक और भाबेश हजारिका

उद्देश्य: तैयार की जाने वाली लोक वित्त प्रबंधन प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल। इनमे शामिल हैं:

- पीएफएम के तहत प्रमुख संवैधानिक उपबंध, अधिनियम और नियम
- मध्यम अवधि की राजकोषीय रूपरेखा
- बजट निष्पादन और प्रतिबद्धता
- सार्वजनिक निवेश प्रबंधन
- नकदी और ऋण प्रबंधन

6. सिक्किम के लिए मध्यम अवधि राजकोषीय याजना: 2022-23 से 2024-25, अप्रैल-मई 2022

प्रायोजक: सिक्किम सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना

उद्देश्य: रिपोर्ट में वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए सिक्किम सरकार के लिए मध्यम अवधि की वित्तीय योजना (एमटीएफपी) प्रस्तुत की गई। एमटीएफपी 2022-23 आगामी बजट वर्ष और दो आगामी वर्षों में राजकोषीय नीति उद्देश्य और अनुमानित राजकोषीय लक्ष्य प्रदान करता है। यह रिपोर्ट मौजूदा वृहत-राजकोषीय माहौल के आधार पर और सिक्किम में एफआरबीएम अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। रिपोर्ट में एफआरबीएम अधिनियम की शर्तों के अनुरूप बजट वर्ष सहित तीन वर्षों के लिए राजकोषीय व्युत्पन्नों का अनुमान लगाया गया है।

7. वर्ष 2019-20 के लिए राज्य एफआरबीएम अधिनियम के सिक्किम सरकार द्वारा अनुपालन की समीक्षा, जनवरी-मई 2022

प्रायोजक: सिक्किम सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह

उद्देश्य: रिपोर्ट का उद्देश्य सामान्य रूप से राज्य के वित्त और विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों का निवारण करना है;

क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन। इनमें घाटे, ऋण और अधिनियम में निर्दिष्ट अन्य राजकोषीय व्युत्पन्नों से संबंधित राजकोषीय लक्ष्य शामिल हैं।

ख) व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन। एफआरबीएम अधिनियम राज्य को अपने एमटीएफपी के साथ एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करने के लिए कहता है।

ग) राजस्व प्रयास, केंद्रीय हस्तांतरण, व्यय पैटर्न और ऋण प्रबंधन के संदर्भ में राज्य के वित्त का आकलन।

8. पांडिचेरी के जीएसडीपी के अनुमान के स्रोत और पद्यतियां: त्रितीय पक्षकार आकलन, अप्रैल-दिसंबर 2022

प्रायोजक: पांडिचेरी सरकार

दल: अमेय सप्रे और वैशाली भारद्वाज

उद्देश्य: यह अध्ययन राष्ट्रीय लेखाओं की 2011-12 आधार वर्ष श्रृंखला के अनुसार पुदुचेरी के जीएसडीपी को संकलित करने के स्रोतों और तरीकों का मूल्यांकन करता है और गुणवत्ता सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

9. राष्ट्रीय अनुकूलन संचार - पर्यावन, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, जून 2022

प्रायोजक: कोई वित्त-पोषण नहीं - परामर्श

दल: अजय नारायण झा, लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर

उद्देश्य: एनआईपीएफपी अध्ययन ने एमओईएफसीसी, भारत सरकार के लिए भारत में अनुकूलन के वित्त-पोषण का विश्लेषण किया। अध्ययन में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन तंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए खर्च की कुल राशि की जांच की गई।

वित्त मंत्रालय के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप

1. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शिता लेखापरीक्षा, 1 जून - 31 दिसम्बर 2022

प्रायोजक: केन्द्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट

दल: सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला

उद्देश्य: आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को उपधारा (1)(ख) के अधीन सूचीबद्ध प्रकृति की जानकारी का स्वत: प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। विभागों से भी अपेक्षा की जाती हैं कि वे उस जानकारी का विश्लेषण करें जो आरटीआई आवेदकों द्वारा सबसे अधिक बार मांगी जाती है और उसका स्वत: प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर करें। इस उपबंध के अनुसरण में, डीओपीटी ने आगे निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से हर साल अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज की तीसरे पक्षकार द्वारा लेखापरीक्षा कराई जानी चाहिए और इसके निष्कर्ष मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) को प्रस्तुत करने चाहिए। एनआईपीएफपी को सीआईसी द्वारा राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों की तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा करने का काम सौंपा गया है। अब तक, एनआईपीएफपी ने 2019-20 के लिए कार्य पूरा कर लिया है, और चूंकि यह एक कार्य हैं, एनआईपीएफपी आने वाले वर्षों के लिए इस दिशा में अपना कार्य जारी रखेगा। एनआईपीएफपी ने बिना किसी अतिरिक्त भुगतान/शुल्क आदि के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में इस कार्य का निष्पादन किया है।

2. भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी नियमावली (आईपीएफएस) की तैयारी, जुलाई 2022

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: अमरनाथ एच.के., श्री हरी नायडू ए. और रोहित दत्ता

उद्देश्य: भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी के संकलन के लिए टेम्पलेट्स के साथ एक नियमावली तैयार की गई है। राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण, राज्य के बजट को केंद्रीय समर्थन, कर संरचना (जीएसटी की शुरूआत) और योजनाओं को बंद करने में हाल के बदलावों को देखते हुए, आईपीएफएस की सामग्री में बदलाव की आवश्यकता है। कुछ धाराओं को हटाए जाने करने की जरूरत है जबकि कुछ को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। अध्ययन उन अध्यायों/अनुभागों/तालिकाओं की जांच करेगा जिन्हें समाप्त किया जा सकता है; जहां हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी शामिल करने की आवश्यकता है तथा मौजूदा तालिका प्रारूपों में जोड़ने या हटाने का सुझाव दिया जाएगा और एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और दो वर्षों के लिए डेटा भरा जाएगा।

3. वित्तीय आस्तियों से आय का कराधान, 1 अगस्त - 26 दिसंबर 2022

प्रायोजक: सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

दल: सुप्रियो डे, प्राची जैन, आदम हुसैन, नीति गुप्ता और आलोकिता बासु

उद्देश्य: यह रिपोर्ट प्रत्यक्ष कर प्रणाली में वित्तीय संपत्तियों के कराधान की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अपेक्षा के आधार पर तैयार की गई थी। रिपोर्ट का आशय उपबंधों के एक जटिल सेट का पता लगाने और मुख्य आर्थिक और नीतिगत सबक प्राप्त करने के लिए डेटा विश्लेषण और कर की उदाहरणात्मक गणना का उपयोग करना है। मोटे तौर पर, रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए वर्तमान कर व्यवस्था जटिल है, यह इक्विटी पर ऋण को

अनुचित रूप से बढ़ावा देती है, इसमें कई विकृतियाँ हैं, दरों की बहुलता है और निवासियों और गैर-निवासियों के लिए अलग-अलग उपबंध हैं। रिपोर्ट कुछ नीतिगत उपचार प्रदान करती है जैसे: (क) गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत उपबंध, (ख) लाभांश कटौती प्रणाली के आधार पर कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर का आंशिक एकीकरण, (ग़) पूंजीगत लाभ के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए प्रतिधारण अवधि का संरेखण, (घ) प्रतिभूति लेनदेन कर उपबंधों को हटाना, और (ड.) लाभांश, इक्विटी परिसंपत्तियों की बिक्री और बायबैक कर दर के बीच कर समानता, विशेष रूप से धारा 115थक को हटाना।

4. क्रिप्टोकरेंसी पर दस्तावेज/रिपोर्टें/टिप्पणियां, अप्रैल - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: ये दस्तावेज़ सीएंडसी प्रभाग को अनुसंधान सहायता के संबंध में डीईए और एनआईपीएफपी के बीच समझौते के ज्ञापन की मद 2.11 के अनुसार तैयार किए गए थे। निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार किए गए:

- क्रिप्टो यूनिवर्स (स्टेबलकॉइन्स सहित) से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग निकायों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर हाल के प्रकाशनों से मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया।
- जी-20 देशों की क्रिप्टोकरेंसी विनियामक स्थिति का अवलोकन।
- हाल के प्रमुख विनियामक विकास (जैसे क्रिप्टो-एसेट्स में बाजार, या यूरोपीय संघ में एमआईसीए) और ब्राजील जैसे कुछ देशों द्वारा लाए गए हालिया विनियम।
- 'क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी विवाक्षाएं' (जैसे नेटवर्क प्रभाव, व्यापक आर्थिक विवक्षाएं, जलवायु ऊर्जा विवक्षाएं और अन्य विवक्षाएं आदि) पर विश्लेषण के लिए शोध पत्रों और प्रत्येक के संक्षिप्त विवरण का संकलन।
- जनवरी 2023 में आयोजित आईएमएफ फोकस समूह की बैठक के संबंध में दो टिप्पणियां तैयार की गईं थीं। पहली में बैठक से उभरे चर्चा बिंदुओं का सारांश था। दूसरी टिप्पणी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा क्रिप्टो एसेट्स (2023) के मैक्रोफाइनेंशियल इम्प्लीकेशन्स पर परिणामी जी-20 नोट से मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

5. यू.एस. बैंक विफलता और क्रिप्टो अंगीकरण पर टिप्पणी, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे और डीईए दल

सारांश: यह टिप्पणी 23 मार्च 2023 को प्राप्त एक कार्य अनुरोध के अनुसार और डीईए के सीएंडसी प्रभाग को अनुसंधान सहायता के संबंध में थी। इस टिप्पणी का उद्देश्य मार्च 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अचानक बैंक विफलता और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के अंगीकरण के बीच मध्य विद्यमान संबंध का अध्ययन करना था। मामला अध्ययन की मदद से, टिप्पणी ने कुछ विफल बैंकों की ऋण देने की प्रथाओं और इन बैंकों पर क्रिप्टो परिसंपत्ति की कीमतों में गिरावट के प्रभाव की जांच की। टिप्पणी में अध्ययन किए गए बैंक विफलता के दो मामले सिग्नेचर बैंक और सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन के थे। इसके अतिरिक्त, टिप्पणी ने बैंकिंग संगठनों के लिए क्रिप्टो-परिसंपत्ति से संबंधित जोखिमों पर अमेरिकी विनियामकों के रुख और क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए बैंकों के जोखिम के विवेकपूर्ण उपचार पर प्रकाश डाला।

टिप्पणी में तीन प्रमुख सीखों को रेखांकित किया गया। सबसे पहले, क्रिप्टो-पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समग्र रूप से उपभोक्ता भावनाएं और आवश्यक नहीं कि संबंधित बैंक, क्रिप्टो-अनुकूल बैंकों की जमा राशि की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप बैंक के बारे में विश्वास कम होने का एक दुष्चक्र आरंभ हो सकता है और अफरातफरी मच सकती है। दूसरे, क्रिप्टो-क्षेत्र के साथ उच्च स्तर का अंतर्संबंध बैंकों के लिए महत्वपूर्ण तरलता और एकाग्रता जोखिमों के लिए उजागर करता है, जिसे अमेरिकी वित्तीय विनियामकों ने भी उजागर किया है। अंत में, इन बैंकों की विफलता के लिए क्रिप्टो-एक्सपोज़र को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एक प्रतिकूल व्यापक आर्थिक परिवेश (अर्थात बढ़ती ब्याज दरें), अपर्याप्त ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के साथ मिलकर बैंक की निरंतर, बड़े पैमाने पर निकासी को झेलने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

6. एनआईपीएफपी में 'क्रिप्टो चुनौती का मार्गनिर्देशन : भारत और जी-20' पर पैनल चर्चा, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: एनआईपीएफपी ने डीईए और एनआईपीएफपी के मध्य समझौता ज्ञापन में मद 2.11 के अनुसार, सीएंडसी प्रभाग से प्राप्त कार्य अनुरोध पर 23 जनवरी 2023 को 'क्रिप्टो चैलेंज का मार्गनिर्देशन करने के लिए नीतिगत ढांचा' पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। पैनल चर्चा में निम्नलिखित व्यापक विषयों पर चर्चा के माध्यम से क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर अनुसंधान संगठनों और निजी क्षेत्र के हितधारकों के परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास किया गया:

- क्रिप्टो संपत्तियों को अपनाने में हालिया रुझान।
- क्रिप्टो अपनाने के वर्तमान और भविष्य के चालक।
- देश में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रमुख निवेश समूहों की पहचान करना।
- एफटीएक्स जैसी हालिया घटनाओं के बाद निवेशकों के व्यवहार में संभावित बदलाव।
- भारत और अन्य देशों में क्रिप्टो के वर्तमान उपयोग के मामलों के साथ-साथ विशेष उपयोग के मामले जिन्हें केवल क्रिप्टो ही पूरा कर सकता है।
- भारत में क्रिप्टो अपनाने पर देश-विशिष्ट नीतियों का सीमा पार प्रभाव।
- भारत में क्रिप्टो-संबंधित डेटा की उपलब्धता और स्रोत।
- वर्तमान क्रिप्टो नियमों की सीमाएं।
- क्रिप्टो परिसंपत्ति पारिस्थितिकी-तंत्र की वर्तमान स्थिति से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक बाह्यताएं, जिनमें व्यापक आर्थिक चिंताएं (जैसे वित्तीय स्थिरता), उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दे और जलवायु परिवर्तन की विवाक्षाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- भारत में विभिन्न हितधारकों के विनियमन से संबंधित चिंताएँ।
- भारत में क्रिप्टो पारिस्थितिकी-तंत्र की रोजगार संबंधी विवक्षाएं।
- भावी मार्ग : एक व्यापक विनियामक ढांचे की रूपरेखा।

7. भारत में बैंककारी क्षेत्र के आकार और आकार में वृद्धि करने के उपायों पर टिप्पणी, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे और डीईए देल

उद्धरण: टिप्पणी का उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र के आकार का अध्ययन करना है और यह जानना है कि क्या बैंकिंग क्षेत्र के आकार में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश है। पत्र में पाया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के सामने आने वाले संभावित क्रेडिट अंतर को पूरा करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के आकार को बढ़ाने की गुंजाइश है। बढ़ती गैर-वित्तीय क्षेत्र की ऋण मांग को पूरा करने के लिए भी बैंकों की आवश्यकता है। इसके बाद टिप्पणी बैंकिंग क्षेत्र के आकार का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वीकार्य मानदंडों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करती है। बैंकों की कुल संपत्ति और जीडीपी अनुपात, बैंकों का कुल राजस्व और जीडीपी अनुपात, प्रति 100,000 व्यक्तियों पर शाखाओं की संख्या, क्रेडिट-से-जीडीपी अनुपात बैंकिंग क्षेत्र के आकार का आकलन करने के लिए कुछ संकेतक हैं। जबकि बैंकिंग क्षेत्र के आकार का कई संकेतकों के लेंस के माध्यम से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, टिप्पणी से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय तुलना की सुविधा के लिए और बैंकिंग क्षेत्र के आकार को नीतिगत परिवेश से जोड़ने के लिए, बैंकों का क्रेडिट-जीडीपी अनुपात एक उचित उपाय प्रतीत होता है।

टिप्पणी ब्रिक्स, दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं तथा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए बैंकों के क्रेडिट-जीडीपी अनुपात के प्रक्षेपपथ की तुलना प्रस्तुत करती है। टिप्पणी अंततः विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है जिसके तहत एमएसएमई और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के क्रेडिट अंतर को संबोधित किया जा सकता है।

8. भारत के लिए वित्तीय तनाव संकेतकों पर टिप्पणी, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे एंड डीईए दल

उद्देश्य: टिप्पणी उन व्युत्पन्नों की चर्चा प्रस्तुत करती है जो वित्तीय प्रणाली में तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और वित्तीय तनाव सूचकांक के निर्माण के लिए एक पद्धति पर चर्चा करती है। भारत के लिए वित्तीय तनाव सूचकांक का निर्माण वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मुद्रा बाजार, इक्विटी बाजार, बांड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र से डेटा लेकर किया जाता है। व्युत्पन्न का चयन वित्तीय तनाव सूचकांक पर साहित्य के अवलोकन और सार्वजनिक डोमेन में उच्च आवृत्ति डेटा की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्रेडिट जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख संकेतकों में मुद्रा बाजार में प्रसार और सरकारी बांड बाजार में प्रसार (उपज वक्र की स्थिरता या सपाटता) शामिल हैं। इसके उपरांत टिप्पणी इक्विटी बाजार में ओवरवैल्यूएशन और अस्थिरता और बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्रों और विदेशी मुद्रा बाजार में उत्तोलन और तनाव को पकड़ने के लिए संकेतकों की चर्चा प्रस्तुत करती है।

9. भारत में कुटुंब देयताएं : विहंगावलोकन, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: बढ़ती घरेलू ऋणग्रस्तता (विशेष रूप से कोविड अवधि के दौरान और उसके बाद) का एक अनुभवजन्य अध्ययन, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव और साथ ही क्या "ऋणग्रस्त मांग" सिद्धांत भारत के मामले में सच है। तैयार की गई टिप्पणी में यह समझने का प्रयास किया गया है कि क्या भारत के मामले में बढ़ते घरेलू ऋण की घटना दिखाई दे रही है और घरेलू तुलन-पत्र की स्थिति को समझाने वाले अनेक संकेतकों के माध्यम से इसका आकलन करने का प्रयास किया गया है। टिप्पणी को ऋणग्रस्त मांग सिद्धांत की चर्चा, घरेलू तुलन-पत्र की संरचना पर विस्तृत विवरण, व्यक्तिगत ऋण पर रुझान और उनकी संरचना तथा ग्रामीण, शहरी और महानगरीय परिवारों के ऋण प्रोफ़ाइल पर अंतर्दृष्टि को शामिल करने के लिए संरचित किया गया है।

10. एआईआईबी का ऊर्जा क्षेत्र इंगेजमेंट : तकनीकी सहायता और निजी पूंजी संघटन पर सूक्ष्म दृष्टि, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: यह टिप्पणी अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं (ओएमआई)/ प्रभागों को अनुसंधान सहायता के संबंध में डीईए और एनआईपीएफपी के बीच समझौता ज्ञापन में मद 2.18 के अनुसरण में थी। टिप्पणी का उद्देश्य भारत के ऊर्जा क्षेत्र में उन्नति का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से तकनीकी सहायता और निजी पूंजी जुटाने (टीए और पीसीएम) के संदर्भ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उनकी सिफारिश करना था। समर्थन में, टिप्पणी ने भारत की वर्तमान कम-कार्बन ऊर्जा संक्रमण आवश्यकताओं के साथ इसके संरेखण की जांच करने के लिए अद्यतन ऊर्जा क्षेत्र रणनीति (2022) के एआईआईबी के मसौदे की समीक्षा की। इसके अलावा, टिप्पणी के आधार पर एआईआईबी की 2022 मसौदा ऊर्जा रणनीति, टीए और पीसीएम पर संप्रभु सदस्यों के साथ एआईआईबी की परामर्श बैठक के लिए सिफारिशों और टिप्पणियों/बातचीत बिंदुओं का एक सेट तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, मानचित्र के इंटरैक्टिव संस्करण के लिंक के साथ, एआईआईबी-अनुमोदित संप्रभु परियोजनाओं (2016-2022) का एक मानचित्र तैयार किया गया था।

11. जी-20 सहयोग के लिए प्रस्तुतीकरण : वैश्विक ऋण खामियों को प्रबंधित करना, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

दल: राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: यह प्रस्तुति जी20 फाइनेंस ट्रैक के ऋण एजेंडे के भाग के रूप में वैश्विक ऋण खामियों के प्रबंधन पर प्राप्त एक मामला टिप्पणी के अनुसार तैयार की गई थी। प्रस्तुति में चार खंड शामिल थे: ऐतिहासिक संदर्भ; ऋण विश्लेषण; ऋण समाधान उपाय - जी20 सामान्य रूपरेखा; और भावी मार्ग।

सर्वप्रथम, प्रस्तुति ने 1970 के दशक के बाद से हुई चार प्रमुख ऋण लहरों (बढ़ती ऋण अवधि) के संबंध में ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान किया। प्रत्येक ऋण लहर के लिए, प्रभावित देशों, ऋण वृद्धि के कारणों और दी गई अवधि में बढ़ते ऋण स्तर को संबोधित करने के लिए किए गए समाधान उपायों के संबंध में संदर्भ प्रदान किया गया था।

दूसरे, प्रस्तुति में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के विदेशी ऋण के विकास पर शैलीबद्ध तथ्यों पर प्रकाश डाला गया। निम्न और मध्यम आय वाले देशों तथा क्षेत्र, परिपक्वता, ऋणदाता संरचना और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के आधार पर बाहरी ऋण में भिन्नता दिखाने के लिए 1987 से 2021 तक विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी (आईडीएस) डेटा का उपयोग करके बाहरी ऋण विश्लेषण किया गया था। इसके अलावा, प्रस्तुतिकरण में देशों के साथ-साथ मानक निर्धारण निकायों से संबंधित ऋण डेटा रिपोर्टिंग और विश्लेषण के मुद्दों को शामिल करते हुए डेटा विश्लेषण में विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। इसके परिणामस्वरूप, ऋण डेटा पारदर्शिता, सांख्यिकीय रिपोर्टिंग और ऋण स्थिरता विश्लेषण में सुधार के लिए ठोस सिफारिशें प्रदान की गईं। ऐसी एक सिफारिश ने देशों में संभावित ऋण वृद्धि की पहचान करने में मदद के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो ऋण समाधान और राहत के लिए समय पर हस्तक्षेप की अनुमति देगा।

तीसरे, प्रस्तुतीकरण में चाड, जाम्बिया और इथियोपिया के मामलों का अध्ययन करके ऋण उपचार के लिए जी20 साझे ढाँचे का गहन विश्लेषण प्रदान किया गया, जो केवल ऐसे तीन देश थे, जिन्होंने ऋण समाधान

के लिए साझे ढाँचे से संपर्क किया है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कोई अंतिम समाधान नहीं देखा है। साझे ढाँचे और ऋण पुनर्गठन से जुड़ी कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। पहचानी गई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बढ़ती ऋण कमजोरियों के बावजूद, सामान्य ढांचे के तहत मध्यम आय वाले देशों को उपचार से बाहर करना था। इसके फलस्वरूप, साझे ढांचे और ऋण समाधान उपायों को मजबूत करने के लिए हस्तक्षेपों के एक बहु-आयामी सेट की सिफारिश की गई, जिसमें आधिकारिक और निजी दोनों लेनदारों से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं।

अंत में, देशों में ऋण भेद्यता के प्रबंधन के लिए बड़े विषयों के रूप में दो रूपरेखाओं के प्रस्ताव रखे गए। एक आदर्श विधि/ढांचा अर्थात जिम्मेदार ऋण पर वैश्विक समझौता तैयार करने का प्रस्ताव था। इस ढांचे में सरकारों, निजी क्षेत्र और बहुपक्षीय वित्तीय/विकास संस्थानों को पारदर्शी और समान ऋण प्रकटीकरण और प्रबंधन की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए ठोस कार्रवाई एजेंडा (प्रस्तुति में सिफारिशों से प्रेरणा लेते हुए) शामिल होंगे। दूसरा प्रस्ताव वैश्विक वित्तीय अवसरंचना (ऋण और जलवायु-संबंधित सुधार) में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है, जो बढ़ते ऋण संकट और जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए कमजोर विकासशील देशों के लिए दीर्घकालिक और निवारक वित्तपोषण सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह प्रस्ताव बारबाडोस सरकार द्वारा शुरू किए गए 2022 ब्रिजटाउन एजेंडा से प्रेरित था।

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप

1 2022-23 के लिए राज्य वित्त डेटा का अद्यतनीकरण, 15 जनवरी - 1 मई 2022

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: अमरनाथ एच.के., श्री हरी नायडू ए. और रोहित दत्ता

उद्देश्य: बजट और वित्त खातों से राज्य वित्त की जानकारी को अद्यतन करना। हमारे पास 1987-88 से लेकर 2021-22 तक की जानकारी है.

2 राष्ट्रीय लेखाओं की स्थिति और संकलन मुद्दे, जनवरी-अप्रैल 2023

प्रायोजक: EAC-PM

दल: अमेय सप्रे और वैशाली भारद्वाज

उद्देश्य: यह अध्ययन राष्ट्रीय लेखाओं के आँकड़ों को संकलित करने के स्रोतों और तरीकों का स्थिति मूल्यांकन करता है और राष्ट्रीय लेखाओं की 2011-12 श्रृंखला के मुद्दों की रूपरेखा तैयार करता है।

3 ओडिशा में लोक व्यय समीक्षा और बाल संरक्षण मूल्यांकन, अप्रैल 2022 - अप्रैल 2023

प्रायोजक: यूनिसेफ

दल: लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बालामूर्ती बी.

उद्देश्य: अध्ययन का ध्यान-केंद्रण मोटे तौर पर द्विआयामी है: (i) सार्वजनिक व्यय समीक्षा (पीईआर) जिसमें राजकोषीय मार्कशिप और पीईएफए (सार्वजनिक व्यय और वित्तीय उत्तरदायित्व) विश्लेषण शामिल है; और (ii) बाल संरक्षण परिणामों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन (ओईसीडी डीएसी) और राजकोषीय हस्तक्षेपों का अर्थमितीय मॉडलिंग। यह अध्ययन ओडिशा के चयनित जिलों में बाल देखभाल संस्थानों की क्षेत्र-स्तरीय सार्वजनिक व्यय की निगरानी, जवाबदेही और संस्थागत समीक्षा भी प्रदान करता है।

4 ईएसी-पीएम – 2023 भारतीय अर्थव्यवस्था पर तिमाही रिपोर्ट : ईएसी-पीएम के लिए टिप्पणी– वर्ष के दौरान ईएसी-पीएम के लिए चार तिमाही रिपोर्टें पूर्ण की गईं, अप्रैल 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: ईएसी-पीएम

दल: आर. कविता राव, लेखा चक्रवर्ती, सुप्रियो डे, मनीष गुप्ता, रुद्राणी भट्टाचार्य, दिनेश कुमार नायक और राधिका पांडे

उद्देश्य: अर्थव्यवस्था का त्रैमासिक मूल्यांकन और विकास दृष्टिकोण। चार त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं, अर्थात्, (i) अप्रैल-जून 2022, (ii) जुलाई-सितंबर 2022, (iii) अक्टूबर-दिसंबर 2022 और (iv) जनवरी-मार्च 2023.

5 जीएसटी व्यवस्था में रूपांतरण ने भारत में मंहगाई को कैसे प्रभावित किया? नवम्बर 2022 - फरवरी 2023

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: रुद्राणी भट्टाचार्य

उद्देश्य: उन्नत और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर अनुभवजन्य साहित्य मुद्रास्फीति पर जीएसटी व्यवस्था को अपनाने के मिश्रित प्रभाव का सुझाव देता है। यह पत्र भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति और उनके प्रमुख घटकों, अर्थात् भोजन और मुख्य मुद्रास्फीति पर जीएसटी प्रणाली के प्रभावों की जांच करके इस साहित्य में योगदान देता है। एक बहुभिन्नरूपी हस्तक्षेप ढांचे में, अन्य व्यापक आर्थिक झटकों और हस्तक्षेप की अंतर्जात रूप से पहचानी गई अवधि को नियंत्रित करते हुए, हम खुदरा खाद्य कीमतों पर मुद्रास्फीति प्रभाव के माध्यम से भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव पाते हैं।

6 केन्द्रीय सरकार के राजस्वो, व्ययों, घाटों और ऋणों का अनुमान, 1 सितम्बर - 10 अक्तूबर 2022

प्रायोजक: ईएसी-पीएम

दल: सुप्रियो डे, मनीष गुप्ता, आदम हुसैन और साक्षी राठी

उद्देश्य: यह टिप्पणी कुछ वैकल्पिक मान्यताओं और परिदृश्यों का उपयोग करके केंद्र सरकार के राजस्व, व्यय, घाटे और ऋण का अनुमान प्रदान करती है। ये अनुमान या तो (i) अन्य व्युत्पन्नों के कुछ प्रक्षेपपथों को ध्यान में रखते हुए ऋण स्टॉक के विकास भविष्यवाणी कर सकते हैं, या (ii) वांछित ऋण स्टॉक, घाटे के आवश्यक मूल्यों आदि को ध्यान में रखते हुए। इस मामले में पूर्व दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2022-23 के बाद की नाममात्र विकास दर श्रृंखला दो अनुमानों पर आधारित है: आईएमएफ और एनआईपीएफपी पूर्वानुमान। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईएमएफ के अनुमान जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के मामले में निचले स्तर पर जा सकते हैं। इसलिए, हम तुलनित्र के रूप में आतंरिक रूप से किए गए वैकल्पिक प्रक्षेपण का उपयोग करते हैं। ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए अनुमान महत्वपूर्ण हैं और इसलिए वित्त मंत्रालय के लिए उपयोगी हैं।

7 प्रत्यक्ष कर अभियोग प्रबंधन और वैकल्पिक विवाद समाधान, 1 अगस्त - 26 मार्च 2023

प्रायोजक: ईएसी-पीएम

दल: सुप्रियो डे, प्राची जैन, मयूराक्षी मित्रा, नीति गुप्ता और आलोकिता बसु

उद्देश्य: रिपोर्ट प्रत्यक्ष कर अपील और अभियोग प्रणाली की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करती है। यह भारत की वर्तमान विवाद समाधान प्रणाली को प्रस्तुत करती है, विभिन्न विवाद समाधान विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करती है, अन्य देशों के साथ इसकी तुलना करती है और कर विवाद समाधान को बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक नीति विकल्पों के साथ निष्कर्ष निकालती है। मोटे तौर पर, रिपोर्ट में पाया गया है कि सामान्य कर मूल्यांकन और मुकदमेबाजी प्रणाली कर विभाग और करदाता के बीच एक प्रतिकूल विधिक संबंध स्थापित करती है।

8 शिक्षा वित्तपोषण पर कोविड का प्रभाव, अक्तूबर 2021 - जुलाई 2022

प्रायोजक: नेशनल कोइलेशन फॉर एजुकेशन

दल: सुकन्या बोस और हर्षिता शर्मा (नेशनल कोइलेशन फॉर एजुकेशन)

उद्देश्य: कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउन ने भारत में स्कूली शिक्षा के बजट को कैसे प्रभावित किया है? इस मुद्दे का केंद्र सरकार और दो राज्य सरकारों - दिल्ली और बिहार के स्तर पर पता लगाया गया है।

9 असम उप-राष्ट्रीय राजवित्तीय स्थिरता विश्लेषण और राजवित्तीय जोखिम, अप्रैल-जून 2022

प्रायोजक: विश्व बैंक, नई दिल्ली

दल: मनीष गुप्ता और सोनल अग्रवाल

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य असम के लिए मध्यम अवधि की राजकोषीय स्थिरता विश्लेषण करना है। इसमें राज्य की विशिष्ट नीति प्राथमिकताओं और बाधाओं के आधार पर परिदृश्यों का निर्माण शामिल है।

10 एसडीजी के लिए वित्तपोषण में तेजी लाने/उप-राष्ट्रीय सरकारों के लिए एसडीजी के लिए राजकोषीय स्थान बढ़ाने के लिए उप-राष्ट्रीय कार्रवाइयों पर अध्ययन, सितम्बर-नवम्बर 2022

प्रायोजक: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

दल: सुरांजलि टंडन और अर्चिता श्रीधर

उद्देश्य:

- राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का उच्च-स्तरीय विश्लेषण राज्य वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट पर आधारित है।
- योजना, संसाधन जुटाना, आवंटन और ट्रैकिंग सहित संसाधन के प्रत्येक चरण के लिए एसडीजी वित्तपोषण पहल पर सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरणों पर प्रकाश डालना, जिनका उपयोग सरकारी वित्त के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए मामला बनाने के लिए किया जा सकता है।
- सर्वोत्तम प्रथाओं के किसी भी वैश्विक उदाहरण की पहचान करना जिसे उप-राष्ट्रीय स्तर पर दोहराया जा सकता है।
- एसडीजी वित्तपोषण पर राज्य सरकारों की जरूरतों की पहचान करना, जिसमें एसडीजी-आधारित बजट समर्थन, टैगिंग तंत्र, अभिनव/मिश्रित वित्तपोषण मॉडल आदि शामिल हैं।
- राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध लीवर का मूल्यांकन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को आधार बनाता है और एसडीजी के लिए बढ़े हुए राजकोषीय स्थान के लिए मार्गों की रूपरेखा तैयार करता है।

11 सीजीटीएमएसई के लिए गारंटी योजनाओं हेतु डेटा विश्लेषण, मई 2022

प्रायोजक: सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)

दल: रेणुका साने, अनन्या गोयल और मिथिला ए. साराह

उद्देश्य:

- सीमा, अर्थमिति, आर्थिक और नीति अनुसंधान सहित डेटा संग्रह और विश्लेषण
- डेटा यूनिवर्स परिभाषा
- डेटा विश्लेषण
- नीति समीक्षा, रिपोर्टिंग और शासन

12 भारत में वित्तीय समावेशन के लिए जीआरएम (शिकायत निवारण तंत्र) का आधारभूत अध्ययन, 1 नवम्बर 2021 - सितम्बर 2022

प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

दल: रेणुका साने, सृष्टि शर्मा, ऐश्वर्या गवली और स्मृति परशीरा

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य है:

- वित्तीय शिकायत का सामना करने पर कुटुंब क्या करते हैं - क्या वे जानते हैं कि इस शिकायत का समाधान कैसे किया जा सकता है और क्या वित्तीय संस्थाओं और विनियामकों द्वारा स्थापित जीआरएम तंत्र से संपर्क करने पर उन्हें संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।
- वित्तीय बाजारों में भागीदारी पर परिवारों के निर्णय लेने पर इन जीआरएम का प्रभाव और इस परिकल्पना का परीक्षण करना कि क्या औपचारिक वित्तीय उत्पादों के साथ पिछली शिकायतें भौतिक संपत्तियों में अतिरिक्त प्रवाह से संबंधित हो सकती हैं।
- परिवारों की प्रतिक्रियाओं में अंतर का उनकी विशेषताओं के आधार पर मूल्यांकन करना - क्या उच्च आय वाले लोग निम्न आय वाले परिवारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्या निर्धनों को असंगत कल्याण हानि का सामना करना पड़ता है, क्या उनकी प्रतिक्रियाएँ जोखिम उठाने की क्षमता और समय की प्राथमिकता की दरों के आधार पर भिन्न होती हैं। इसमें परिवारों की 'जोखिम प्राथमिकताएं' और 'समय प्राथमिकताएं' का मापन शामिल होगा। 'सर्वाधिक निर्धन लोगों' और महिलाओं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल हैं, के अनुभवों पर विशेष बल प्रदान किया जाएगा, जिनके पास आमतौर पर कम एजेंसी होने की संभावना है।

13 वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकारों के डेटा बैंक, वित्त को अद्यतन बनाना, November 2022

प्रायोजक: स्व-आरंभित

दल: अमरनाथ एच.के. और रोहित दता

उद्देश्य: वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी के वित्त खातों से राज्य वित्त डेटा के अनुसार डेटाबैंक को अद्यतन किया गया और अनुसंधान गतिविधियों के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय को भारतीय सार्वजनिक वित्त आँकड़े तैयार करने के लिए भी लाभान्वित किया गया है।

चल रहे अध्ययन

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए चल रहे अध्ययन

1. चयनित राज्यों में स्पष्ट आर्थिक सहायताओं का प्राक्कलन, जुलाई 2022 - मार्च 2023

प्रायोजक: नीति आयोग

दल: अमरनाथ एच.के., श्री हरी नायडू ए., मिताली गुरदत्त, किशन, आशीष राज और रोहित दत्ता

उद्देश्य: अध्ययन में उप-राष्ट्रीय स्तर पर व्यय वर्गीकरण के अनुसार स्पष्ट आर्थिक सहायता की मात्रा और परिमाण का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। अध्ययन में वर्ष 2017-18 से 2022-23 (बीई) के लिए छह राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया।

2. वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए मध्य प्रदेश एफआरबीएम के उपबंधों के अनुपालन की द्वि-वार्षिक समीक्षा, फरवरी 2022 - जुलाई 2023

प्रायोजक: मध्य प्रदेश सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे

उद्देश्य: यह मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य के वित्त की एक स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया और राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुपालन के भाग के रूप में तैयार और प्रस्तुत की जाती है। मूल्यांकन रिपोर्ट इन दो वर्षों के लिए राजकोषीय प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख निष्कर्षों और पाठों का सारांश प्रस्तुत करेगी। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लक्ष्यों के राज्य के अनुपालन का प्रकटीकरण करने के अलावा, रिपोर्ट राजकोषीय प्रबंधन की व्यापक प्रवृत्ति का आकलन करेगी। बजटीय योजनाओं को लागू करने की सरकार की क्षमता का आकलन करने के लिए परिणामों को ध्यान में रखते हुए राजस्व और व्यय से संबंधित बजटीय अनुमानों का विश्लेषण किया जाएगा।

3. वर्ष 2020-21 के लिए राज्य एफआरबीएम अधिनियम की सिक्किम सरकार द्वारा अनुपालन की समीक्षा, जनवरी 2022 - मई 2023

प्रायोजक: सिक्किम सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे

उद्देश्य: रिपोर्ट का उद्देश्य सामान्य रूप से राज्य के वित्त और विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करना है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 राज्य सरकार के लिए काफी चुनौतियां लेकर आया। हालांकि राजस्व वृद्धि धीमी रही, व्यय का दबाव बना रहा। बजट अनुमान की तुलना में 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों में कमी के मामले में कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक वित्त में गंभीर विकृतियाँ उत्पन्न कर दीं। लॉकडाउन अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण राज्य के कर प्रयास को नुकसान हुआ। 2020-21 में राजकोषीय प्रबंधन और एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन का आकलन राजकोषीय समेकन प्रक्रिया में वापस जाने के लिए राज्य सरकार की अंतर्निहित ताकत का विश्लेषण करने पर केंद्रित होगा।

4. लोक वित्त प्रबंधन और स्थानीय सरकारी वित्त पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, जुलाई 2021 - जुलाई 2023

प्रायोजक: पंडित दीन दयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (पीडीयू-सीटीआरएफए), उत्तराखंड सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना और मनीष गुप्ता

उद्देश्य: परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय सरकारी वित्त पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना शामिल है।

5. नीतिगत ढाँचे का विकास और भारत में किगाली संशोधन के कार्यान्वयन के लिए रणनीति, 6 सितम्बर 2022 - 20 जुलाई 2023

प्रायोजक: ओजोन प्रकोष्ठ, एमओईएफएंडसीसी

दल: सुरांजली टंडन, अर्चित श्रीधर, रिद्धि वर्मा और ज्योत्स्ना चिकारा

उद्देश्य: ओजोन प्रकोष्ठ, एमओईएफएंडसीसी और एनआईपीएफपी भारत में किगाली संशोधन के कार्यान्वयन की रणनीति सहित एक राष्ट्रीय नीति ढांचे के विकास से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे। असाइनमेंट का उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के अंतर्गत अनुपालन दायित्वों और ओडीएस (ओजोन-क्षयकारी) के लिए भारत के देश कार्यक्रम में निहित सिद्धांतों पर विचार करते हुए एचएफसी (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन) को चरण-दर-चरण लागू करने के लिए एक नीतिगत ढांचा और रणनीति विकसित करना है जिसमें औद्योगिक और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उपभोक्ता और सार्वजनिक हितों की रक्षा किए बिना, पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

6. एमओएचयूए-एनआईपीएफपी अनुसंधान कार्यक्रम, नवम्बर 2022 (3 वर्ष की अवधि के लिए)

प्रायोजक: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

दल: आर. कविता राव, मनीष गुप्ता, अमेय सप्रे, आकाश गुप्ता, नीति गुप्ता, सिराज येजदानी और सौम्या अग्रवाल

उद्देश्य: कार्यक्रम में भारत में शहरी वित्तपोषण और सेवा वितरण में अनुसंधान करने और नवाचारों का भंडार बनाने के लिए शहरी सार्वजनिक वित्त अनुसंधान केंद्र (सीईआरयूपीएफ) की स्थापना करना शामिल है।

7. भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक के अनुरक्षण के लिए नीति तैयार करने में समर्थ होने के लिए इनपुट प्रदान करना, अक्टूबर 2021 - अक्टूबर 2022

प्रायोजक: केन्द्रीय कार्यशाला आधुनिकीकरण संगठन (रेल)

दल: रेणुका साने, मार्गी पांड्या, नैन्सी गुप्ता और अमृता पिल्लई

उद्देश्य: अध्ययन रोलिंग स्टॉक में निजी निवेश के मामले में आवश्यक विनियामक व्यवस्था, विधिक अनुपालन और क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें शामिल होंगे:

I. रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के संबंध में भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान प्रथाओं और विनियामक अनुपालन पर नीति पत्र।

II. प्रमुख देशों में माल ढुलाई प्रचालकों द्वारा अपनाई जाने वाली रखरखाव प्रणालियों और विनियामक संरचनाओं के विश्लेषण पर पत्र।

III. माल ढुलाई रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के दौरान जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रबंधन और दायित्व के दायरे पर नीति पत्र।

IV. यात्री रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के दौरान जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रबंधन और दायित्व के दायरे पर नीति पत्र।

V. प्रमुख देशों में यात्री प्रचालकों द्वारा अपनाई जाने वाली रखरखाव प्रणालियों और विनियामक संरचनाओं के विश्लेषण पर पत्र।

VI. भारतीय रेलवे कोचों और वैगनों में दोषों के मात्रात्मक विश्लेषण पर पत्र।

VII. इन क्रियाकलापों में निजी संस्थाओं की भागीदारी पर विचार करते हुए भारत में माल ढुलाई स्टॉक के रखरखाव के लिए विनियामक ढांचे पर नीति पत्र।

VIII. इन क्रियाकलापों में निजी संस्थाओं की भागीदारी पर विचार करते हुए भारत में यात्री रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के आसपास विनियामक ढांचे पर नीति पत्र।

वित्त मंत्रालय के लिए चल रहे अध्ययन

1 वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए भारत सरकार का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण (ईएफसी) बजट, 1 अक्तूबर 2022 से 1 अक्तूबर 2023 के अंत तक

प्रायोजक: वित्त मंत्रालय

दल: अमरनाथ एच.के., श्री हरी नायडू इ., आशीष राज और रोहित दत्ता

उद्देश्य: वर्ष 2017-18 से 2022-23 (बीई) के लिए भारत सरकार के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण (ईएफसी) बजट के लिए टेम्पलेट और नियमावली का संशोधन।

2 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शिता लेखापरीक्षा, जून 2023, पूर्ण होने की संभावित तारीख दिसंबर 2023

प्रायोजक: केन्द्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट

दल: सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला

उद्देश्य: आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को उप-धारा (1)(ख) के अधीन सूचीबद्ध प्रकृति की जानकारी का स्वत: प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। विभागों को उस जानकारी का विश्लेषण करने की भी आवश्यकता होती है जो आरटीआई आवेदकों द्वारा सबसे अधिक बार मांगी जाती है और इसे अपनी वेबसाइट पर स्वत: प्रकटीकरण के रूप में प्रदान किया जाता है। इस उपबंध के अनुसरण में, डीओपीटी ने आगे निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से हर साल अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज का तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा करवाई जानी चाहिए और इसका निष्कर्ष मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) को प्रस्तुत करना चाहिए। एनआईपीएफपी को सीआईसी द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों की तीसरे पक्षकार द्वारा लेखापरीक्षा करने का काम सौंपा गया है। अब तक, एनआईपीएफपी ने 2019-20 के लिए कार्य पूरा कर लिया है, और चूंकि यह एक वार्षिक मामला होगा, एनआईपीएफपी आने वाले वर्षों के लिए इस कार्य को जारी रखेगा।

एनआईपीएफपी ने बिना किसी अतिरिक्त भुगतान/शुल्क आदि के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य किया है।

3 राज्य के अपने राजस्वो और अपने गैर-कर राजस्वों पर राज्य-स्तरीय विश्लेषण, अप्रैल 2022 में आरम्भ

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: दिनेश कुमार नायक और भाबेश हजारिका

उद्देश्य: इस राज्य-स्तरीय अध्ययन का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों में उनके अपने कर राजस्वों और अपने गैर-कर राजस्वों के रुझान और पैटर्न का विश्लेषण करना है। अध्ययन में राजस्व के प्रमुख स्रोतों और राज्यों के समग्र राजस्व में उनके योगदान की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है। इस अध्ययन के निष्कर्षों से राज्यों के नीति-निर्माताओं और हितधारकों को राज्यों की राजस्व संरचना को बेहतर ढंग से समझने, राजस्व सृजन और आवंटन के संबंध में सूचित निर्णय लेने और अंततः राज्यों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलेगी।

4 एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम, अप्रैल 2022 में प्रारंभ, समाप्ति की संभावित तारीख मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशिम कपूर, रितिका सिंह, सिमरन कौर, उत्सव सक्सेना, कृति वट्टल, राम्या आर. कुमार और आनंदिता गुप्ता

उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य संप्रभु क्रेडिट रेटिंग, सार्वजनिक वित्त संबंधी अनुसंधान सहित वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्र के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधान, वित्तीय बाजारों से संबंधित अनुसंधान से संबंधित मुद्दों पर विभाग को अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना है जिसमें राजस्व, व्यय, राज्यों को हस्तांतरण, भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी की परियोजना, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामले, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) मामले, मुद्रा से संबंधित मामले अर्थात, उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की मांग, स्मारक मुद्रा नोटों का महत्व, बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की मजबूती, वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्र की स्थापना पर स्थापना-संबंधी पहलुओं के लिए अनुसंधान सहायता, एमडीबी के प्रभाव का आकलन, जलवायु वित्तपोषण, एमडीबी की ऊर्जा रणनीतियां और एएफडीबी (अफ्रीकी विकास बैंक) समूह में भारत के शामिल होने पर अध्ययन (एएफडीबी/) एडीएफ), कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) और पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक (ईबीआरडी) शामिल हैं।

5 क्रिप्टोकरेंसी पर मासिक रिपोर्टें, अप्रैल 2022 - मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: सिक्का और मुद्रा (सीएंडसी) प्रभाग के अनुसंधान समर्थन के संबंध में रिपोर्ट डीईए और एनआईपीएफपी के बीच समझौता ज्ञापन में मद 2.11 के अनुसार हैं। मासिक रिपोर्ट निम्नलिखित सहित क्रिप्टो क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास का पता लगाती है:

- बाजार विकास (व्यापक बाजार विकास और क्रिप्टोकरेंसी में मूल्य संचलनों के हालिया एपिसोड)।
- रिपोर्ट और चर्चाएँ (मानक-सेटिंग निकायों और अन्य प्लेटफार्मों द्वारा प्रकाशन)।
- न्यायक्षेत्रों में हाल के घटनाक्रम।
- कोई अन्य अपडेट।

रिपोर्ट में सीबीडीसी और क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी-तंत्र में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दों की चल रही शब्दावली के साथ एक अनुबंध भी शामिल है।

6 क्रिप्टोकरेंसी के लिए डैशबोर्ड, अप्रैल 2022 - मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: क्रिप्टोकरेंसी के लिए डैशबोर्ड क्रिप्टो यूनिवर्स के संबंध में प्रमुख बाजार संचलनों, रिपोर्टों और चर्चाओं और न्यायक्षेत्रों में विनियामक विकास का अवलोकन प्रदान करता है। डैशबोर्ड को हर महीने अपडेट किया जाता है, और इसमें शामिल जानकारी क्रिप्टोकरेंसी पर मासिक रिपोर्ट के संदर्भ में होती है। डैशबोर्ड बाजार पूंजीकरण (पिछले 30 दिन) द्वारा शीर्ष पांच क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए बाजार की गतिविधियों का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है; समापन मूल्य के हिसाब से सबसे बड़े मूवर्स (पिछले 30 दिन); और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़े मूवर्स (पिछले दो महीने)। क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य और मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन की गणना पिछले महीने की तुलना में दिए गए महीने में परिवर्तन के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त, डैशबोर्ड मानक सेटिंग निकायों द्वारा प्रासंगिक रिपोर्टों और चर्चाओं के साथ-साथ प्रत्येक माह के लिए विभिन्न न्यायालयों में प्रमुख विनियामक विकासों की एक व्यापक सूची (स्रोतों के साथ) प्रदान करता है।

7 सीबीडीसी पर मासिक रिपोर्टें, अप्रैल 2022 - मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: रिपोर्टें सीएंडसी प्रभाग को अनुसंधान सहायता के संबंध में डीईए और एनआईपीएफपी के बीच समझौता ज्ञापन में मद 2.12 के अनुसरण में हैं। मासिक रिपोर्टें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) क्षेत्र में निम्नलिखित सहित महत्वपूर्ण विकासों का पता लगाती हैं:

- दुनिया भर में सीबीडीसी परियोजनाओं का अवलोकन, जिसमें सीबीडीसी परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में देशों को दर्शाने वाले दो मानचित्र शामिल हैं। मानचित्र 1 प्रायोगिक, आरंभ और रद्द की गई परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और मानचित्र 2 विकास चरण में परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- प्रमुख संस्थानों और मानक निर्धारण एजेंसियों द्वारा हाल की रिपोर्ट और चर्चाएँ।
- न्यायक्षेत्रों में हाल के घटनाक्रम।
- बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) से जुड़ी डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं सहित कोई अन्य अपडेट।

रिपोर्ट में दो अनुबंध भी शामिल हैं: अनुबंध 1 में सीबीडीसी परियोजनाओं को पूरा करने वाले कुछ देशों की स्थिति बताने वाली एक तालिका दी गई है। अनुबंध 2 सीबीडीसी और क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी-तंत्र में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दों की एक सतत शब्दावली है।

8 वित्तीय स्थिरता पर मासिक रिपोर्टें, अप्रैल 2022 - मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: मासिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय बाजार के विकास और भारतीय वित्तीय बाजारों में हाल के विकास जैसे मुद्रा बाजार, सरकारी बांड बाजार, कॉर्पोरेट बांड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और शेयर बाजार की स्थितियों को शामिल करना है। टिप्पणी प्रतिलाभो, विस्तार, शेयर बाजार सूचकांक संचलनों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और म्यूचुअल फंड निवेश जैसे व्युत्पन्नों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), बीमा और पेंशन क्षेत्रों में विकास मासिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के कुछ अन्य भाग हैं। रिपोर्ट बाजार आधारित वित्तीय तनाव सूचकांकों (एफएसआई) जैसे मुद्रा बाजार एफएसआई, बांड बाजार एफएसआई, इक्विटी बाजार एफएसआई और विदेशी मुद्रा बाजार एफएसआई, बैंक और एनबीएफसी एफएसआई और एक समग्र एफएसआई का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है जिसे उप-सूचकांक का उपयोग करके बनाया गया है।

9 **मैक्रो-डैशबोर्ड : वित्तीय बाजारों में उभरते तनाओं को पकड़ने के लिए संकेतकों का दृश्य प्रतिनिधित्व,** अप्रैल – मार्च 2024

प्रायोजक : डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: मैक्रो-डैशबोर्ड उन प्रमुख व्युत्पन्नों की दृश्य प्रस्तुति हैं जो अर्थव्यवस्था में वित्तीय तनाव के आकलन में मदद करते हैं। व्युत्पन्न विभिन्न वित्तीय बाजारों जैसे बांड बाजार, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में स्थितियों को दर्शाते हैं। एनबीएफसी और बैंकिंग क्षेत्रों में तनाव का आकलन करने के लिए संकेतक भी मैक्रो-डैशबोर्ड में शामिल हैं।

मैक्रो-डैशबोर्ड में प्रत्येक ग्राफ़ उनके 25वें प्रतिशतक, औसत और 75वें प्रतिशतक मानों के साथ व्युत्पन्नों की दीर्घकालिक समय श्रृंखला (10 वर्ष) दिखाता है। डैशबोर्ड में एक सुविधा है जो उपयोगकर्ता को कम समय-सीमा (एक वर्ष) या लंबी समय-सीमा के लिए ग्राफ़ को देखने का विकल्प देती है। डैशबोर्ड को वर्ष भर में संशोधित और बेहतर बनाया गया है। डैशबोर्ड में जोड़ी गई कुछ विशेषताओं में सारांश आँकड़े, ऐतिहासिक डेटा के संबंध में अंतिम मूल्य की प्रतिशतक रैंक और ऐतिहासिक डेटा की तुलना में अंतिम मूल्य की स्थिति के आधार पर लाल/हरा ब्लिंकर शामिल हैं। वित्तीय असुरक्षा के शुरुआती लक्षण दिखाने वाले और गंभीर या मध्यवर्ती जोखिम के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्नों की एक सूची मासिक आधार पर तैयार की जाती है।

10 **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुतीकरण और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणियां,** अप्रैल 2022 - मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: इसका उद्देश्य संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फिच रेटिंग्स, डीबीआरएस मॉर्निंग स्टार, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) ग्लोबल रेटिंग्स, और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन (आरएंडआई) इंक. के

साथ बैठकों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और ऐसे ही अन्य दस्तावेज तैयार किया जाना जारी रहेगा:

- अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुति
- सचिव (ईए) के लिए बातचीत के बिंदु
- रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रश्नावली/चर्चा विषयों पर प्रतिक्रियाएँ

11 वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण और निवारण एजेंसी पर टिप्पणियां और मसौदा विधान, अप्रैल 2022 – मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: व्युत्पन्न वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधान (एफएसआरएल) प्रभाग के अनुसंधान समर्थन के संबंध में डीईए और एनआईपीएफपी के बीच समझौता ज्ञापन में मद 2.15 के अनुसरण में थे।

एफएसएलआरसी ने 2013 में भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) का एक मसौदा तैयार किया - एक एकीकृत कोड जिसने वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण (एफसीपी) विधियों के प्रति सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया और एक एकीकृत वित्तीय निवारण एजेंसी की स्थापना की। एफसीपी विधेयक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के सभी ग्राहकों के संबंध में आधारभूत उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों को शामिल करके और खुदरा ग्राहकों के संबंध में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा को मान्यता देकर एफएसएलआरसी की सिफारिशों का पालन किया। पिछले वित्तीय वर्ष में, नवंबर 2018 में मसौदा एफसीपी विधेयक प्रस्तुत करने के बाद से एफसीपी के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उभरते विकास और मुद्दों पर एक पृष्ठाधार टिप्पण तैयार किया गया था।

इस टिप्पण के उपरांत, एफएसआरएल प्रभाग से प्राप्त टिप्पणियों और प्रश्नों के लिए प्रतिक्रियाओं के दो सेट तैयार किए गए थे। विभिन्न बैठकों में चर्चा किए गए बिंदुओं और विनियामकों से प्राप्त टिप्पणियों को शामिल करते हुए एफसीपी विधेयक को संशोधित किया गया था। वर्तमान में, एफसीपी विधेयक को प्रत्येक वित्तीय विनियामक की प्रमुख विधि में शामिल करने का आशय है। विधेयक तीन पहलुओं से संबंधित है - प्रत्येक विनियामक के अंतर्गत एक स्वतंत्र, तीन-चरणीय शिकायत निवारण तंत्र; एफसीपी के सिद्धांत एफसीपी पर 2022 जी-20/ओईसीडी उच्च स्तरीय सिद्धांतों के अनुरूप हैं, तथा विनियामकों द्वारा विनियमन बनाने की प्रक्रिया। इसके अलावा, एफसीपी के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के विहंगावलोकन और टिप्पणियों पर विनियामकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते हुए प्रस्तुतीकरण तैयार किए गए हैं।

12 एआईआईबी, आईबीआरडी, एडीबी और आईएफसी पर ध्यान-केंद्रण के साथ एमबीडी और आईएफसी द्वारा एलसीएफ पर टिप्पणी, अप्रैल 2022 - मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

उद्देश्य: यह टिप्पणी ओएमआई प्रभाग को अनुसंधान सहायता के संबंध में डीईए और एनआईपीएफपी के बीच समझौता ज्ञापन की मद 2.20 के अनुसरण में थी। टिप्पणी का उद्देश्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) के माध्यम से संप्रभु और गैर-संप्रभु उधारकर्ताओं द्वारा स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण (एलसीएफ) का लाभ उठाने के दायरे की जांच करना था। पत्र विशेष रूप से एआईआईबी, आईबीआरडी, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के

मामले के अध्ययन के माध्यम से ऋण संरचनाओं, एलसीएफ उपकरणों और मूल्य निर्धारण पहलुओं सहित एलसीएफ कार्यक्रमों की जांच करता है।

13 डीईए-एनआईपीएफपी अनुसंधान कार्यक्रम, दिसम्बर 2022

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: आर. कविता राव, मुकेश कुमार और पुल्किट कुमार शर्मा

उद्देश्य: केंद्र और व्यक्तिगत राज्य सरकारों में पेंशन की प्रवृत्तियों और स्थिरता का राज्य-स्तरीय विश्लेषण। प्रारंभ में दो राज्यों के लिए मान्यताओं पर आधारित विश्लेषण किया जा सकता है और टेम्पलेट पर चर्चा के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

14 पूंजीगत व्यय पर डीईए परियोजना, जनवरी 2022 - अगस्त 2023

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: प्रताप रंजन जेना, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे

उद्देश्य: अध्ययन वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के उनके बजटीय लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक पूंजीगत व्यय में अंतर के रुझानों और कारणों के अलग-अलग (क्षेत्र-वार और घटक-वार) विश्लेषण का आकलन करता है।

इस अध्ययन के निम्नलिखित अनुसंधान उद्देश्य हैं:

- वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय के रुझान और संरचना की जांच करना।
- वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विश्लेषण करना।
- केंद्र और राज्यों में वास्तविक बनाम आवंटित पूंजीगत व्यय के बीच अंतर के कारणों की जांच करना।

15 वैश्विक ऋण खामियों को प्रबंधित करना – जी-20 पत्र, 1 अक्तूबर 2022 - 15 जून 2023

प्रायोजक: मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वित्त मंत्रालय

दल: सुप्रियो डे, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, कृति वट्टल, रचना शर्मा, वी. राम्या राजाश्री, आशिम कपूर, प्रवीण सिंह, रितिका सिंह, आनंदिता गुप्ता, उत्सव सक्सेना और राधिका अग्रवाल।

उद्देश्य: वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी से पहले भी बढ़ती ऋण समस्या का सामना कर रही है। हालाँकि, महामारी और हालिया भू-राजनीतिक तनाव ने इस संकट को और बढ़ा दिया है और वैश्विक ऋण संकट के एक प्रणालीगत संकट में परिवर्तित होने का संकट पैदा हो गया है। विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों के लिए संप्रभु ऋण प्रशासन का मुद्दा, कोविड-19 महामारी के फैलने से बहुत पहले ही जी-20 के एजेंडे में शामिल हो गया था। लेकिन महामारी ने इस मुद्दे को विकासशील दुनिया को संकट से निपटने में सहायता करने के जी-20 के सामूहिक प्रयासों के केंद्र में ला दिया। इस टिप्पणी का उद्देश्य मध्यम-आय वाले देशों (एमआईसी) और निम्न-आय वाले देशों (एलआईसी) के सामने आने वाले ऋण संकट की प्रकृति के बीच

मुख्य अंतर/समानताओं को समझना और दोनों श्रेणियों के लिए ऋण राहत कैसे प्राप्त करें, यह समझना है।

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए चल रहे अध्ययन

1. **पुराणी पेंशन योजना पर लोक व्यय को परिगत करने और वृद्धावस्था आय सहयोग प्रणाली में कर्मकार समावेशन को व्यापक बनाने के लिए सुधार**

प्रायोजक: स्व-प्रारंभित (एनआईपीएफपी)

दल: मुकेश कुमार आनंद

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य 'पुरानी पेंशन प्रणाली' (ओपीएस) के तहत परिभाषित लाभों को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव पर कार्य करना है। यह तर्क दिया जाता है कि ओपीएस में सेवानिवृत्ति लाभ के कुछ घटक अतिरेक का गठन करते हैं। इसलिए हम ऐसे 'सेवांत लाभों' को कम करने का प्रस्ताव करते हैं, अर्थात्, (i) अवकाश नकदीकरण और (ii) स्तंभ -1 से लाभार्थियों के लिए पेंशन का कम्यूटेशन, और संसाधनों का आगे और उपयोग करना, जिसके फलस्वरूप 40 वर्ष से कम आयु के सभी मौजूदा श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में 1000 रुपये के वार्षिक सरकारी योगदान को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

2. **सार्वजनिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण**

प्रायोजक: स्व-प्रारंभित

दल: मुकेश कुमार आनंद

उद्देश्य: केंद्रीय वेतन आयोग तीन व्यक्ति उपभोग इकाइयों के लिए औसत (वांछनीय) उपभोग बास्केट पर विचार करके न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है। यह सबसे निचले स्तर की भर्ती की बुनियादी प्रोफ़ाइल विकसित करने के लिए प्रवेश स्तर पर रोजगार विवरण में दी गई न्यूनतम आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है। ऐसे में किसी नए प्रवेशकर्ता की प्रोफ़ाइल के उस नियाजन विवरण से परे जाने की संभावना होती है जिसे नियोजन विवरण पर्याप्त मानता है। ये वेतन अपेक्षाओं के निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं और बदले में श्रम बल की भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूनतम वेतन को पुन: विन्यासित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय से उपभोग व्यय डेटा और निम्नतम स्तर के प्रवेशकर्ता की वांछित विशेषताओं का उपयोग किया जाता है।

3. **सीपीआई मंहगाई को क्या संचालित करता है?** समाप्ति की संभावित तारीख अगस्त 2023

प्रायोजक: स्व-प्रारंभित

दल: अमेय सप्रे, राधिका पांडे और प्रमोद सिन्हा

उद्देश्य: यह पत्र मुद्रास्फीति के चालकों को निर्धारित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), इसकी संरचना और इसके डिजाइन में संरचनात्मक मुद्दों का विश्लेषण करता है।

4. **राजवित्तीय संघवाद और लिंग समानता,** जनवरी 2021 - दिसम्बर 2023

प्रायोजक: फोरम ऑफ़ फेडरेशंस, ओटावा

दल: लेखा चक्रवर्ती और दिव्य रंगन (जून 2021 तक कार्य किया)

उद्देश्य: यह परियोजना कर हस्तांतरण, व्यय असाइनमेंट और राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर विशेष बल प्रदान करने के साथ लिंग और संघवाद के बीच संभावित संबंधों का विश्लेषण करती है।

5. **चयनित राज्यों हेतु जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तपोषण,** जनवरी 2023 - जनवरी 2024

प्रायोजक: स्व-प्रारंभित

दल: अमनदीप कौर

उद्देश्य: अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान के क्षेत्र हैं:

i. क्या अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण तंत्र में पर्यावरणीय चर को एकीकृत करने से राज्यों के अनुकूलन और शमन प्रयासों के लिए संसाधन अधिकतम हो जाते हैं?
ii. विभिन्न राज्यों द्वारा वनों और पारिस्थितिकी पर कुल व्यय का आकलन करना।
iii. सीएएमपीए निधियों का उपयोग और उसका अभिसरण।
iv. अंतिम समीक्षा के बाद जिन राज्यों का चयन किया जा रहा है उनके पास उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को समझना।

6. **ओडिशा के बालकों के स्वास्थ्य पर व्यय अनुकूलन की विवक्षा,** मार्च 2023 - मार्च 2024

प्रायोजक: स्व-प्रारंभित

दल: अमनदीप कौर

उद्देश्य: ओडिशा राज्य में राजकोषीय विवेकशीलता होने के बावजूद, बालकों के लिए मानवशास्त्रीय संकेतक प्रभावशाली नहीं हैं। लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में इन संकेतकों के कम होने की अधिक घटना देखी गई है। यद्यपि अंतर-सरकारी हस्तांतरण एक अतिरिक्त संसाधन है, अनुकूलन पर राज्य द्वारा जलवायु खर्च की जांच करने और इसकी बाधाओं और चुनौतियों को समझने की आवश्यकता है।

7. **सतत विकास में सार्वजनिक व्यय, शासन और क्षेत्रीय असमानता: असम में जिला-स्तरीय विश्लेषण,** मार्च 2022 - मार्च 2024

प्रायोजक: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्

दल: भावेश हजारिका और अंकित सिंह

उद्देश्य: अध्ययन में जिलों में एसडीजी उपलब्धि के विचलन को समझाने के लिए सार्वजनिक व्यय और शासन की गुणवत्ता की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जिसका नीतिगत नुस्खों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

8. **भारत में राज्य वित्त के मुद्दे की पुन:समीक्षा : कतिपय अनुभवजन्य अन्वेषण,** नवम्बर 2021 - दिसंबर 2023

प्रायोजक: स्व-आरंभित

दल: भाबेश हजारिका और देनेश कुमार नायक

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य राज्य के वित्त के लिए विभिन्न मुद्दों और विवक्षाओं का विश्लेषण करना है।

9. **भारतीय बच्चों के बीच जल, स्वच्छता और हाइजीन (वॉश) और स्टंटिंग पर सार्वजनिक व्यय,** दिसम्बर 2022 - दिसम्बर 2023

प्रायोजक: स्व-आरंभित

दल: भाबेश हजारिका, अंकित सिंह और पल्लबी गोगोई

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य भारत में बच्चों के बौनेपन को कम करने पर वॉश पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का पता लगाना है।

10. **स्वास्थ्य में सार्वजनिक प्रावधान को लागू करना: क्या सार्वजनिक और निजी प्रदाता सह-अस्तित्व में हैं?** अगस्त 2021 - जून 2023

प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

दल: मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता

उद्देश्य: अध्ययन सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के प्रसार और उनके सह-अस्तित्व, यदि कोई हो, का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच संभावित संपूरकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

11. **भारतीय राज्य आर्थिक और सामजिक निष्पादनों में विभेद क्यों रखते हैं?** जुलाई 2022 - मार्च 2024

प्राजोजक: एनआईपीईएफ

दल: रुद्राणी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मंडल (सीडीएस) और दिनेश कुमार नायक

उद्देश्य: आर्थिक वृद्धि और मानव विकास के मामले में भारतीय राज्यों के बीच काफी विविधता है। यह अध्ययन इस विविधता को समझाने वाले कारकों के वर्ग की पहचान करने का प्रयास करता है जैसे प्रारंभिक स्थिति, पूंजी स्टॉक, भौतिक अवसरंचना, सामाजिक अवसरंचना की गुणवत्ता और स्तर और शासन की गुणवत्ता।

12. **भारत में करदाता सेवाओं में सुधार करना,** 1 अक्तूबर 2022 - 15 जून 2023.

प्रायोजक: ईएसी-पीएम

दल: सुप्रियो डे, प्राची जैन, नीति गुप्ता और आलोकिता बासु

उद्देश्य: कर अनुपालन में सुधार के लिए, करदाता सेवाएँ एक कुशल और प्रभावी कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। आईटी अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण और स्वचालन के साथ-साथ कर रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने, करों का भुगतान करने, समायोजन करने, जानकारी अपडेट करने और विवादों और शिकायतों को हल करने पर जानकारी बढ़ाने के माध्यम से करदाताओं की सेवाओं को सक्षम करने वाला है।

13. **स्कूली शिक्षा पर लिंग-संवेदी बजटिंग का अध्ययन,** 2019 - दिसम्बर 2022 **(संशोधन के अधीन)**

प्रायोजक: नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन

दल: सुकन्या बोस, अनुराधा डे और हर्षिता शर्मा

उद्देश्य: लिंग बजटिंग एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो लिंग-विभेदित प्रभाव को प्रकट करने के लिए सरकारी बजट की जांच करता है और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग-आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अधिक प्राथमिकताओं की हिमायत करता है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक बजटिंग पर लागू नीतियों और प्रथाओं को समझना है। क्या लिंग बजट मौजूद हैं? यदि हां, तो लड़कियों की शिक्षा के लिए योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने के

उपकरण के रूप में ये कितने सार्थक हैं? बजट में लड़कियों की शिक्षा पर व्यय का पैटर्न क्या है? अधिक सार्थक लिंग बजटिंग (जीबी) प्रक्रिया के लिए डेटा में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है?

14. **भारतीय राज्यों में राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा और मूल्यांकन,** दिसम्बर 2021 - मार्च 2023

प्रायोजक: यूनिसेफ इंडिया

दल: मनीष गुप्ता, स्मृति बहल, सोनल अग्रवाल, देवयानी गुप्ता और प्रियांशी गर्ग

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने में एसएफसी के कार्यकरण और उनकी सिफारिशों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना है।

15. **कर नीति और अनुपालन के प्रति प्रवृतियों का आकलन,** जनवरी 2022

प्रायोजक: स्व-प्रारंभिक

दल: आर. कविता राव

उद्देश्य: करदाताओं की धारणाओं से कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि के सवाल पर विचार करते हुए, अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या भारत में नागरिकों द्वारा कर अनुपालन के बारे में लोगों की धारणाएं एक ओर निष्पक्षता और अनुपालन में आसानी के बारे में उनकी धारणाओं से संबंधित हैं, और दूसरी ओर, सरकारी व्यय से कथित लाभ से। अध्ययन में यह पता लगाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के 150-200 व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है कि क्या धारणाओं में अंतर है। इस अध्ययन को एक प्रायोगिक माना जा सकता है जिसे बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में विस्तारित किया जा सकता है, यदि प्रारंभिक परिणाम रुचिकर पाए जाते हैं।

16. **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों के माध्यम से बजट निष्पादन में सुधार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मामला,** नवम्बर 2022, समाप्ति की संभावित तारीख दिसम्बर 2023

प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

दल: मीता चौधरी, प्रीतम दत्ता, नित्या चुटानी और खुशबू आहूजा

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बजट निष्पादन में सुधार में एकल नोडल खाते (एसएनए) की भूमिका की जांच करना है। चयनित राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

17. **कोविड महामारी वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य व्यय का निर्धारण,** नवम्बर 2022, समाप्ति की संभावित तारीख दिसम्बर 2023

प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोणों के अंतर्गत

दल: मीता चौधरी और चेतना चौधरी

उद्देश्य: अध्ययन में कोविड वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय राज्यों में स्वास्थ्य पर किए गए सार्वजनिक व्यय की प्रकृति की जांच करने का प्रयास किया गया है। यह दो चरणों में मुद्दे का विश्लेषण करता है। सबसे पहले, यह सामाजिक सेवाओं पर व्यय के बड़े दायरे के भीतर स्वास्थ्य व्यय के समग्र घटकों की तुलना करता है। दूसरे, यह चयनित वर्ष में सबसे अधिक स्वास्थ्य व्यय करने वाले पांच राज्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और अधिक विस्तृत स्तर पर पैटर्न को समझने के लिए गहन विश्लेषण करता है।

आरंभ की गई नई परियोजनाएं

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नई परियोजनाएं

1. **मध्य प्रदेश के राजस्व संघटन पर एनाईपीएफपी अध्ययन,** आरंभ होने की तारीख से छह माह, मार्च 2023 से प्रारंभ

प्रायोजक: वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश सरकार

दल: सच्चिदानंद मुकर्जी, शिवानी बडोला और विष्णु ई.के.

उद्देश्य: क) जीएसटी में कर आधार कैसे बढ़ाया जाए; ख) जीएसटी में कर दक्षता में सुधार कैसे किया जाए, और ग) जीएसटी के अंतर्गत कर संग्रह बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए।

2. **उत्तराखंड राज के लिए लोक व्यय और वित्तीय उत्तरदायित्व (पीईएफए) आकलन,** अप्रैल 2023 – जनवरी 2024

प्रायोजक: उत्तराखंड सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना, दिनेश कुमार नायक, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे

उद्देश्य: एनआईपीएफपी ने उत्तराखंड राज्य के लिए परियोजना पीईएफए मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया है। मूल्यांकन स्थापित पीईएफए मूल्यांकन पद्धति का अनुपालन करेगा। अध्ययन उत्तराखंड में पीएफएम प्रणाली की ताकत और कमजोरियों को दर्शाएगा और इस प्रक्रिया में अधिकारियों को उचित नीतिगत उपाय करने में मदद करेगा।

3. **त्रिपुरा के राज्य पीएसयू का अध्ययन,** अप्रैल 2023, समाप्ति की संभावित तारीख अक्तूबर 2023

प्रायोजक: वित्त विभाग, त्रिपुरा सरकार

दल: आर. कविता राव और रुद्राणी भट्टाचार्य

उद्देश्य: यह अध्ययन त्रिपुरा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा करेगा, त्रिपुरा सरकार के लिए ऋण-स्थिरता का विश्लेषण करेगा, कर-जीडीपी अनुपात पर तुलनात्मक अध्ययन करेगा और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्रोतों की पहचान करेगा।

वित्त मंत्रालय के लिए नई परियोजनाएं

1 **एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम – राज्य सरकारों द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों को वित्त हस्तांतरण की प्रवृत्तियों और तंत्र के राज्यवार विश्लेषण पर अध्ययन,** अप्रैल 2023 – मार्च 2024

प्रायोजक: डीईए, वित्त मंत्रालय

दल: मनीष गुप्ता और प्रियांशी गर्ग

उद्देश्य: इस परियोजना में बजट दस्तावेजों, वित्त आयोग की रिपोर्ट और सूचना के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों को वित्त के हस्तांतरण तंत्र और प्रवृत्तियों की जांच करना शामिल है।

2 **योजनाओं और परियोजनाओं पर बार-बार होने वाले चुनावों का प्रभाव,** जनवरी-जून 2023

प्रायोजक: व्यय विभाग, वित्त मंत्राला

दल: आर. कविता राव, ए.एन. झा, माल्विका महेश और रॉली कुकरेजा

उद्देश्य: बार-बार चुनाव होने से परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन पर किस हद तक प्रभाव पड़ता है? क्या देश के लिए संभावित 'नुकसान' का पता लगाने के लिए इन्हें परिमाणित किया जा सकता है? अध्ययन का उद्देश्य चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर बार-बार चुनावों के प्रभाव का आकलन करना है, और एमसीसी के कार्यान्वयन और नीतिगत कार्यों पर इसके निर्विवाद प्रभाव और किसी भी प्रकार के नए या ताजा व्यय पर रोक लगाना है। इसके साथ ही, चुनाव ड्यूटी के लिए बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने से सामान्य राजस्व संग्रह और चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन, दोनों ही पर असर पड़ता है। आसन्न चुनावी कैलेंडर सत्तारूढ़ सरकार को मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों, योजनाओं और आर्थिक सहायता और/या कर छूट या रियायतों की घोषणा करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ये कार्यक्रम चुनावी वर्ष में बजटीय घोषणाओं या बजट के बाद की घोषणाओं का भाग हो सकते हैं। इनके लिए संसाधन कुछ अन्य व्यय आवंटन में अंतर्निहित कटौती से पाए जा सकते हैं। आसन्न चुनावी कैलेंडर के कारण चुने हुए क्षेत्रों और एजेंटों के पक्ष में व्यय की ऐसी वृद्धि हो सकती है जो संबंधित परिणामों या नतीजों से मेल नहीं खाती।

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए नई परियोजनाएं

1 जीडीपी के अग्रिम अनुमानों के संकलन की वैकल्पिक पद्यति का निर्माण, समाप्ति की संभावित तारीख अगस्त 2023

प्रायोजक: स्व-आरंभित

दल: अमेय सप्रे और वैशाली भारद्वाज

उद्देश्य: यह पत्र अनुमान के वर्तमान स्वरूप में उपयोग की जाने वाली मौजूदा और पारंपरिक पद्यतियों की तुलना में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों को संकलित करने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने और निर्माण करने का प्रयास करता है।

2 चयनित राज्यों में लोक निवेश के प्रबंधन की स्टॉकटेकिंग, मार्च 2023, समाप्ति की संभावित तारीख जून 2023

प्रायोजक: विश्व बैंक

दल: सुप्रियो डे, आर. कविता राव, प्रियाली दास, मयूराक्षी सिन्हा, सीमा मौर्या और दिव्या रुद्रा

उद्देश्य: भारत सरकार यह मानते हुए कि प्राथमिक विकास की मुख्य बाधा मजबूत अवसंरचना की कमी होना है, अवसंरचना के अंतर को कम करने के लिए अनेक पहलकदम उठा रही है। चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल को देखते हुए, राजकोषीय समेकन जारी रहने की आशा की जाती है जिससे अवसंरचना के लिए व्यय में वृद्धि करने के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। इसके परिणामस्वरूप, अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश की दक्षता को अधिकतम करना और अवसंरचना में निजी निवेश जुटाना महत्वपूर्ण है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने की सुविधा के लिए, इस विषय में सहयोजित होने और विश्लेषणात्मक आधार में योगदान करने के लिए विश्व बैंक द्वारा नैदानिक कार्य प्रस्तावित है। चयनित राज्यों में सार्वजनिक निवेश के प्रबंधन पर एक स्टॉकटेकिंग प्रस्तावित है। ऐसा भारतीय संदर्भ के अनुरूप प्रश्नावली और विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर किया जाएगा, जिसमें राज्यों की अच्छी प्रथाओं और सबक को उजागर किया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ भी उठाया जाएगा।

3 भारतीय राज्यों में स्पष्ट बजट आर्थिक सहायता : कर्नाटक का मामला, 1 मार्च - 31 मई 2023

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: श्री हरी नायडु ए. और अमरनाथ एच.के.

उद्देश्य: अध्ययन द्वारा उप-राष्ट्रीय स्तर पर व्यय वर्गीकरण के अनुसार स्पष्ट आर्थिक सहायता की मात्रा और परिमाण का अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्ययन कर्नाटक राज्य 2018-19 और 2023-24 (बीई) पर केंद्रित है।

4 **विशेष श्रेणी के राज्यों में स्पष्ट बजट आर्थिक सहायता,** मार्च-अक्तूबर 2023

प्रायोजक: एनआईपीएफपी

दल: श्री हरी नायडु ए. और अमरनाथ एच.के.

उद्देश्य: अध्ययन द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए व्यय वर्गीकरण के अनुसार स्पष्ट सब्सिडी की मात्रा और परिमाण का अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वे अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर हैं।

3 कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन

क्रमांक	शीर्षक	आयोजक	तारीख और स्थान
1	क्रेडिट बाजारों पर दो-दिवसीय कार्यशाला	एनआईपीएफपी समन्यक: रेणुका साने	3-4 नवम्बर 2022 एनआईपीएफपी
2	'भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव' पर दो-दिवसीय कार्यशाला	एनआईपीएफपी समन्यक: सच्चिदानंद मुकर्जी	28-29 नवम्बर 2022 एनआईपीएफपी
3	'वैश्विक कर विचार-गोष्ठी- 2022' पर वेबिनार	एनआईपीएफपी समन्यक: सुरांजलि टंडन	1-2 दिसम्बर 2022 एनआईपीएफपी
4	'पूर्व-बजट (वित्त वर्ष 2023-24) भारतीय अर्थव्यवस्था, 2022-23 की समीक्षा' पर विशेषज्ञ विश्लेषण और वार्ता	एनआईपीएफपी समन्यक: रुद्राणी भट्टाचार्य	20 दिसम्बर 2022 एनआईपीएफपी
5	कंबोडिया के प्रतिनिधिमंडल के लिए 'महिला अधिकारिता हेतु एक उपकरण के रूप में लिंग बजट का सांस्थानीकरण' पर कार्यशाला	एनआईपीएफपी समन्यक: लेखा चक्रवर्ती	22 दिसम्बर 2022 एनआईपीएफपी
6	'क्रिप्टो चुनौती को संचालित करने के लिए नीतिगत ढांचा' पर डीईए पैनल चर्चा	एनआईपीएफपी समन्यक: राधिका पांडे	23 जनवरी 2023 एनआईपीएफपी
7	सत्रहवीं पांच संस्थान बजट संगोष्ठी 2023 : 'केंद्रीय बजट, 2023-24 का परिचय'	सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ, एनसीएईआर और एनआईपीएफपी द्वारा संयुक्त रूप से समन्यक: आर. कविता राव	6 फरवरी 2023 एनसीएईआर
8	'भारत में स्थिर वित्त' पर आधे दिन का सम्मेलन	एनआईपीएफपी समन्यक: सुरांजलि टंडन	10 फरवरी 2023 नई दिल्ली
9	''वित्तीय बाजारों में उपभोक्ता परिवाद निवारण' पर सम्मेलन	एनआईपीएफपी समन्यक: रेणुका साने	10-11 फरवरी 2023 धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

क्रमांक	शीर्षक	आयोजक	तारीख और स्थान
10	'#जस्ट ट्रांज़िशन के लिए वित्तपोषण संबंधी विचार क्या हैं, यह जानने के लिए #ग्लोबल जेटी डायलॉग में वित्त पर हमारे पावर-पैक और अंतिम पैनल की शुरुआत' पर कार्यशाला	एनआईपीएफपी समन्यक: सुरांजलि टंडन	23 मार्च 2023 एनआईपीएफपी

4 प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	शीर्षक	दिन और समय	स्थान	कार्यक्रम समन्वयक
1.	विभाग के सहयोग से असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति: परिदृश्य और राजकोषीय पूर्वानुमान/अनुमान' पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम	25-29 अप्रैल 2022	एनआईपीएफपी	रुद्राणी भट्टाचार्य
2.	भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (2021 बैच के 12 अधिकारी और 2020 बैच का एक अधिकारी)	2-7 मई 2022	एनआईपीएफपी	रुद्राणी भट्टाचार्य
3.	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस), एनएएए, शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2-13 मई 2022	एनआईपीएफपी	अमेय सप्रे
4.	असम सरकार के वित्त विभाग के सहयोग से विभाग के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	6-10 जून 2022	गुवाहाटी, असम	प्रताप रंजन जेना
5.	असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'परिणाम बजट पर केंद्रित बजट प्रबंधन' पर तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 अगस्त - 1 सितम्बर 2022	गुवाहाटी, असम	प्रताप रंजन जेना

क्रमांक	शीर्षक	दिन और समय	स्थान	कार्यक्रम समन्वयक
6.	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	10-12 नवम्बर 2022	विकास अध्ययन संस्थान, कोलकाता	प्रताप रंजन जेना
7.	चरण-III, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के सहयोग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवाकालीन मध्य-कैरियर अधिकारियों के लिए लोक वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2-6 जनवरी 2023	LBSNAA, Mussoorie	अमेय सप्रे
8.	गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	11-13 जनवरी 2023	गोवा लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (जीआईपीएआरडी) पुराना गोवा	प्रताप रंजन जेना
9.	आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 जनवरी - 10 फरवरी 2023	एनआईपीएफपी	अमेय सप्रे
10.	भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	13-17 फरवरी 2023	एनआईपीएफपी	अमनदीप कौर
11.	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर लोक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर पांच-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	20-24 मार्च 2023	एनआईपीएफपी	प्रताप रंजन जेना और भाबेश हजारिका

5 प्रकाशन और संचार

संस्थान का द्वि-वार्षिक न्यूज़लेटर जनवरी 2021 और जुलाई 2021 में प्रकाशित हुआ था। इन न्यूज़लेटरों में परियोजनाओं, संकाय क्रियाकलापों और घटनाओं पर अद्यतन जानकारी शामिल की गई थी।

एनआईपीएफपी अकादमिक समिति की बैठक में हर दो महीने में एक न्यूज़लेटर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। तब से, तीन द्विमासिक न्यूज़लेटर (जुलाई-अक्टूबर 2022, जनवरी-फरवरी 2023 और मार्च-अप्रैल 2023) प्रकाशित किए जा चुके हैं।

एनआईपीएफपी के अनुसंधान संकाय और उनके सहयोगियों द्वारा लिखे गए कुल 12 कार्यकारी पत्र एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे। रिपोर्ट के वर्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 25 ब्लॉग लेख प्रकाशित किए गए। ब्लॉग http://nipfp.org.in/blog/ पर उपलब्ध है। प्रकाशन इकाई संस्थान की वेबसाइट http://www.nipfp.org.in को नियमित रूप से अद्यतन बनाने का कार्य भी करती है।

ट्विटर पर एनआईपीएफपी के सोशल मीडिया अकाउंट, @nipfp.org का उपयोग इसके शोध कार्य और आयोजनों की जानकारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति के क्षेत्रों में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया था।

संस्थान के प्रसार-प्रसार प्रयासों के भाग के रूप में, अकादमिक पत्र वेबसाइट अपडेटों और ईमेलर्स के माध्यम से हितधारकों के बीच व्यापक रूप से वितरित किए गए थे। (एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्रों की सूची के लिए अनुलग्नक II, मूल्य प्रकाशनों के लिए अनुलग्नक V और संकाय-प्रकाशित सामग्री के लिए अनुलग्नक VI देखें)।

6 पुस्तकालय और सूचना केंद्र

एनआईपीएफपी पुस्तकालय और सूचना केंद्र लोक वित्त और नीति के क्षेत्र में एक शोध पुस्तकालय के रूप में विकसित है जिसमें लोक वित्त; राजकोषीय नीति; सूक्ष्म और वृहद अर्थशास्त्र; उद्योग अध्ययन; योजना और विकास; आर्थिक सिद्धांत और कार्यप्रणाली; भारतीय अर्थव्यवस्था; राजनीतिक अर्थव्यवस्था; पर्यावरणीय और प्राकृतिक अर्थशास्त्र; शहरी अर्थशास्त्र और शहरी वित्त; स्वास्थ्य अर्थशास्त्र; तथा संघवाद और विकेंद्रीकरण पर समृद्ध संसाधन सामग्री उपलब्ध है।

पुस्तकालय आवश्यक अवसंरचना के साथ तीन तलों में फैला हुआ है। भूतल पर स्थित विशाल पाठक क्षेत्र लैपटॉप और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ पाठकों को वाचन सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय के कार्यकरण और सेवाओं के सभी परिचालन पहलुओं को एक एकीकृत जावाबींस (ईजेबी)-आधारित लाइब्रेरी सॉफ़्टवेयर पैकेज अर्थात लिबसिस-7.0 का उपयोग करते हुए कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

पुस्तकालय सभी कार्यदिवसों पर प्रात: 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक और एक छोड़कर दूसरे शनिवार को प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहता है।

पुस्तकालय संग्रहण

पुस्तकालय में 66,466 से अधिक पुस्तकें और अन्य दस्तावेज़ हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, पुस्तकालय ने अपने संग्रह में 125 नए दस्तावेज़ शामिल किए हैं, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तर की सोसाइटियों, अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रकाशनों का एक अत्यंत व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। पुस्तकालय को भारत की जनगणना, डेटा स्रोतों आदि पर चार सीडी-रोम भी प्राप्त हुए हैं।

पुस्तकालय ने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिस्कल डॉक्यूमेंटेशन (आईबीएफडी) से विभिन्न प्रकाशनों तक पहुंच के लिए ई-सदस्यता भी ग्रहण की है। इस सदस्यता के माध्यम से, संस्थान ने अपने संकायों और शोधकर्ताओं को ई-जर्नल्स, ई-बुक्स, ग्लोबल टैक्स एक्सप्लोरर कॉम्पैक्ट प्लस (ऑनलाइन) की एक श्रृंखला के माध्यम से एक पर्याप्त सुविधा प्रदान की है।

जर्नल

पुस्तकालय निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों, अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता के जर्नलों, डेटाबेस जर्नलों और अन्य ऑनलाइन जर्नलों की सदस्यता लेता है/प्राप्त करता है और उनका रखरखाव करता है।

विवरण	कुल संख्या
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल	31
राष्ट्रीय जर्नल	46

पत्रिकाएं	16
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सदस्यताओं के अंतर्गत जर्नल: 1) अमेरिकन इकॉनॉमिक्स एसोसिएशन 2) अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3) इंस्टिट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज़ 4) इंटर्नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस	12
निम्नलिखित ऑनलाइन डेटाबेसों के अंतर्गत जर्नल: 1) साइंस डाइरेक्ट : इकॉनॉमिक्स, इकॉनॉमीट्रिक्स एंड फाइनेंस बंडल 2) ओयूपी ऑनलाइन इकॉनॉमिक्स जर्नल बंडल कलेक्शन 3) जेएसटीओआर (बिजनेस कलेक्शन I एवं II) 4) इकोलिट विथ फुल टेक्स्ट वर्जन 5) दि स्टाटा जर्नल	

समाचारपत्र और पत्रिकाएं

क्रमांक	राष्ट्रीय समाचारपत्र	प्रिंट/ऑनलाइन
1.	बिजनेस लाइन	प्रिंट
2.	बिजनेस स्टैंडर्ड	प्रिंट + ऑनलाइन
3.	दि इकॉनॉमिक टाइम्स	प्रिंट
4.	एम्प्लॉयमेंट न्यूज़	प्रिंट
5.	दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस	प्रिंट
6.	दि इंडियन एक्सप्रेस	प्रिंट
7.	मिंट	प्रिंट
8.	नवभारत टाइम्स (हिंदी)	प्रिंट
9.	दि टेलीग्राफ (कोलकाता संस्करण)	प्रिंट
10.	दि हिंदू	ऑनलाइन
11.	दि हिंदुस्तान टाइम्स	प्रिंट
12.	दि स्टेटमैन	प्रिंट
13.	दि टाइम्स ऑफ इंडिया	प्रिंट
	अंतर्राष्ट्रीय समाचारपत्र	प्रिंट/ऑनलाइन
1.	फाइनेंशियल टाइम्स	ऑनलाइन

ई-संसाधन

ई-जर्नल डेटाबेस

क्रमांक	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	पहुंच का माध्यम
1.	ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन इकॉनॉमिक जर्नल	http://www.oxfordjournals.org	आईपी-आधारित
2.	जेएसटीओआर (बिजनेस कलेक्शन I एवं II)	http://www.jstor.org	आईपी-आधारित
3.	एल्सेवियर साइंस जर्नल : इकॉनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट सब्जेक्ट	http://www.sciencedirect.com	आईपी-आधारित

4.	इकोनलिट विद फुल टेक्स्ट	http://www.search.ebscohost.com	आईपी-आधारित

ई-डेटाबेस

क्रमांक	डेटाबेस का नाम	वेबलिंक	पहुंच का माध्यम
1.	ओईसीडी कराधान आई-पुस्तकालय	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी-आधारित
2.	ओईसीडी अर्थशास्त्र पुस्तकालय	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी-आधारित
3.	ओईसीडी ईसीडी शासन आई-पुस्तकालय	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी-आधारित
4.	आईबीएफडी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन	http://www.ibfd.org	यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित पहुंच (5 प्रयोक्ताओं तक)
5.	आईएमएफ ई-पुस्तकालय	http://www.elibrary.imf.org	आईपी-आधारित
6.	दि स्टाटा जर्नल	http://www.stata-journal.com	पीडीएफ उपलब्ध
7.	ईपीडब्ल्यूआरएफ इंडिया टाइम सीरीज	http://www.epwrfits.in	आईपी-आधारित
8.	सीईपीआर (चर्चा पत्र)	http://www.cepr.org	(चुनिंदा प्रयोक्ताओं के लिए)
9.	अंतर्राष्ट्रीय कराधान	http://www.internationaltaxation.taxmann.com	यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित पहुंच

कार्पोरेट डेटाबेस

क्रमांक	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	पहुंच का माध्यम
1.	सीएमआईई: इकॉनॉमिक आउटलुक	http://www.economicoutlook.cmie.com	आईपी-आधारित
2.	सीएमआईई: प्रोवेसेल्क्यू	http://www.prowess.cmie.com	आईपी-आधारित
3.	सीएमआईई: केपेक्स	http://www.capex.cmie.com	आईपी-आधारित

ई-पुस्तक डेटाबेस

S.no.	Name of the Database	Web Link	Mode of Accessibility
1.	*एडवर्ड ई-बुक्स	https://www.elgaronline.com/browse?access=user	आईपी-आधारित
2.	**स्प्रिंगेर ई-बुक्स सबजेक्ट बंडल ऑन इकॉनॉमिक्स	http://www.link.springer.com	आईपी-आधारित

वर्तमान जागरूकता सेवा

पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए दस्तावेज़, लेख और समाचारपत्र लेख नियमित रूप से डेटाबेस में जोड़े जा रहे हैं और निम्नलिखित वर्तमान जागरूकता बुलेटिन के रूप में जारी किए जा रहे हैं:

आर्टिकल एलर्ट सेवा (समाचारपत्र कतरनों के नवीनतम संस्करण)

नवीनतम जागरूकता सेवा (पुस्तकों के नवीनतम संस्करण)

नवीनतम विषय-वस्तु सेवा (पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं की विषय-वस्तु के पृष्ठों के लिए मासिक बुलेटिन)

बजट पूर्व और पश्चात विशेष बुलेटिन (बजट के पहले और बाद में संबंधित समाचारों और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों के विचारों का बुलेटिन)

इसके अलावा, पुस्तकालय सभी संकाय सदस्यों को वर्तमान जागरूकता सेवा, ग्रंथ सूची सेवा और संदर्भ सेवा भी प्रदान करता है। यह एनआईपीएफपी संकाय सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से बुक एलर्ट और आर्टिकल एलर्ट भी प्रदान करता है।

एनआईपीएफपी पुस्तकालय द्वारा सब्सक्राइब्ड डेटाबेस/ई-संसाधनों की पहुंच बढ़ाने के लिए, जनवरी 2023 में एक सूचना साक्षरता कार्यक्रम/उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम (ऑनलाइन मोड) आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों/डेटाबेस के उपयोग को बढ़ाना और इसके लिए संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं के ज्ञान को उन्नत करना था।

संसाधन साझाकरण

एनआईपीएफपी पुस्तकालय व्यापक संसाधन साझाकरण और दस्तावेज़ वितरण सेवा के लिए डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) के साथ सदस्यता बनाए रखती है। वर्ष के दौरान, पुस्तकालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित पुस्तकालयों से 20 दस्तावेज़ उधार लिए और अंतरपुस्तकालय संसाधनों के व्यापक प्रसार के लिए समान प्रतिष्ठित पुस्तकालयों को 18 दस्तावेज़ उधार दिए। वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 625 बाह्य अनुसंधान स्कॉलरों और नीति निर्माताओं ने पुस्तकालय का दौरा किया और वे इसके समृद्ध संसाधनों से लाभान्वित हुए।

आरईपीईसी (अर्थशास्त्र में अनुसंधान पत्र)

आरईपीईसी अर्थशास्त्र और संबंधित विज्ञान में अनुसंधान के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए 103 देशों में सैकड़ों वैश्विक स्वयंसेवकों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। परियोजना का केंद्र कार्यकारी पत्र, जर्नल लेख, किताबें, पुस्तक अध्यायों का एक ऑनलाइन, विकेन्द्रीकृत ग्रंथसूची डेटाबेस संग्रहित करना है, जो ऐसे स्वयंसेवकों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। एनआईपीएफपी पुस्तकालय ने संस्थान के कार्यकारी पत्रों के मेटाडेटा को अपलोड करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विषय भंडार आरईपीईसी (अर्थशास्त्र पर शोध पत्र) में भी भाग लिया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईपीईसी में 12 कार्यकारी पत्र अपलोड किए गए हैं। इन एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्रों की 1,607 बार सर्च, एक्सेस की गई और इन्हें डाउनलोड किया गया तथा इनके उद्धरणों को वैश्विक स्तर पर 6,720 बार देखा गया।

आरईपीईसी कार्यकारी पत्र श्रृंखला 2022-2023 के एक्सेस आंकड़े

डाउनलोडों और उदधरण व्यज की संख्या अप्रैल 2022 - मार्च 2023		
माह	डाउनलोड	उदधरण व्यज
2022-04	**206**	637
2022-05	133	552
2022-06	164	568
2022-07	117	539
2022-08	120	533
2022-09	114	552
2022-10	119	518
2022-11	150	**660**
2022-12	108	475
2023-01	119	563
2023-02	114	528

2023-03	143	595
योग	**1607**	**6720**

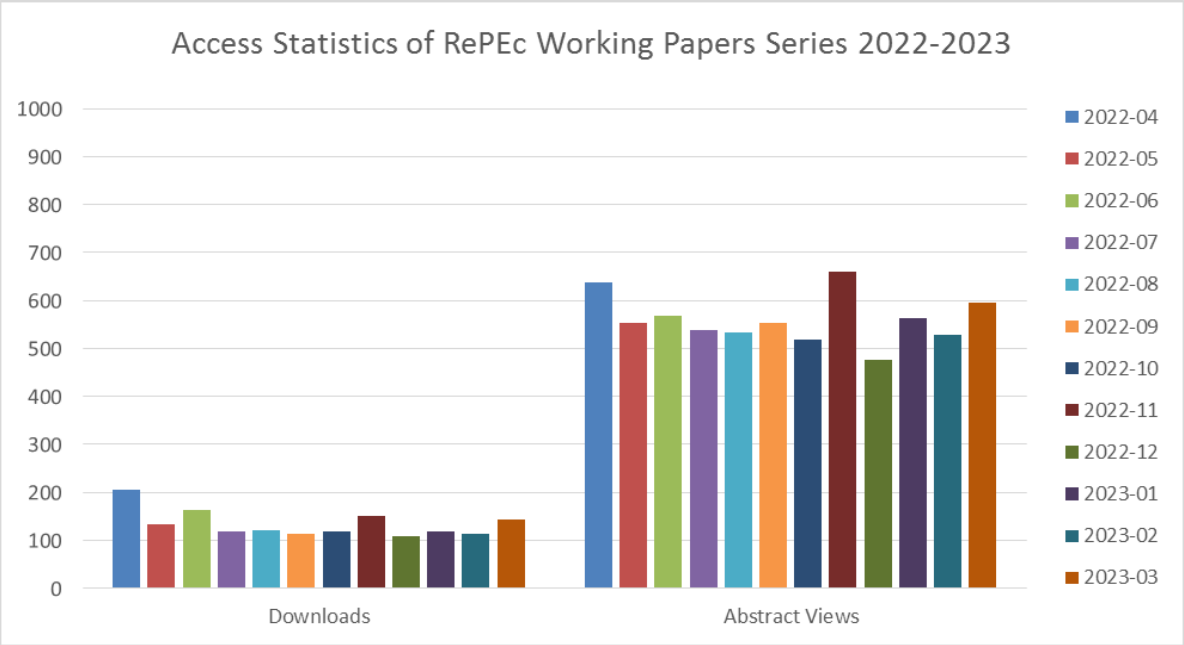

उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि अप्रैल 2022 में अधिकतम संख्या अर्थात 206 में कार्यकारी पत्र डाउनलोड किए गए थे, और नवंबर 2022 में सबसे अधिक संख्या में अर्थात 660 कार्यकारी पत्र उद्धरण डाउनलोड किए गए थे।

रेप्रोग्राफिक सेवाएं

एनआईपीएफपी पुस्तकालय संकाय सदस्यों और बाह्य अनुसंधान स्कॉलरों को पुस्तकालय संसाधन सामग्री की पारंपरिक रिप्रोग्राफिक सेवा प्रदान करता है। हमारे रिप्रोग्राफी रोस्टर की तत्परता को उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया है। वर्ष के दौरान उपयोगकर्ताओं को उनके शोध कार्य के लिए लगभग 3,260 पृष्ठों की फोटोकॉपी सामग्री प्रदान की गई। किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए एनआईपीएफपी लाइब्रेरी में रिप्रोग्राफिक नयाचार का पालन किया जाता है।

पुस्तकालय स्टाफ क्रियाकलाप : 2022-23

प्रकाशित/प्रस्तुत पत्र

सिंह सोनम, 'पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच के लिए रिमोट एक्सेस समाधान की भूमिका: महामारी के दौरान विधिक डेटाबेस तक सतत पहुंच के लिए एक रामबाण', *लाइब्रेरी हेराल्ड*, खंड 60, क्रमांक 3, सितंबर 2022.

सिंह सोनम, सोसाइटी फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और एसएलए-एशिया कम्युनिटी द्वारा आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित 10वें आई-एलआईपीएस 2022 में '21वीं सदी में आधुनिक पुस्तकालय सेवाओं और सुविधाओं का मूल्यांकन: उत्तर भारत के राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालयों के चुनिंदा विधिक पुस्तकालयों का एक अध्ययन' विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 20-22 मई 2022.

संगोष्ठियां, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम

सिंह सोनम, दिल्ली विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बीएलआईएससी - पेपर बी111) के छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता के रूप में लाइब्रेरी इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया। सितंबर 2022.

सिंह सोनम ने डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) की 31वीं वार्षिक आम सभा की बैठक (ऑनलाइन मोड) में भाग लिया, 9 नवंबर 2022.

7 संकाय क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं

आर. कविता राव

एनआईपीएफपी कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया। 21 मार्च - 1 अप्रैल 2022.
- एनआईपीपीएफ में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस), शिमला के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन व्याख्यान दिया। 30 जनवरी 2023.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक व्याख्यान दिया। 7 फरवरी 2023.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक व्याख्यान दिया। 10 फरवरी 2023.
- भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन व्याख्यान दिया। 13 फरवरी 2023.
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजस्व वृद्धि के उपाय' पर व्याख्यान दिया। 20 मार्च 2023.
- बांग्लादेश सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान एक व्याख्यान दिया। 1 अप्रैल 2022.
- वित्त विभाग, असम सरकार के सहयोग से असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति और परिदृश्य' पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में समापन सत्र के दौरान एक व्याख्यान दिया। 29 अप्रैल,2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन व्याख्यान दिया। 2 मई 2022.
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं (2021 बैच के 12 अधिकारी और 2020 बैच के एक अधिकारी) के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में कर नीति डिजाइन में चुनौतियां' पर एक व्याख्यान दिया। 2 मई 2022.

आमंत्रित व्याख्यान

- नई दिल्ली में सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) के साथ साझेदारी में सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित सेव द चिल्ड्रन इंडिया के अध्ययन 'भारत में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा

को सार्वभौमिक बनाने की लागत' के विमोचन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 20 सितंबर 2022.

- गया में बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा आयोजित बिहार के आईएएस प्रोबेशनर्स और डिप्टी कलेक्टरों के लिए सार्वजनिक वित्त और नीति से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 8 नवम्बर 2022.
- नॉर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक एसोसिएशन के 23वें वार्षिक सम्मेलन और अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में आधार व्याख्यान दिया। 16 नवम्बर 2022.
- एलबीएसएनएए, मसूरी में एनआईपीएफपी-एलबीएसएनएए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवाकालीन मध्य-कैरियर अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 6 जनवरी 2023.

बैठकों और सम्मेलनों मे प्रतिभागिता/आयोजन

- भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी नियोजन पर आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। 11 अप्रैल 2022.
- एनआईपीएफपी तथा नीति अनुसंधान संस्थान, वित्त मंत्रालय, जापान सरकार के बीच संभावित सहयोग के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक का आयोजन किया। 12 अप्रैल 2022.
- एनआईपीएफपी में आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान एक व्याख्यान दिया। 13 मई 2022.
- नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 10वीं एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया समिति की पहली बैठक में भाग लिया। 17 मई 2022.
- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), नई दिल्ली में बिजली वितरण उपयोगिताओं की 10वीं एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए बिजली मंत्रालय द्वारा गठित समिति की प्रारंभिक बैठक में भाग लिया। 17 मई 2022.
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी की अध्यक्षता में प्रमुख नीति निर्माताओं के साथ आयोजित एक ऑनलाइन चर्चा में भाग लिया। 18 मई 2022.
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 10वीं एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया के लिए समिति की दूसरी बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। 25 मई 2022.
- भारत में धुआं रहित तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने की व्यवस्था पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए 'भारत में धुआं रहित तंबाकू उत्पादों पर कर' विषय पर एक आभासी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी मेजबानी इंडिया स्ट्रैटेजी ग्रुप और हम्मुराबी और सोलोमन पार्टनर्स द्वारा की गई थी। 29 मई 2022.
- नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 10वीं एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया। 30 मई 2022.
- भारतीय सतत विकास संस्थान (आईआईएसडी) तथा ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए सार्वजनिक समर्थन निजी निवेश कैसे जुटा सकता है?' विषय पर एक वेबिनार के लिए पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। 31 मई 2022.
- सातवें टोक्यो राजकोषीय फोरम में ऑनलाइन भाग लिया - जो आईएमएफ के राजकोषीय मामलों के विभाग; नीति अनुसंधान संस्थान, जापान के वित्त मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से राजकोषीय मुद्दों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन था। 22-23 जून 2022.

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान माला में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए व्याख्यान में भाग लिया। 8 जुलाई 2002.
- नई दिल्ली में एनसीएईआर द्वारा इंडिया पॉलिसी फोरम 2022 में 'भारत के सेवा क्षेत्र का विकास: गैर-व्यापार योग्य सेवाओं पर सेवा व्यापार का प्रभाव' विषय पर आयोजित सत्र 6 में भाग लिया। 13 जुलाई 2022.
- नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया। 20 जुलाई 2022.
- संस्थागत निवेशकों के लिए कॉल के संबंध में स्पार्क कैपिटल - थीमैटिक ग्रुप के साथ ऑनलाइन वार्तालाप किया। 26 जुलाई 2022.
- मुख्य रूप से एनआईपीएफपी की असाइनमेंट की समझ, ऐसे असाइनमेंट में विशेषज्ञता, पालन किए जाने वाले दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली और समयसीमा और बजट के साथ एक कार्य योजना को कवर करने के लिए प्रस्तुति के लिए परियोजना प्रस्ताव के संबंध में आर्थिक सलाहकार (ओजोन सेल), एमओईएफ और सीसी की अध्यक्षता में वर्चुअल प्रस्तुति पेश की। 10 अगस्त 2022.
- नीति भवन, नई दिल्ली में डॉ. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में वृहद और राजकोषीय स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक में भाग लिया। 11 अगस्त 2022.
- डॉ. ए.एन. झा, वरिष्ठ फेलो के नेतृत्व में राज्य वित्त पर काम करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने के लिए एनआईपीएफपी संकाय सदस्यों के साथ इन-हाउस बैठक। 11 अगस्त 2022.
- वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ 'इनपुट ऑन जीएसटी' पर एक वेबिनार में भाग लिया। 23 अगस्त 2022.
- गुलाटी इंस्टीट्यूट फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआईएफटी), तिरुवनंतपुरम, केरल द्वारा *स्टडीज इन इंडियन पब्लिक फाइनेंस* पुस्तक के विमोचन और लेखक प्रोफेसर एम. गोविंदा राव के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लिया। 23 अगस्त 2022.
- जब भारत नई दिल्ली में जी20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा था, तब जी20 सचिवालय द्वारा आयोजित विचार-मंथन सत्र में भाग लिया। 14 सितंबर 2022.
- नई दिल्ली में जर्मन एकता दिवस के अवसर पर जर्मनी संघीय गणराज्य के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लिया। 3 अक्टूबर 2022.
- नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित सीआईआई वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में 'भारत के विकास के वित्तपोषण के लिए उच्च कर राजस्व जुटाने' पर एक विशेष पैनल चर्चा में भाग लिया। 8 दिसंबर 2022.
- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), नई दिल्ली में बिजली वितरण उपयोगिताओं की 11वीं एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित समिति की प्रारंभिक बैठक में भाग लिया। 14 दिसंबर 2022.
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनफॉर्मिस्ट मीडिया (पूर्व में कॉर्जेसिस समाचार एजेंसी) को व्यक्तिगत रूप से बजट-पूर्व साक्षात्कार दिया। 20 जनवरी 2023.
- मिश्रा सेंटर फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमी (एमसीएफएमई), भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद द्वारा 'धीमे वैश्विक विकास के बीच नीतिगत प्राथमिकताएं और राजकोषीय चुनौतियां' विषय पर आयोजित बजट-पूर्व चर्चा वेबिनार में भाग लिया। 25 जनवरी 2023.
- पीटीआई के साथ बजट के बाद ऑनलाइन साक्षात्कार में भाग लिया। 1 फरवरी 2023.

- इकोनॉमिक्स क्लब, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ऑनलाइन पोस्ट-बजट पैनल चर्चा में भाग लिया। 2 फरवरी 2023.
- पुणे इंटरनेशनल सेंटर (पीआईसी), गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स (जीआईपीई), पुणे द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 पर आयोजित ऑनलाइन पैनल चर्चा में भाग लिया। 5 फरवरी 2023.
- 17वीं पांच संस्थान बजट संगोष्ठी 2023: 'अनपैकिंग द यूनियन बजट 2023-24' में पैनलविद के रूप में भाग लिया, जिसे पांच संस्थानों, अर्थात् सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ, एनसीएईआर और एनआईपीएफपी द्वारा संयुक्त रूप से एनसीएईआर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 6 फरवरी 2023.
- अमृता सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा बजट 2023 पर आयोजित एक ऑनलाइन संगोष्ठी में पैनलविद के रूप में आमंत्रित किया गया। 9 फरवरी 2023.
- नई दिल्ली में जर्मनी के संघीय गणराज्य के दूतावास द्वारा आयोजित भारत के साथ-साथ क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक विकास पर जर्मनी की राष्ट्रीय संसद की बजट समिति के सदस्यों और दिल्ली के थिंक टैंक के बीच दौर की चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 13 फरवरी 2023.
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), नई दिल्ली में इकोनॉमी एंड पॉलिसी इनिशिएटिव, अनंता सेंटर, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'केंद्रीय बजट 2023 और उससे आगे' विषय पर बजट उपरांत आयोजित सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। 16 फरवरी 2023.
- 11वीं एकीकृत रेटिंग के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित पीएफसी समिति की एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। 31 मार्च 2023.

सरकारी तथा अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय (एफसी एंड ईओडीबी डिवीजन), भारत सरकार द्वारा गठित पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नए शहरों के ऊष्मायन के लिए विशेषज्ञ समिति की सदस्य।
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 10वीं एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया के लिए समिति की सदस्य।
- राजकोषीय क्षमताओं और प्रबंधन को बढ़ाने पर छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग कार्यबल की सदस्य।
- तम्बाकू कराधान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पर विशेषज्ञ समूह की सदस्य।
- दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड की सदस्य।
- पीएच.डी. शोधप्रबंध के लिए बाह्य रेफर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- पीएच.डी. शोधप्रबंध के लिए बाह्य रेफरी, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता।

लेखा चक्रवर्ती

एनआईपीएफई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय और मौद्रिक नीति विश्लेषण' पर व्याख्यान दिया। 20-24 मार्च 2023.
- एनआईपीएफपी में आईसीएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जेंडर बजटिंग और मानव विकास' पर व्याख्यान दिया। 13-17 फरवरी 2023.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सरकारी अर्थशास्त्र और मानव विकास के वित्तपोषण' पर व्याख्यान दिया। 2-13 मई 2022.
- आईईएस, 2021 के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सरकारी अर्थशास्त्र और मानव विकास के वित्तपोषण: लिंग बजटिंग' पर व्याख्यान दिया। 2-7 मई 2022.
- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में 'महामारी के बीच मानव विकास का वित्तपोषण: लिंग बजटिंग' और 'राजकोषीय जोखिम और व्यापक आर्थिक अनिश्चितताएं' पर व्याख्यान दिया। 25-29 अप्रैल 2022.

आमंत्रित व्याख्यान

- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआईएफटी), तिरुवनंतपुरम में डॉक्टरेट अनुसंधान स्कॉलरों के लिए एक सत्र में 'लोक वित्त' पर व्याख्यान दिया। 9 फरवरी 2023.
- जीआईएफटी, तिरुवनंतपुरम के पीएच.डी स्कॉलरों के लिए 'सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति' पर एक व्याख्यान दिया। 7 फरवरी 2023.
- जीआईएफटी, तिरुवनंतपुरम के पीएच.डी स्कॉलरों के लिए 'घाटे के प्रभाव' पर एक व्याख्यान दिया। 6 फरवरी 2023.
- अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबटूर, तमिलनाडु में 'भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास की चुनौतियां' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में समापन भाषण दिया। 5 फरवरी 2023.
- केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के अर्थशास्त्र विभाग में 'राजकोषीय जोखिम, घाटा और व्यापक आर्थिक प्रभाव' पर एक व्याख्यान दिया। 5 जनवरी 2023.
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति: भारत में लिंग बजटिंग' पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 21 दिसंबर 2022.
- गोवा विश्वविद्यालय, गोवा द्वारा आयोजित अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में 'भूराजनीतिक अनिश्चितताओं पर आरबीआई की प्रतिक्रिया' पर एक व्याख्यान दिया। 14 नवंबर 2022.
- स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी में 'राजकोषीय जोखिम, अनिश्चितताएं और लिंग' पर एक व्याख्यान दिया। 11 नवंबर 2022.
- यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'मानव विकास के लिए राजकोषीय नवाचार, लिंग बजटिंग' पर एक व्याख्यान दिया। 7 नवंबर 2022.
- मानव संसाधन विकास (एचआरडीसी), गोवा विश्वविद्यालय में 'भारतीय अर्थव्यवस्था @ 75' पर आयोजित ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में दो व्याख्यान दिए। 1-14 नवंबर 2022.

- संयुक्त राष्ट्र महिला, एडीबी, भारत सरकार तथा जापान फंड फॉर प्रॉस्पेरस एंड रेजिलिएंट एशिया एंड द पैसिफिक (जेएफपीआर) द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों के एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जेंडर बजटिंग' पर सत्र के दौरान ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 2-4 नवंबर 2022.
- अर्थशास्त्र विभाग, नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय द्वारा आयोजित अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में 'सरकार का अर्थशास्त्र: सार्वजनिक सामान और सार्वजनिक विकल्प' पर एक व्याख्यान दिया। 19 अक्टूबर 2022.
- मार इवानियोस कॉलेज, तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम में 'ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड' पर व्याख्यान दिया। 18 अक्टूबर 2022.
- अर्थशास्त्र विभाग, सरकारी महिला कॉलेज, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति केंद्रीय बैंक की प्रतिक्रियाएँ' (भाग 1 और 2) पर व्याख्यान दिया। 18 अक्टूबर 2022.
- अर्थशास्त्र विभाग, नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में आयोजित कार्यक्रम में 'सतत मानव विकास के लिए राजकोषीय नीति' पर एक अतिथि व्याख्यान दिया। 13 अक्टूबर 2022.
- जिंदल सेंटर फॉर द ग्लोबल साउथ, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम में 'भूराजनीतिक अनिश्चितताओं के लिए सार्वजनिक नीति प्रतिक्रिया' पर एक अतिथि व्याख्यान दिया। 3 अक्टूबर 2022.
- महाराजा कॉलेज फॉर वुमेन, तिरुवनंतपुरम के अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए 'एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति' विषय पर एक व्याख्यान दिया। 22 सितंबर 2022.
- बंगाल इकोनॉमिक एसोसिएशन, कोलकाता द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'वैश्विक जोखिम और अनिश्चितताएं' पर एक विशेष व्याख्यान दिया। 29 जून 2022.
- विश्वनीडम सेंटर फॉर एशियन ब्लूमिंग, पुडुचेरी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन स्कूल में 'उम्र बढ़ने का अर्थशास्त्र: एकजुटता अर्थव्यवस्था' विषय पर व्याख्यान दिया। 10 जून 2022.
- अर्थशास्त्र विभाग, सेंट बर्चमैन्स कॉलेज, चंगनास्सेरी, केरल द्वारा 'बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए आर्थिक नीति प्रतिक्रिया' पर आयोजित अब्राहम मेमोरियल व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत सातवें वार्षिक प्रोफेसर सी.ओ. में ऑनलाइन व्याख्यान दिया। 24 मई 2022.
- राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 'आर्थिक सुधार के लिए व्यापक आर्थिक नीति' पर एक व्याख्यान दिया। 19 मई 2022.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- नई दिल्ली में सीईईडब्ल्यू इंडिया द्वारा 'कार्बन-मूल्य निर्धारण - निवल-शून्य रूपांतरण को सक्षम करना' विषय पर आयोजित एक पैनल में भाग लिया। 19 मार्च 2023.
- सेंटर फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन (सीईआरएसई) द्वारा आयोजित 'जेंडर बजटिंग 2023-24: चुनौतियां और भविष्य के रुझान' पर एक वर्चुअल पैनल चर्चा में भाग लिया। 8 मार्च 2023.
- जीआईएफटी, तिरुवनंतपुरम द्वारा केंद्रीय बजट 2023 पर आयोजित एक पैनल चर्चा में भाग लिया। 8 फरवरी 2023.
- इस्तांबुल, तुर्की में समावेशी विकास नीतियों और देखरेख में निवेश के माध्यम से महिलाओं के लिए सभ्य रोजगार को बढ़ावा देने पर आयोजित महिला-आईएलओ संयुक्त कार्यक्रम के तत्वावधान में 'राजकोषीय स्थान को बढ़ाना' विषय पर एक विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया। 26-27 जनवरी 2023.

- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना में इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी की 57वीं बैठक में 'बच्चों के प्रति अपराध को कम करने में लोक वित्तीय प्रबंधन की प्रभावशीलता' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 4-6 जनवरी 2023.
- हैदराबाद विश्वविद्यालय में इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी की 57वीं बैठक में 'उभरती अर्थव्यवस्था में पर्यावरण संघवाद' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 4-6 जनवरी 2023.
- ओडिशा राज्य सचिवालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में 'बाल संरक्षण सार्वजनिक व्यय समीक्षा और मूल्यांकन पर एनआईपीएफपी अध्ययन' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 22-23 फरवरी 2023.
- यूनिसेफ इंडिया, आईआईपीएस मुंबई तथा नीति आयोग द्वारा मुंबई में 'बाल विकास सूचकांक पद्धति फ्रेमवर्क समीक्षा' पर आयोजित तकनीकी कार्यशाला में भाग लिया। 14 दिसंबर 2022.
- नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएएसएनएए) तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के नेतृत्व में पोषण अभियान 'भारत में पोषण चुनौती से निपटना' विषय पर आईएएस अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नई दिल्ली में एक पैनल चर्चा में भाग लिया। 12-13 दिसंबर 2022.
- नई दिल्ली में टीईआरआई द्वारा आयोजित 'द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी) पहल: अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त प्रवचन के लिए इसका क्या अर्थ है?' विषय पर पैनल में विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया। 28 अक्टूबर 2022.
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के साथ संयुक्त राष्ट्र महिला भारत द्वारा 'जेंडर बजटिंग' पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन विशेष संबोधन दिया। 25 अगस्त 2022.
- एमिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलकाता द्वारा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में 'राजकोषीय नीति और असमानता: स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय लाभ घटना विश्लेषण' विषय पर व्याख्यान दिया। 3 अगस्त 2022.
- हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग और विकेंद्रीकृत शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के भाग के रूप में 'राजकोषीय समाजशास्त्र, राजकोषीय विकेंद्रीकरण और जेंडर बजटिंग की राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर चर्चा में भाग लिया। 17 मई 2022.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- प्रबंधन बोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ) के सदस्य।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) जर्नल अर्बन इंडिया के संपादकीय बोर्ड के सदस्य।
- कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी), कोच्चि के बोर्ड के सदस्य,
- इकोनोमेट्रिक सोसायटी, भारत के सदस्य।

सुप्रियो डे

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'नीति-आधारित राजकोषीय रणनीति' पर व्याख्यान दिया। 2 फरवरी 2023.
- आईसीएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'नीति-आधारित राजकोषीय रणनीति' पर व्याख्यान दिया। 14 फरवरी 2023.
- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'परिणाम बजट: अभ्यास और प्राथमिकताएं' और 'प्रदर्शन बजट: सिद्धांत और अवधारणाएं' पर दो व्याख्यान दिए। 30 अगस्त 2022.
- पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, विकास अध्ययन संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'नीति-आधारित राजकोषीय रणनीति' पर व्याख्यान दिया। 10 नवंबर 2022.
- ओल्ड गोवा, गोवा में गोवा राज्य सरकार, गोवा लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'नीति-आधारित राजकोषीय रणनीति' पर एक व्याख्यान दिया। 13 जनवरी 2023.
- एनआईपीएफपी में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में 'नीति-आधारित राजकोषीय रणनीति' पर एक व्याख्यान दिया। 21 मार्च 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- भारतीय लोक प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा (अप्रत्यक्ष कर) के लिए 'राजकोषीय नीति और विकास रणनीति' पर व्याख्यान दिया। 11 अक्टूबर 2022.
- राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में 'मैक्रोइकॉनॉमिक्स और राजकोषीय नीति' पर चार व्याख्यान दिए। 11-12 जनवरी 2023.
- एलबीएसएनएए, मसूरी में 'मैक्रोइकॉनॉमिक्स मॉड्यूल' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया और तीन व्याख्यान दिए । 11-14 अप्रैल 2023.
- मधुसूदन दास क्षेत्रीय वित्तीय प्रबंधन अकादमी (एमडीआरएएफएम)-आईएमएफ एसएआरटीटीएसी, भुवनेश्वर में 'राजकोषीय जोखिम' पर एक व्याख्यान दिया। 8-9 जनवरी 2023.
- नई दिल्ली में आईईएस परिविक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजित आईएमएफ एसएआरटीटीएसी पाठ्यक्रम में 'मैक्रोइकॉनॉमिक्स' पर चार व्याख्यान दिए। 6-9 फरवरी 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- चेन्नई में डॉ. सी. रंगराजन की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में 'भारत के समकालीन व्यापक आर्थिक विषय-वस्तु' विषय पर सम्मेलन में भाग लिया। 21-22 अप्रैल 2023.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जर्नल अर्बन इंडिया 2023 के संपादकीय बोर्ड के सदस्य।

प्रताप रंजन जेना

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 'राज्य स्तर पर राजस्व और व्यय का अनुमान और एमटीएफपी तैयार करना' पर व्याख्यान दिया। 26 अप्रैल 2022.
- आईईएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पीएफएम प्रदर्शन मापन फ्रेमवर्क' पर व्याख्यान दिया। 4 मई 2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही' पर व्याख्यान दिया। 11 मई 2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य स्तर पर बजट प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना' पर व्याख्यान दिया। 7 फरवरी 2023.
- 'लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दे और चुनौतियां' पर आईसीएएस परिवीक्षाधीनों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना' पर व्याख्यान दिया। 14 फरवरी, 2023.
- असम सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'उप-राष्ट्रीय सरकारी पीएफएम प्रदर्शन मूल्यांकन - एसएनजी पीईएफए' और 'राज्य स्तर पर राजस्व और व्यय का प्रक्षेपण' पर व्याख्यान दिया। 6-10 जून 2022.
- असम सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कार्य-निष्पादन/परिणाम बजट: अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सीखना' विषय पर व्याख्यान दिया। 30 अगस्त 2022.
- पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य स्तर पर बजट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना' और 'बजट प्रबंधन में प्रदर्शन अभिविन्यास - परिणाम बजट' पर व्याख्यान दिया। 10 नवंबर 2022.
- गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य स्तर पर बजट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना' और 'बजट प्रबंधन में प्रदर्शन अभिविन्यास - परिणाम बजट' पर व्याख्यान दिया। 11 जनवरी 2023.
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर लोक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में नवाचार: राज्यों का परिप्रेक्ष्य' पर व्याख्यान दिया। 20 मार्च 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस (आईएनजीएएफ), नई दिल्ली में लेखा महानियंत्रक (सीजीए), भारत सरकार के आईसीएएस अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'लोक व्यय और वित्तीय जवाबदेही' पर व्याख्यान दिया। 13 अप्रैल 2022.
- आईएनजीएएफ, सीजीए, नई दिल्ली में आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पीएफएम कार्य-निष्पादन मापन फ्रेमवर्क' पर व्याख्यान दिया। 18 जनवरी 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- सीजीए, नई दिल्ली में कैडर प्रशिक्षण योजना के नीति निर्माण, समन्वय और कार्यान्वयन व्यवस्था संबंधी समिति की बैठक में भाग लिया। 22 अगस्त 2022.
- रक्षा संपदा महानिदेशालय, नई दिल्ली में 'सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार (सीईओ/डीईओ)' श्रेणी के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 के नामांकित व्यक्तियों को अंतिम रूप देने पर आयोजित बैठक में भाग लिया। 14 नवंबर 2022.
- सेंटर फॉर पब्लिक फाइनेंस, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई, तमिलनाडु में 'सार्वजनिक वित्त मुद्दे' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएम) प्रणालियों में नवाचार: भारतीय अनुभव' पर परिचर्चा की। 20 जनवरी 2023.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों के सदस्यता

- कैडर प्रशिक्षण योजना सीजीए की नीति निर्माण, समन्वय और कार्यान्वयन व्यवस्था संबंधी समिति के सदस्य।
- सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार समिति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य।

मीता चौधरी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- आईईएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में सार्वजनिक नीति के मुद्दे' विषय पर व्याख्यान दिया। 5 मई 2022.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में सार्वजनिक नीति के मुद्दे' विषय पर व्याख्यान दिया। 10 मई 2022.
- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'परिणाम बजट: क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' पर व्याख्यान दिया। 1 सितंबर 2022.
- पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'परिणाम बजट: क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' पर व्याख्यान दिया। 11 नवंबर 2022.
- गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'परिणाम बजट: क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर व्याख्यान दिया। 12 जनवरी 2023.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण में सार्वजनिक नीति के मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 6 और 15 फरवरी 2023.
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर लोक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'परिणाम बजटिंग: क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' पर व्याख्यान दिया। 22 मार्च, 2023.

आमंत्रित व्याख्यान

- एम.एस. रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बेंगलुरु में 'भारत में हेल्थकेयर फाइनेंसिंग में सार्वजनिक नीति के मुद्दे' विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 28 फरवरी 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2018-19 संबंधी विशेषज्ञ समूह समिति की बैठक में भाग लिया और महत्वपूर्ण विचार प्रदान किए। 12 सितंबर 2022.
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2019-20 संबंधी विशेषज्ञ समूह समिति की बैठक में भाग लिया और महत्वपूर्ण विचार प्रदान किए। 13 फरवरी 2023.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 'सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर एबी-पीएमजेएवाई का वित्तीय प्रभाव' विषय पर आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया। 6 जनवरी 2023.
- एनसीएईआर, नई दिल्ली में पांच संस्थानों अर्थात् सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ, एनसीएईआर और एनआईपीएफपी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सत्रहवीं पांच संस्थान बजट संगोष्ठी 2023-24: 'केंद्रीय बजट 2023-24 का परिचय' में भाग लिया। 6 फरवरी 2023.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखाओं संबंधी विशेषज्ञ समूह के सदस्य।

सच्चिदानंद मुखर्जी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में 'लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर आईसीएएस परिवीक्षार्थियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में जीएसटी की उभरती चुनौतियां' पर एक व्याख्यान दिया। 14 फरवरी 2023.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कराधान और जीएसटी की थियोरी और सिद्धांत - राजस्व निहितार्थ और प्रदर्शन' पर दो व्याख्यान दिए। 30 जनवरी 2023.
- आईईएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) में उभरती चुनौतियां' पर व्याख्यान दिया। 5 मई 2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कराधान के थियोरी और सिद्धांत' तथा 'जीएसटी का परिचय: डिजाइन और संरचनात्मक मुद्दे' पर दो व्याख्यान दिए। 2 और 4 मई 2022.
- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में 'राज्य करों के लिए राजस्व प्रक्षेपण की पद्धति' विषय पर एक व्याख्यान दिया। 27 अप्रैल 2022.

आमंत्रित व्याख्यान

- कोलकाता में लोक वित्त और नीति प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में लोक वित्त और कराधान 2022 पर आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण कार्यशाला में 'भारत में जीएसटी के राजस्व निहितार्थ' विषय पर व्याख्यान दिया। 11 दिसंबर 2022.
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में विधान सभाओं के सदस्यों, पीआरएस विधायी अनुसंधान के लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य और राज्य वित्त पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में 'भारत में राज्य वित्त पर जीएसटी का प्रभाव' पर व्याख्यान दिया। 23 सितंबर 2022.

- सार्वजनिक नीति प्रबंधन में कार्यकारी स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम, भारतीय प्रबंधन संस्थान - कोझिकोड, केरल के लिए सार्वजनिक वित्त और नीति पर आठ व्याख्यान दिए। जून-जुलाई 2022.

एच.के. अमरनाथ

एनआईपीएफपी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में 'बजट डेटा पढ़ने में वर्गीकरण संबंधी मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 6-10 जून 2022.
- आईईएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बजट पढ़ना' और 'सब्सिडी: अर्थ, अनुमान और युक्तिकरण' पर दो व्याख्यान दिए। 2-7 मई 2022.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बजट पढ़ना' और 'सब्सिडी: अर्थ, अनुमान और युक्तिकरण' पर दो व्याख्यान दिए। 2-13 मई 2022.
- असम राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय स्थान और 'सब्सिडी के युक्तिकरण की आवश्यकता' पर दो व्याख्यान दिए। 6-10 जून 2022.
- पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय स्थान और 'बजट प्रबंधन में सब्सिडी के युक्तिकरण की आवश्यकता' पर दो व्याख्यान दिए। 10-12 नवंबर 2022.
- गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय स्थान और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता' पर व्याख्यान दिया। 11-13 जनवरी 2023.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बजट पढ़ना' और 'सब्सिडी: अर्थ, अनुमान और युक्तिकरण' पर दो व्याख्यान दिए। 30 जनवरी और 10 फरवरी 2023.
- आईसीएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय स्थान और सब्सिडी के युक्तिकरण की आवश्यकता' पर एक व्याख्यान दिया। 13-17 फरवरी 2023.
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राजकोषीय स्थान और सब्सिडी के युक्तिकरण की आवश्यकता' पर व्याख्यान दिया। 20-24 मार्च 2023.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के वित्तीय संसाधन संवर्धन और प्रबंधन कार्यबल के सदस्य।

रेणुका साने

आमंत्रित व्याख्यान

- गुरूग्राम में भारतीय विनियामक फोरम के सहयोग से स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ एंड मार्केट रेगुलेशन, आईआईसीए द्वारा रेगुलेटरी गवर्नेंस पर आयोजित तीन माह के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के चौथे बैच के दूसरे सत्र के दौरान 'सार्वजनिक नीति और विनियमन के अर्थशास्त्र' पर एक व्याख्यान दिया। 9 जुलाई 2022.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- ईपीएस-1995 के तहत लाभ बढ़ाने के संभावित उपाय सुझाने के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के कार्यबल की पहली बैठक में भाग लिया। 8 जून 2022.
- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के सहयोग से जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा सार्वजनिक व्यय के डिजिटलीकरण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। 10 जून 2022.
- नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से एस्या सेंटर द्वारा 'डेटा मार्केट में प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर रणनीतिक रोडमैप' की आवश्यकता पर आयोजित चर्चा में भाग लिया। 17 जून 2022.
- मुंबई में द्वार रिसर्च फाउंडेशन और एक्सकेडीआर फोरम द्वारा घरेलू वित्त पर आयोजित कार्यशाला में 'औपचारिक वित्त तक पहुंच के विस्तार में फिनटेक की भूमिका' पर पैनल चर्चा में भाग लिया। 25 जून 2022.
- तक्षशिला संस्थान द्वारा 'हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना की विवक्षाएं' विषय पर हाइब्रिड-मोड में आयोजित तक्षशिला सम्मेलन में भाग लिया। 20 जुलाई 2022.
- पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के कार्यबल की तीसरी बैठक में भाग लिया। 3 अगस्त 2022.
- गोवा में डॉ. जान्हवी नीलेकणि और नीलेकणि फिलैंथ्रोपीज के साथ साझेदारी में मर्कटस सेंटर के भारत में पहले नीति संवाद द्वारा आयोजित 'भारत के विचार: राजनीतिक अर्थव्यवस्था सम्मेलन' में भाग लिया। 16-19 अगस्त 2022.
- बीएमजीएफ द्वारा 'वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए नवाचारों की अगली लहर - भारत कैसे अवसर का लाभ उठा सकता है और उपयोग बढ़ा सकता है' विषय पर आयोजित अक्शा कार्यक्रम में भाग लिया। 13 सितंबर 2022.
- डेटा सुरक्षा आयोग की भूमिका' पर डेटा सुरक्षा विनियामकों के साथ मीडियानामा के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस प्राइवेसीनामा के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। 7 अक्टूबर 2022.
- नई दिल्ली में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के कार्यबल की चौथी बैठक में भाग लिया। 19 अक्टूबर 2022.
- द डायलॉग द्वारा आयोजित 'द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी' के वर्चुअल रिपोर्ट विमोचन में वक्ता के रूप में भाग लिया। 19 अक्टूबर 2022.
- क्रेडिट मार्केट पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और एनआईपीएफपी में 'फर्म फाइनेंसिंग का अवलोकन' सत्र में एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया। 3 नवंबर 2022.
- क्रेडिट मार्केट्स पर एनआईपीएफपी कार्यशाला में 'एकमात्र स्वामित्व और वित्तीय तनाव: भारत में दिवालियापन कानून के लिए विवक्षा' विषय में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। 4 नवंबर 2022.

- क्रेडिट मार्केट्स पर एनआईपीएफपी कार्यशाला में 'एकमात्र स्वामित्व और वित्तीय तनाव: भारत में दिवालियापन कानून के लिए निहितार्थ' विषय में वक्ता के रूप में भाग लिया। 4 नवंबर 2022.
- इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (आईएनईटी) और फ्लेम विश्वविद्यालय, पुणे द्वारा आयोजित विधि, अर्थशास्त्र और नीति सम्मेलन (एलईपीसी), 2022 के पांचवें संस्करण में 'घरेलू वित्त: कैसे और क्यों?' विषय पर चर्चा में एक पैनलविद के रूप में भाग लिया। 29 नवंबर 2022.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के कार्यबल के सदस्य।
- स्पेक्ट्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए स्पेक्ट्रम मूल्यांकन के तरीकों और साधनों का पता लगाने और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों का आकलन करने के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सदस्य।

मुकेश कुमार आनंद

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर लोक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'ओपीएस/एनपीएस और राज्य स्तर पर राजकोषीय प्रबंधन' विषय पर व्याख्यान दिया। 21 मार्च 2023.
- एनआईपीएफपी में 'लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दे और चुनौतियां' पर आईसीएएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'वृद्धावस्था पर सार्वजनिक व्यय' पर एक व्याख्यान दिया। 6 फरवरी 2023.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'वृद्धावस्था आय सहायता योजना पर सार्वजनिक व्यय और श्रम अर्थव्यवस्था से संबंधित राजकोषीय मुद्दों' पर एक व्याख्यान दिया। 6-10 फरवरी 2023.
- आईईएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में श्रम बाजार के मुद्दे' पर एक व्याख्यान दिया। 2-7 मई 2022.
- मौजूदा पेंशन प्रणाली, इसकी व्यापकता और सुधार के लिए संभावित मार्ग पर केंद्रित चर्चाओं में भाग लिया।
    - https://youtu.be/kNtIPI68Phw 15 दिसम्बर 2022.
    - https://youtu.be/5P05LY1EPeM 13 जनवरी 2023.
    - https://m.youtube.com/watch?v=dKynwH5p6z4 29 मार्च 2023.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- इंडियन इकॉनॉमिक जर्नल के लिए जर्नल रेफरी।

मनीष गुप्ता

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- ईआरडी अधिकारियों, बांग्लादेश के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्थानीय निकाय और राजकोषीय विकेंद्रीकरण' पर एक व्याख्यान दिया। 21 मार्च - 1 अप्रैल 2022.
- असम राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति: परिदृश्य और राजकोषीय पूर्वानुमान/अनुमान' पर आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में 'असम के वित्त की स्थिरता विश्लेषण' पर दो व्याख्यान दिए। 25-29 अप्रैल 2022.
- आईईएस (2021 बैच) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध' और 'स्थानीय निकायों के वित्त में मुद्दे' पर दो व्याख्यान दिए। 2-7 मई 2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्थानीय निकायों के वित्त में मुद्दे' और 'केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध' पर दो व्याख्यान दिए। 2-6 मई 2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्थानीय निकायों के वित्त में मुद्दे' पर एक व्याख्यान दिया। 30 जनवरी - 3 फरवरी 2023.
- 'सार्वजनिक वित्त और नीति में उभरते मुद्दे और चुनौतियां' पर आईसीएएस परिवीक्षाधीनों के लिए आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्थानीय सरकार के वित्त में मुद्दे' पर व्याख्यान दिया। 13-17 फरवरी 2023.
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्थानीय निकायों से संबंधित मुद्दे: शहरी और ग्रामीण' पर व्याख्यान दिया। 20-24 मार्च 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोगों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में 'दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और एसएफसी द्वारा संबोधित मुद्दे' पर तकनीकी सत्र में मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे। 29-30 नवंबर 2022.
- एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित 'भारतीय अर्थव्यवस्था की बजट-पूर्व समीक्षा' के दौरान 'राजकोषीय आउटलुक: केंद्र और राज्य सरकारें' पर प्रस्तुतिकरण पेश किया। 20 दिसंबर 2022.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- पंद्रहवें वित्त आयोग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नए शहरों के उद्भवन के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य।

रुद्राणी भट्टाचार्य

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में असम राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए 'राजकोषीय नीति: परिदृश्य और राजकोषीय पूर्वानुमान/अनुमान' पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के मॉड्यूल । में 'भारत के लिए वास्तविक समय में त्रैमासिक वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान के लिए एक रूपरेखा' पर व्याख्यान दिया। । 25 अप्रैल 2022.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भुगतान संतुलन' पर व्याख्यान दिया। 5 मई 2022.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में प्रमुख मूल्य सूचकांक' पर व्याख्यान दिया। 6 मई 2022.
- आईएएंडएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भुगतान संतुलन' पर एक व्याख्यान दिया। 1 फरवरी 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में आयोजित 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव पर सम्मेलन' में 'भारत में मुद्रास्फीति पर जीएसटी का प्रभाव' पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। 28-29 नवंबर 2022.
- एनआईपीएफपी में 'भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की प्री-बजट (वित्त वर्ष 2023-24) समीक्षा' में भारत के वास्तविक क्षेत्र, मुद्रास्फीति और बाहरी क्षेत्र की समीक्षा प्रस्तुत की। 20 दिसंबर 2022.
- नई दिल्ली में टाटा कैपिटल और आईडीओबीआरओ इम्पैक्ट सॉल्यूशंस के सहयोग से यूएसओ हाउस द्वारा आयोजित धनज्ञान (वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम) पर आठवीं-बारहवीं कक्षा के छात्रों की अंतिम प्रस्तुतियों के मूल्यांकन के लिए जूरी सदस्य के रूप में भाग लिया। 24 मार्च, 2023.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- इनके समीक्षक के रूप में आमंत्रित: कॉर्जेंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, आईआईएमबी मैनेजमेंट रिव्यू, इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, जर्नल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड, कॉर्जेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट और भारतीय रिजर्व बैंक डीईपीआर वर्किंग पेपर सीरीज।

सुकन्या बोस

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में आईसीएएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्कूल शिक्षा के सार्वजनिक वित्तपोषण: प्रमुख रुझान' पर एक व्याख्यान दिया। 16 फरवरी 2023.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शिक्षा का अधिकार: लेखापरीक्षा के लिए वित्तपोषण और परिप्रेक्ष्य' पर एक व्याख्यान दिया। 10 फरवरी 2023.

- 12 मई 2022 को IA&AS के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित सार्वजनिक वित्त पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शिक्षा के वित्तपोषण का अधिकार' और 'शिक्षा पर अंतर सरकारी हस्तांतरण' पर व्याख्यान दिया।
- आईईएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'स्कूल शिक्षा के सार्वजनिक वित्तपोषण: प्रमुख रुझान' पर एक व्याख्यान दिया। 6 मई 2022.
- बांग्लादेश सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बुनियादी शिक्षा और सार्वजनिक नीति' पर एक व्याख्यान दिया। 1 अप्रैल 2022.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- नेशनल कोएलिशन ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित 'स्कूल शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय: कोविड-19 द्वारा उजागर खामियां' विषय पर प्रस्तुतिकरण पेश किया और ऑनलाइन पैनल चर्चा में भाग लिया। 6 अगस्त 2022.
- उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली में 'एचईएफए के तृतीय पक्ष मूल्यांकन' पर एक प्रस्तुतिकरण पेश किया। 21 अक्टूबर 2022.
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस), तिरुवनंतपुरम में 'कॉन्फ्रेंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी' में 'सोशल स्पेंडिंग एंड मैक्रोइकोनॉमी: ए ले ऑफ द लैंडस्केप' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया। 28-30 नवंबर 2022.
- नई दिल्ली में 'नेशनल स्टॉकटेकिंग कन्वेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन फोरम' में पैनल चर्चा में भाग लिया। 22 नवंबर 2022.
- एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा 'एजुकेशन बजट: हिट्स एंड मिसेज' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में ऑनलाइन भाग लिया। 2 फरवरी 2023.
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 'लिंग-उत्तरदायी बजट' पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यशाला में 'स्कूल शिक्षा और लिंग बजट: कुछ प्रतिबिंब' पर ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण पेश किया। 22 दिसंबर 2022.
- राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली के अधिकारियों के लिए 'स्कूल शिक्षा बजट: अनुदान की मांग का विश्लेषण, 2023-24' पर एक प्रस्तुतिकरण पेश किया। 9 फरवरी 2023.

सरकार और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- न्यासी बोर्ड, सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रसार, भारत के सदस्य
- दिल्ली विश्वविद्यालय के बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग के छात्र के लिए पीएच.डी. पर्यवेक्षक।

अमेय सप्रे

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- आईईएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'आधिकारिक सांख्यिकी के मुद्दे' और 'छाया अर्थव्यवस्था, अवधारणाएं और मापन' पर दो व्याख्यान दिए। 4 मई 2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का परिचय' पर एक व्याख्यान दिया। 7 मई 2022.

आमंत्रित व्याख्यान

- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'ब्लू इकोनॉमी के आकलन के तरीके' विषय पर व्याख्यान दिया। 21 नवंबर 2022.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- आईएएस, चरण III, एलबीएसएनएए, मसूरी, उत्तराखंड के मध्य-कैरियर अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक वित्त पर एक व्याख्यान दिया। 2 जनवरी 2023.

सुरांजलि टंडन

आमंत्रित व्याख्यान

- राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी), नागपुर में 'मैक्रोइकॉनॉमिक्स' और 'टैक्स पॉलिसी' पर दो व्याख्यान दिए। 4 अप्रैल 2022.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूकेआईबीसी), लंदन द्वारा आयोजित 'यूके-इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर डेवलपमेंट्स' पर हाइब्रिड-मोड रेगुलेटर गोलमेज सम्मेलन में सह-संवक्ता के रूप में ऑनलाइन भाग लिया। 31 मार्च 2023.
- नई दिल्ली में आईजीएफ द्वारा 'विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर वैश्विक जलवायु वित्त प्रवाह को आगे बढ़ाना' विषय पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 27 मार्च 2023.
- नई दिल्ली में आई-फॉरेस्ट द्वारा आयोजित 'विशेषज्ञ गोलमेज सम्मेलन और कार्य समूह बैठक' में एक सत्र का संचालन किया। 24 मार्च 2023.
- उदयपुर, राजस्थान में जी-20 सतत वित्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। 21-22 मार्च 2023.
- नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में 'ब्रिक्स थिंक टैंक ब्रेकफास्ट - सतत विकास और विकास एजेंडा' में वक्ता के रूप में भाग लिया। 4 मार्च 2023.
- ग्रीन इन्वेस्टमेंट डायलॉग की मेजबानी तथा मैकआर्थर फाउंडेशन और थिया वेंचर्स के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित टी20 (थिंकट्वेंटी) साइड इवेंट में 'जी20 और जलवायु वित्त: भारत के हरित संक्रमण के लिए ग्रेटर इंटरनेशनल फाइनेंस को सक्षम करना' विषय पर मुंबई में गोलमेज सम्मेलन में वक्ता। 3 फरवरी 2023.
- एनआईपीएफपी में 'सतत वित्त' पर एक सम्मेलन की मेजबानी की। 10 फरवरी 2023.
- नई दिल्ली में ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ संयुक्त रूप से 'सस्टेनेबल फाइनेंस' पर टी20 कार्यक्रम की मेजबानी की। 10 फरवरी 2023.
- इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन (आईटीआरएएफ) द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्रचलित और उभरती दुविधाएं' विषय पर छठी पुस्तक विमोचन के अवसर पर ऑनलाइन 'वित्तीय नवाचारों से उत्पन्न कर चुनौतियां: एसपीएसी' प्रस्तुत पेश की। 16 दिसंबर 2022.
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) और इंटरनेशनल सीनियर लॉयर्स प्रोजेक्ट (आईएसएलपी) द्वारा 'वैश्विक न्यूनतम कर को कैसे समझें और अनुकूलित करें, इस पर विकासशील देशों के लिए एक गाइड' के ऑनलाइन विमोचन के अवसर पर वक्ता। 15 दिसंबर 2022.

- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (यूनाइटेड किंगडम), यूनिवर्सिटी ऑफ लौवेन (बेल्जियम), यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), यूरोपीय अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित ग्लोबटैक्सगॉव प्रोजेक्ट के सहयोग से लीडेन यूनिवर्सिटी (नीदरलैंड्स) और मुंस्टर विश्वविद्यालय (जर्मनी) द्वारा संचालित ऑनलाइन ग्लोबल टैक्स संगोष्ठी की मेजबानी की। 1-2 दिसंबर 2022.
- कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर (सीएटीए) के 42वें तकनीकी सम्मेलन के 'डिजिटलीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियां' विषय पर आयोजित सत्र 4 में पैनलविद के रूप में भाग लिया। 29 नवंबर 2022.
- शर्म अल शेख, मिस्र में एफईपीएस और ओआरएफ द्वारा 'कॉप-27 - ग्लोबल जस्ट ट्रांज़िशन का वित्तपोषण तथा विस्तृत और उच्च-स्तरीय दृष्टिकोणों के संयोजन की आवश्यकता' तथा एचएसबीसी, एक्सेंचर, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूजीईओ) और यूएनएफसीसीसी द्वारा 'उभरते बाजारों में जस्ट ट्रांज़िशन' पर साइड इवेंट में भागीदारी। 8-9 नवंबर 2022.
- ईडीएफआई और ऑकुटस ईएसजी द्वारा आयोजित ग्लोबल डीएफआई फोरम 2022 में 'सभी के लिए सुरक्षित पर्यावरण के लिए युवा एकजुट हों' विषय पर पैनल चर्चा में ऑनलाइन भाग लिया। 3 नवंबर 2022.
- ई-सीईपीआर ई-बुक स्केलिंग अप सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन द ग्लोबल साउथ (संपा. उलरिच वोल्ज़ और डिर्क शॉनमेकर) के ऑनलाइन विमोचन के अवसर पर वक्ता। 3 नवंबर 2022.
- यूएनसीटीएडी डब्ल्यूआईआर के विशेष विषय अध्याय पर आयोजित वेबिनार में एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया। 30 सितंबर 2022.
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) - सतत वित्त समिति की बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। 3 अक्टूबर 2022.
- दिल्ली एनसीआर के सिरिल अमरचंद मंगलदास द्वारा आयोजित 'ग्रीन फाइनेंस पर यूकेआईबीसी गोलमेज सम्मेलन' में वक्ता। 21 सितंबर 2022.
- एनएडीटी, बेंगलुरु में 'भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद' पर वर्चुअल कार्य प्रस्तुत किया। 16 सितंबर 2022.
- 'डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान' पर एटीएआईसी और सीएटीए द्वारा आयोजित वेबिनार में 'वैश्विक कर सुधार की आवश्यकता' पर कार्य प्रस्तुत किया। 30 अगस्त 2022.
- टैक्ससूत्र द्वारा आयोजित वेबिनार में 'कोविड-19 संकट के बाद कर और राजकोषीय नीति' पर कार्य प्रस्तुत किया। 16 अगस्त 2022.
- क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा 'ग्रीन फाइनेंस लैंडस्केप रिपोर्ट' के विमोचन के अवसर पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा में भाग लिया। 10 अगस्त 2022.
- ऑक्टस ईएसजी द्वारा आयोजित 'यूक्रेन के लिए स्थिरता (एस4यू) फाइनेंसिंग ए जस्ट ट्रांजिशन: ए फोकस ऑन यूक्रेन' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। 22 जून 2022.
- हरियाणा के मानेसर में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा 'ईएसजी को मजबूत करने की दिशा में प्रभावशाली सीएसआर' पर आयोजित एक पैनल चर्चा में वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। 12 जून 2022.
- मेलबर्न लॉ स्कूल और ग्लोबल टैक्स सिम्पोजियम ऑनलाइन सेमिनार में 'इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म - पिलर टू' पर प्रस्तुति पेश की। 6 जून 2022.
- प्रकटीकरण पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में ऑनलाइन आईएफएससीए - सतत वित्त विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। 21 मई 2022.

- नई दिल्ली में इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन द्वारा 'महामारी के बाद उभरते अंतर्राष्ट्रीय कराधान परिदृश्य' पर आयोजित सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय कर के नीतिगत आयाम - क्या स्तंभ-दो भारत के लिए एक व्यवहार्य समाधान है?' विषयक सत्र में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। 30 अप्रैल 2022.
- एक्सिस कैपिटल इंडिया ईएसजी कॉन्फ्रेंस ईएसजी - प्वाइंट ब्लैंक' में 'जस्ट ट्रांजिशन इन इंडिया' पर ऑनलाइन वार्ता संचालित की। 7 अप्रैल 2022.
- ईडीएफआई और ऑक्टस ईएसजी द्वारा आयोजित 'फाइनेंसिंग नेट जीरो: उभरते बाजारों में डीएफआई पर फोकस' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया। 1 अप्रैल 2022.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- ओला मोबिलिटी इंस्टिट्यूट के ईज़ ऑफ मोबिलिटी इंडेक्स विकसित करने के लिए सलाहकार दल, 2022 के सदस्य।

रॉली कुकरेजा

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा आयोजित 'एबी पीएम-जेएवाई के तहत प्रदाता भुगतान और मूल्य निर्धारण' पर पत्र के लिए वर्चुअल हितधारक परामर्श के भाग के रूप में आयोजित वेबिनार में भाग लिया। 26 अप्रैल 2022.
- एनएचए द्वारा आयोजित 'वॉल्यूम-आधारित से मूल्य-आधारित देखभाल: एबी पीएम-जेएवाई के तहत बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना' पर पत्र के लिए वर्चुअल हितधारक परामर्श के भाग के रूप में आयोजित वेबिनार में भाग लिया। 15 जुलाई 2022.
- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) द्वारा 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्वास्थ्य बीमा में स्वास्थ्य प्रणाली संवाद: स्वास्थ्य सेवाओं की पुष्टि के एकीकरण के लिए कारकों को सक्षम और नियंत्रित करना' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। 22 अगस्त 2022.
- फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे में 'राजनेता आपराधिकता और उच्च शिक्षा संस्थान' विषय पर पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। 29 अगस्त 2022.

प्रियाली दास

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'ऋण स्थिरता के परिप्रेक्ष्य' पर एक व्याख्यान दिया। 9 फरवरी 2023.
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन' पर व्याख्यान दिया। 24 मार्च 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नई दिल्ली में नौवीं दिल्ली मैक्रोइकॉनॉमिक्स कार्यशाला में भाग लिया। 16-17 मार्च 2023.

मालविका महेश

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- एनआईपीएफपी में 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव' विषय पर एक सम्मेलन में भाग लिया। 28-29 नवंबर 2022.
- नई दिल्ली में विश्व बैंक द्वारा आयोजित स्त्री संवाद: 'प्रगतिशील कानून, प्रतिगामी प्रथाएं: भारत में लिंग, भूमि और उत्पादकता' पर बीना अग्रवाल की एक वार्ता में भाग लिया। 15 फरवरी 2023.

दिनेश कुमार नायक

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'राज्य वित्त में सर्वोत्तम प्रथाओं' पर व्याख्यान दिया। 22 मार्च 2023.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- आईएमएफ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र, नई दिल्ली तथा क्षमता विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित मौद्रिक नीति कार्यान्वयन: विदेशी मुद्रा संचालन पर पाठ्यक्रम में भाग लिया। 10-12 जनवरी 2023.
- देहरादून, उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय द्वारा 'विकास अनुभव और सतत विकास के वित्तपोषण' पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'उत्तराखंड राज्य वित्त पर राजकोषीय निदान और जोखिम विश्लेषण' पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। 24 सितंबर 2022.
- मुंबई में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च (आईजीआईडीआर) द्वारा इकोनोमेट्रिक्स एंड मशीन लर्निंग पर आयोजित समर स्कूल में भाग लिया। 6-10 सितंबर 2022.
- जोहान्स केप्लर यूनिवर्सिटी (जेकेयू), लिंज़, ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ) सम्मेलन की 78वीं वार्षिक कांग्रेस में 'भारतीय उप-राष्ट्रीय स्तर पर आय और सरकारी व्यय के बीच संबंध: दूसरी पीढ़ी के पैनल सह-एकीकरण तकनीक' पर ऑनलाइन पत्र (भाबेश हजारिका के साथ) प्रस्तुत किया। । 10-12 अगस्त 2022.
- ऐक्स-मार्सिले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एएमएसई), मार्सिले, फ्रांस में सार्वजनिक अर्थशास्त्र में 21वें जर्नल्स एलएजीवी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'राजकोषीय भ्रम और फ्लाईपेपर प्रभाव: भारतीय उप-राष्ट्रीय वित्त से साक्ष्य' पर ऑनलाइन पत्र (भाबेश हजारिका के साथ) प्रस्तुत किया। 6-8 जून 2022.
- ऐक्स-मार्सिले स्कूल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स (एएमएसई), मार्सिले, फ्रांस में 21वीं जर्नीज़ एलएजीवी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 'दूसरी पीढ़ी के पैनल सह-एकीकरण तकनीकों का उपयोग करके भारतीय उप-राष्ट्रीय के लिए वैगनर के कानून की वैधता की पुन: जांच' पर ऑनलाइन पत्र (भाबेश हजारिका के साथ) प्रस्तुत किया गया। 6-8 जून 2022.

सरकारी और अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी (एआईबी), 2022 के सदस्य।
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ), 2022 के सदस्य।
- कार्य समूह के सदस्य, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़, 2022.

श्री हरी नायडु ए.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटिजनशिप (वाईएलएसी) द्वारा '2019 से आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त का विश्लेषण' विषय पर आयोजित एक पैनल चर्चा में भाग लिया। 29 अप्रैल 2022.
- एनसीएईआर, नई दिल्ली में सत्रहववीं पांच संस्थान बजट संगोष्ठी 2023 में भाग लिया। 6 फरवरी 2023.
- पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'जीएसटी ऑडिट - करदाताओं का परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया। 19 अप्रैल 2022.
- सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी) द्वारा 'आरबीआई राज्य वित्त रिपोर्ट' पर आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया। 28 जून 2022.

सरकारी और अन्य निकायो/जर्नलों की सदस्यता

- जर्नल ऑफ मिलेनिया एशिया, सेज पब्लिकेशन के समीक्षाकार।

भाबेश हजारिका

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक निवेश प्रबंधन' पर व्याख्यान दिया। 24 मार्च 2023.
- गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (जीआईपीएआरडी), ओल्ड गोवा में गोवा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सार्वजनिक निवेश प्रबंधन' पर एक व्याख्यान दिया। 11 जनवरी 2023.
- इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, कोलकाता (आईडीएसके) में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए बजट प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया। 12 नवंबर 2022.

बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- गारगांव कॉलेज, असम द्वारा आयोजित एक वेबिनार में 'केंद्रीय बजट 2023-24: एक विश्लेषण' पर एक व्याख्यान दिया। 6 मार्च 2023.
- नई दिल्ली में आईएमएफ एसएआरटीटीएसी और आईसीडी द्वारा आयोजित 'आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए जलवायु परिवर्तन संकेतकों का परिचय' विषय पर पाठ्यक्रम में भाग लिया। 10-12 जनवरी 2023.

- 'भारतीय उप-राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक व्यय, शासन और मृत्यु दर संभावना: दो-स्तरीय मिश्रित प्रभाव विश्लेषण' पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया।
    - मुंबई में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर) द्वारा 'विकास: कई वैश्विक झटकों के बीच सतत विकास लक्ष्य: प्रगति, चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर आयोजित दूसरे द्विवार्षिक सम्मेलन में। 21-23 दिसंबर 2022.
    - त्रिपुरा में त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 23वें उत्तर पूर्वी आर्थिक संघ सम्मेलन में। 17-19 नवंबर 2022.
- नई दिल्ली में आईएमएफ एसएआरआईटीएसी और इंस्टीट्यूट फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट (आईसीडी) द्वारा प्रस्तावित 'मौद्रिक नीति कार्यान्वयन: विदेशी मुद्रा संचालन' पर एक पाठ्यक्रम में भाग लिया। 31 अक्टूबर - 3 नवंबर 2022.
- लिंज़, ऑस्ट्रिया में जोहान्स केपलर विश्वविद्यालय (जेकेयू) द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ) सम्मेलन की 78वीं वार्षिक कांग्रेस में 'भारतीय उप-राष्ट्रीय स्तर पर आय और सरकारी व्यय के बीच संबंध: एक दूसरी पीढ़ी के पैनल सह-एकीकरण तकनीक' विषय पर (दिनेश कुमार नायक के साथ - ऑनलाइन) पत्र प्रस्तुत किया। 10-12 अगस्त 2022.
- मार्सिले, फ़्रांस में ऐक्स-मार्सिले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एएमएसई) में सार्वजनिक अर्थशास्त्र में 21वें जर्नल्स एलएजीवी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'राजकोषीय भ्रम और फ्लाईपेपर प्रभाव: भारतीय उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्त से साक्ष्य' (दिनेश कुमार नायक के साथ - ऑनलाइन) विषय पर पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया। 6-8 जून 2022.
- एक्स-मार्सिले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एएमएसई), मार्सिले, फ्रांस में सार्वजनिक अर्थशास्त्र, में 21वीं जर्नीज़ एलएजीवी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'दूसरी पीढ़ी के पैनल सह-एकीकरण तकनीकों का उपयोग करके भारतीय उप-राष्ट्रीय के लिए वैगनर के कानून की वैधता की पुन: जांच' विषय पर (दिनेश कुमार नायक के साथ - ऑनलाइन) ऑनलाइन पत्र प्रस्तुत किया। 6-8 जून 2022.

सरकारी तथा अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस (एआईबी) के वार्षिक सदस्य।
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ) के वार्षिक सदस्य।
- नॉर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक एसोसिएशन (एनईईए) के आजीवन सदस्य।

अमनदीप कौर

बैठकों/सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- लिंज़, ऑस्ट्रिया में आईआईपीएफ की 78वीं वार्षिक कांग्रेस में 'उभरती अर्थव्यवस्था में पर्यावरण संघवाद: एक अनुभवजन्य विश्लेषण' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 10-12 अगस्त 2022.
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी (टीआईईएस) के 57वें वार्षिक सम्मेलन में 'उभरती अर्थव्यवस्था में पर्यावरण संघवाद: एक अनुभवजन्य विश्लेषण' पर एक पत्र प्रस्तुत किया। 4-6 जनवरी 2023.
- नई दिल्ली में राष्ट्रीय लिंग एवं बाल केंद्र, एलबीएसएनएए, मसूरी द्वारा 'पोषण अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में पोषण चुनौती से निपटना' विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर दो-दिवसीय परामर्श कार्यशाला में भाग लिया। 12-13 दिसंबर 2022.

सरकारी तथा अन्य निकायों/जर्नलों में सदस्यता

- इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जर्मनी की सदस्य।

राधिका पांडे

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त और प्रबंधन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'वित्तीय समावेशन' पर व्याख्यान दिया। 24 मार्च 2023.
- आईसीएएस परिवीक्षार्थियों के लिए 'सार्वजनिक वित्त और नीति में उभरते मुद्दे और चुनौतियां' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार' पर व्याख्यान दिया। 13 फरवरी 2023.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मूल्य सूचकांक की मूल बातें' पर एक व्याख्यान दिया। 3 फरवरी 2023.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'धन की मांग और आपूर्ति' पर एक व्याख्यान दिया। 31 जनवरी 2023.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मैक्रो: वित्तीय बाजार' पर एक व्याख्यान दिया। 5 मई 2022.
- आईए एंड एएस के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक वित्त पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मैक्रो: धन की मांग और आपूर्ति' पर एक व्याख्यान दिया। 4 मई 2022.

आमंत्रित व्याख्यान

- अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पर संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम के लिए दो ऑनलाइन व्याख्यान दिए:
  1. 'सरकारी बांड बाजार और विनियामक ढांचे की संरचना और प्रचालन' पर व्याख्यान, 28 अगस्त 2022.
  2. 'भारत का कार्पोरेट बांड बाजार : संरचना और विनियामक ढांचा' पर व्याख्यान, 4 सितम्बर 2022.

बैठकों/सम्मेलनों में प्रतिभागिता/आयोजन

- आसियान इंडिया पार्टनरशिप ऑफ थिंक टैंक (एआईएनटीटी) के लिए क्षेत्रीय सहयोग एजेंडा पर आसियान-भारत नेटवर्क के सातवें गोलमेज सम्मेलन के दौरान 'आर्थिक और सतत पुनर्प्राप्ति' सत्र में भाग लिया। 12 मई 2022.
- इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएमपीआरआई) द्वारा केंद्रीय बजट पर आयोजित एक ऑनलाइन पैनल चर्चा में भाग लिया। 6 फरवरी 2023.
- अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा केंद्रीय बजट पर आयोजित एक ऑनलाइन पैनल चर्चा में भाग लिया। 20 फरवरी 2023.

अनुबंध

अनुबंध I: अध्ययनों की सूची 2022–23

पूर्ण अध्ययन

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
1	भारत के पहले राष्ट्रीय अनुकूलन संचार के लिए कॉप-27 और सार्वजनिक व्यय (अप्रैल 2022 – दिसम्बर 2022)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	लेखा चक्रवर्ती, अजय नारायण झा, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बालामुरली बी.
2	आंध्र प्रदेश राज्य के राजस्व पर जीएसटी मुआवजे की वापसी का प्रभाव (जनवरी 2022 – मई, 2022)	वाणिज्यिक कर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	प्रताप रंजन जेना, दिनेश कुमार नायक, भाबेश हजारिका और श्री हरि नायडू ए.
3	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई): डिजाइन रूपरेखा, उभरते पैटर्न और सरकार की लागत (नबम्बर 2022)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए)	मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता
4	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी की तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा (जुलाई 2022 – जनवरी 2023)	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	आर. कविता राव, सुकन्या बोस और गौरव
5	वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय केंद्र, उत्तराखंड सरकार, देहरादून को अनुसंधान और परामर्श सहायता (अगस्त 2021 - जुलाई 2022)	उत्तराखंड सरकार	प्रताप रंजन जेना, दिनेश नायक और भाबेश हजारिका
6	सिक्किम के लिए मध्यम अवधि योजना: 2022-23 से 2024-25 (अप्रैल-मई 2022)	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना
7	वर्ष 2019-20 के लिए सिक्किम सरकार द्वारा राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा (जनवरी-मई 2022)	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
8	पुडुचेरी के जीएसडीपी के आकलन के स्रोत और पद्यतियां: तृतीय पक्षकार आकलन (अप्रैल-दिसम्बर 2022)	पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सरकार	अमेय सप्रे और वैशाली भारद्वाज

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
9	राष्ट्रीय अनुकूलन संचार - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार (जून 2022)	कोई वित्तपोषण नहीं (एमओएफईसीसी)	अजय नारायण झा, लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर
10	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शिता लेखापरीक्षा (जून-दिसम्बर 2022)	केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी भदोला
11	भारतीय लोक सेवा सांख्यिकी (आईपीएफएस) के लिए नियमावली तैयार करना (8 जुलाई 2022)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	अमरनाथ एच.के, श्री हरी नायडु और रोहित दत्ता
12	वित्तीय आस्तियों से आय का कराधान (अगस्त-दिसम्बर 2022)	सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय	सुप्रियो डे, प्राची जैन, अदम हुसैन, नीति गुप्ता और आलोकिता बासु
13	क्रिप्टो करेंसी पर दस्तावेज/रिपोर्टें/ टिप्पणियां (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल
14	यूएस बैंक कोलैप्सेज़ और क्रिप्टो एडॉप्शन पर टिप्पणियां (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल
15	'क्रिप्टो चुनौती का संवाहन : भारत और जी20' पर चर्चा (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल
16	भारत में बैंकिंग क्षेत्र के आकार और आकार में वृद्धि के उपायों पर टिप्पणियां (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल
17	भारत के लिए वित्तीय तनाव संकेतकों पर टिप्पणी (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल
18	भारत में कुटुंब दायित्व : विहंगावलोकन (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
19	एआईआईबी की ऊर्जा क्षेत्र भागीदारी: तकनीकी सहायता और निजी पूंजी जुटाने पर एक करीबी नजर पर टिप्पणी (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल
20	जी-20 अनुसंधान सहयोग : वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन के लिए प्रस्तुति (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	राधिका पांडे और डीईए दल
21	वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त डेटा का अद्यतनीकरण (15 जनवरी - 1 मई 2022)	एनआईपीएफपी	अमरनाथ एच.के, श्री हरी नायडु और रोहित दत्ता
22	राष्ट्रीय लेखाओं में स्थिति और संकलन मुद्दे (जनवरी-अप्रैल 2023)	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	अमेय दत्ता और वैशाली भारद्वाज
23	ओडिशा में बाल संरक्षण पर सार्वजनिक व्यय की समीक्षा और मूल्यांकन (अप्रैल 2022 - अप्रैल 2023)	यूनिसेफ	लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बालामूर्ति बी.
24	पीएमईएसी -2023 भारतीय अर्थव्यवस्था पर त्रैमासिक रिपोर्ट: ईएसी-पीएम के लिए टिप्पणी - वर्ष के दौरान पीएमईएसी के लिए चार त्रैमासिक रिपोर्टें पूरी की गईं (अप्रैल 2022 – मार्च 2023)	ईएसी-पीएम	आर. कविता राव. लेखा चक्रवर्ती, सुप्रियो डे, मनीष गुप्ता, रुद्राणी भट्टाचार्य, दिनेश कुमार नायक और राधिका पांडे
25	जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन ने भारत में मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित किया? (नवम्बर 2022 – फरवरी 2023)	एनआईपीएफपी	रुद्राणी भट्टाचार्य
26	केंद्र सरकार के राजस्व, व्यय, घाटे और ऋण का अनुमान (1 सितम्बर - 10 अक्तूबर 2022)	ईएसी-पीएम	सुप्रियो डे, मनीष गुप्ता, आदम हुसैन और साक्षी राठी
27	प्रत्यक्ष कर मुकदमेबाजी प्रबंधन और वैकल्पिक विवाद समाधान (1 अगस्त – 26 मार्च, 2023)	ईएसी-पीएम	सुप्रियो डे, प्राची जैन, मयूराक्षी सिन्हा, नीति गुप्ता और आलोकिता बासु

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
28	शिक्षा वित्तपोषण पर कोविड का प्रभाव (अक्तूबर 2021 – जुलाई 2022)	नेशनल कोइलेशन फॉर एजुकेशन	सुकन्या बोस और हर्षिता शर्मा (नेशनल कोइलेशन फॉर एजुकेशन)
29	असम उप-राष्ट्रीय राजकोषीय संधारणीयता विश्लेषण और राजकोषीय जोखिम (अप्रैल-जून 2022)	विश्व बैंक, नई दिल्ली	मनीष गुप्ता और सोनल अग्रवाल
30	एसडीजी के लिए वित्तपोषण में तेजी लाने/उप-राष्ट्रीय सरकारों के लिए एसडीजी के लिए राजकोषीय स्थान बढ़ाने के लिए उप-राष्ट्रीय कार्रवाइयों पर अध्ययन (सितम्बर-नवम्बर 2022)	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	सुरांजलि टंडन और अर्चिता श्रीधर
31	सीजीटीएमएसई के लिए गारंटी योजनाओं हेतु डेटा एनालिटिक्स (मई 2022)	सूक्ष्म और लघु उदयमो के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीआईएमएसई)	रेणुका साने, अनन्या गोयल और मिथिला ए. साराह
32	जीआरएम तंत्र का आधारभूत अध्ययन (भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल) (नवम्बर 2021 - सितम्बर 2022)	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	रेणुका साने, श्रष्टि शर्मा, ऐश्वर्या गवली और स्मृति पर्शीरा
33	वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकारों के डेटा बैंक, वित्त का अद्यतनीकरण (नवम्बर 2022)	एनआईपीएफपी	अमरनाथ एच.के. और रोहित दत्ता

चल रहे अध्ययन

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
1	चयनित राज्यों में स्पष्ट आर्थिक सहायताओं का प्राक्कलन (जुलाई 2022 - मार्च 2023)	नीति आयोग	अमरनाथ एच.के., श्री हरी नायडु ए. और मिताली गुरुदत्त
2	वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा (फरवरी 2022 - जुलाई 2023)	मध्य प्रदेश सरकार	प्रताप रंजन जेना, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे
3	वर्ष 2020-21 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों के सिक्किम सरकार द्वारा अनुपालन की समीक्षा (जनवरी 2022 – मई 2023)	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे
4	लोक वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय सरकारी वित्त पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना (जुलाई 2021 – जुलाई 2023)	पंडित दीन दयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (पीडीयू-सीटीआरएफए), उत्तराखंड सरकार	प्रताप रंजन जेना और मनीष गुप्ता
5	भारत में किगाली संशोधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे और रणनीति का विकास (6 सितम्बर 2022 - 20 जुलाई 2023)	ओज़ोन प्रकोष्ठ, एमओईएफएंडसीसी	सुरांजलि टंडन, अर्चिता श्रीधर, रिद्धि वर्मा और ज्योत्स्ना चिक्खरा
6	एमओएचयूए-एनआईपीएफपी अनुसंधान कार्यक्रम (नवम्बर 2022)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	आर. कविता राव, मनीष गुप्ता, अमेय सप्रे, आकाश गुप्ता, नीति गुप्ता, सिराज येज़दानी और सौम्या अग्रवाल
7	भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक के रखरखाव हेतु नीति निर्माण को सक्षम करने के लिए इनपुट प्रदान करना (अक्तूबर 2021 – अक्तूबर 2022)	केंद्रीय कार्यशाला आधुनिकीकरण संगठन (रेल)	रेणुका साने, मार्गी पांड्या, नैंसी गुप्ता और अमृता पिल्लई

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
8	वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए भारत सरकार का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण (ईएफसी) बजट (अक्तूबरr 2022 – अक्तूबर 2023)	वित्त मंत्रालय	अमरनाथ एच.के., श्री हरी नायडु ए., आशीष राज और रोहित दता
9	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शी लेखापरीक्षा (जून 2023 - दिसम्बर 2023)	केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
10	राज्यों के अपने कर राजस्व और अपने गैर-कर राजस्व का राज्य-स्तरीय विश्लेषण (अप्रैल 2022 -)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	दिनेश कुमार नायक और भाबेश हज़ारिका
11	एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, आशिम कपूर, रितिका सिंह, सिमरन कौर, उत्सव सक्सेना, कीर्ति वट्टल, राम्या आर. कुमार और अनुराधा गुप्ता
12	क्रिप्टोकरेंसी पर मासिक रिपोर्ट (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल
13	क्रिप्टोकरेंसी के लिए डैशबोर्ड (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल
14	सीबीडीसी पर मासिक रिपोर्ट (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल
15	वित्तीय स्थायित्व पर मासिक रिपोर्ट (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल
16	मैक्रो-डैशबोर्ड: वित्तीय बाजारों में उभरते तनाव को रखने वाले संकेतकों का दृश्य प्रतिनिधित्व (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
17	सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समीक्षा बैठकों के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुतिकरण और टिप्पणियां (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल
18	वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण और निवारण एजेंसी पर टिप्पणिया6 और मसौदा विधान (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल
19	एआईआईबी, आईबीआरडी, एडीबी और आईएफसी पर ध्यान-केंद्रण के साथ एमडीबी और आईएफआई द्वारा एलसीएफ पर टिप्पणी (अप्रैल 2022 - मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, राधिका पांडे और डीईए दल
20	डीईए-एनआईपीएफपी अनुसंधान कार्यक्रम (दिसम्बर 2022 – दिसम्बर 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, मुकेश कुमार आनंद और पुल्किट कुमार शर्मा
21	पूंजीगत व्यय पर डीईए परियोजना (जनवरी 2022 – अगस्त 2023)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रताप रंजन जेना, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे
22	वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन - जी-20 पत्र (1 अक्तूबर 2022 -15 जून 2023)	मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय	सुप्रिया डे, राधिका पांडे, प्रमोद सिन्हा, कीर्ति विट्टल, रचना शर्मा और वी. राम्या
23	पुरानी पेंशन योजना पर सार्वजनिक व्यय को सीमित करने और वृद्धावस्था आय सहायता प्रणाली में श्रमिक समावेशन को व्यापक बनाने के लिए सुधार	स्व-प्रारंभित	मुकेश कुमार आनंद
24	सार्वजनिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण	स्व-प्रारंभित	मुकेश कुमार आनंद
25	सीपीआई मंहगाई को कौन संचालित करता है? (समाप्ति की संभावित तारीख अगस्त 2023)	स्व-प्रारंभित	अमेय सप्रे, राधिका पांडे और प्रमोद सिन्हा
26	राजवित्तीय संघवाद और लिंग समानता (जनवरी 2021 – दिसम्बर 2023)	फोरम ऑफ फेडेरेशंस, ओटावा	लेखा चक्रवर्ती और दिव्य रंगन (जून 2021 तक कार्य किया)

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
27	चयनित राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तपोषण (जनवरी 2023 – जनवरी 2024)	स्व-प्रारंभित	अमनदीप कौर
28	ओडिशा के बालकों के स्वास्थ्य पर अनुकूलन व्यय की विवक्षा (मार्च 2023 – मार्च 2024)	स्व-प्रारंभित	अमनदीप कौर
29	सतत विकास में सार्वजनिक व्यय, शासन और क्षेत्रीय असमानता: असम में जिला-स्तरीय विश्लेषण (मार्च 2022 – मार्च 2024)	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	भाबेश हजारिका और अंकित सिंह
30	भारत में राज्य वित्त के मुद्दों पर दोबारा गौर करना: कुछ अनुभवजन्य अन्वेषण (नवम्बर 2021 - दिसम्बर 2023)	स्व-प्रारंभित	भाबेश हजारिका और दिनेश कुमार नायक
31	भारतीय बच्चों के मध्य वाश और रुद्धविकास पर लोक व्यय (दिसम्बर 2022 – दिसम्बर 2023)	स्व-प्रारंभित	भाबेश हजारिका, अंकित सिंह और पल्लबी गोगोई
32	स्वास्थ्य में सार्वजनिक प्रावधान को लागू करना: क्या सार्वजनिक और निजी प्रदाता सह-अस्तित्व में हैं? (अगस्त 2021 - जून 2023)	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण के अंतर्गत बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन: भावी मार्ग	मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता
33	भारतीय आर्थिक और सामाजिक प्रदर्शनों में भिन्न क्यों होते हैं? (जुलाई 2022 - मार्च 2024)	एनआईपीएफपी	रुद्राणी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मंडल (सीडीएस) और दिनेश कुमार नायक
34	भारत में करदाता सेवाओं में सुधार करना (1 अक्तूबर 2022 – 15 जून 2023)	ईएसी-पीएम	सुप्रियो डे, प्राची जैन, नीति गुप्ता और आलोकिता बासु
35	स्कूली शिक्षा पर लिंग-संवेदनशील बजट पर अध्ययन (2019 – दिसम्बर 2022)	नेशनल कॉइलेशन फॉर एजुकेशन	सुकन्या बोस, अनुराधा डे और हर्षिता शर्मा

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
36	भारतीय राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के कामकाज की समीक्षा और मूल्यांकन (दिसम्बर 2021 – मार्च 2023)	यूनिसेफ इंडिया	मनीष गुप्ता, स्मृति बहल, सोनल अग्रवाल, देवयानी गुप्ता और प्रियाश्री गर्ग
37	कर नीति और अनुपालन के प्रति दृष्टिकोण का आकलन (जनवरी 2022)	स्व-प्रारंभित	आर. कविता राव
38	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों के माध्यम से बजट निष्पादन में सुधार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मामला (नवम्बर 2022 – दिसम्बर 2023)	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण के अंतर्गत बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन: भावी मार्ग	मीता चौधरी, प्रीतम दत्ता, नित्या चुटानी और खुशबू अहूजा
39	कोविड महामारी वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य व्यय का निर्धारण (नवम्बर 2022 – दिसम्बर 2023)	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण के अंतर्गत बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन: भावी मार्ग	मीता चौधरी और चेतना चौधरी

आरंभ किए गए नए अध्ययन

क्र. सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
1	मध्य प्रदेश के राजस्व संग्रहण पर एनआईपीएफपी अध्ययन (मार्च 2023 – प्रारंभन की तारीख से छह माह)	वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	सच्चिदानंद ए. मुखर्जी, शिवानी बडोला और विष्णु ई.के.
2	उत्तराखंड राज्य के लिए सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही आकलन (अप्रैल 2023 – जनवरी 2024)	उत्तराखंड सरकार	प्रताप रंजन जेना, दिनेश नायक, अभिषेक सिंह और अनुकृति चौबे
3	त्रिपुरा के राज्य सार्वजनिक उपक्रमों पर किए गए अध्ययन पर रिपोर्ट तैयार करना (अप्रैल-अक्तूबर 2023)	वित्त विभाग, त्रिपुरा सरकार	आर. कविता राव और रुद्राणी भट्टाचार्य
4	एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम - राज्य सरकारों द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों को वित्त के रुझान और हस्तांतरण तंत्र के राज्य-वार विश्लेषण पर अध्ययन (अप्रैल 2023 – मार्च 2024)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	मनीष गर्ग और प्रियांशी गर्ग
5	योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बार-बार होने वाले चुनावों का प्रभाव (जनवरी-जून 2023)	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव, ए.एन. झा, माल्विका महेश और रॉली कुकरेजा
6	सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान संकलित करने के वैकल्पिक तरीकों का निर्माण (पूरा होने की संभावित तारीख अगस्त 2023)	स्व-प्रारंभित	अमेय सप्रे और वैशाली भारद्वाज
7	चयनित राज्यों में सार्वजनिक निवेश के प्रबंधन पर स्टॉकटेकिंग (मार्च-जून 2023)	विश्व बैंक	सुप्रियो डे, आर. कविता राव, प्रियाली दास, मयूराक्षी सिन्हा, मीमा मौर्या और दिव्या रुद्रा
8	भारतीय राज्यों में स्पष्ट बजट सहायता : कर्नाटक का मामला (1 मार्च - 31 मई 2023)	स्व-प्रारंभित	श्री हरी नायडु ए. और अमरनाथ एच.के.
9	विशेष श्रेणी के राज्यों में स्पष्ट बजट सब्सिडी	स्व-प्रारंभित	श्री हरी नायडु ए. और अमरनाथ एच.के.

अनुबंध II: एनआईपीएफपी: कार्यकारी पत्र श्रृंखला

क्रमांक	शीर्षक	लेखक
1	भारत में केंद्रीय करों पर कर व्यय के रुझान और पैटर्न (अप्रैल 2022, सं. 380)	सच्चिदानंद मुखर्जी
2	भारत में कर नैतिकता के निर्धारक (अप्रैल 2022, सं.. 381)	चिन्मय एन. कोरगांवकर
3	भारत में कोयला और लिग्नाइट-आधारित थर्मल पावर सेक्टर के लिए कार्बन टैक्स के डिजाइन का अन्वेषण (अप्रैल 2022, सं. 382)	सच्चिदानंद मुखर्जी
4	प्राकृतिक आपदाएँ और आर्थिक गतिशीलता: केरल बाढ़ से साक्ष्य (अप्रैल 2022, सं. 383)	रॉबर्ट सी.एम. बेयेर, अभिनव नारायणन और गोगोल मित्रा ठाकुर
5	आयकर डेटा और पारदर्शिता के पहलू (मई 2022, सं. 384)	आर. कविता राव
6	भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) का राजस्व आकलन (जुलाई 2022, सं. 385)	सच्चिदानंद मुखर्जी
7	भारत के प्रमुख राज्यों के राज्य बजट 2022-23 का विश्लेषण (अगस्त 2022, सं. 386)	सच्चिदानंद मुखर्जी
8	दिल्ली में सरकारी स्कूलों की अतिरिक्त मांग का अनुमान: कितना क्षमता निर्माण आवश्यक है? (सितम्बर 2022, सं. 387)	प्रियंका घोष और सुकन्या बोस
9	भारतीय राज्य वित्त पर जीएसटी की राजस्व विवक्षाएं (जनवरी 2023, सं. 388)	सच्चिदानंद मुखर्जी
10	भारत के पहले राष्ट्रीय अनुकूलन संचार के लिए कॉप-27 और सार्वजनिक व्यय (मार्च 2023, सं. 389)	लेखा चक्रवर्ती, अजया नारायण झा, अमनदीप कौर, जितेश यादव और बालामुरली बी.
11	निवेश पर कर कटौती का प्रभाव: भारतीय विनिर्माण फर्मों से साक्ष्य (फरवरी 2023, सं. 390)	आदम हुसैन
12	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और बच्चों के प्रति अपराध: भारत में एक राज्य-स्तरीय विश्लेषण (फरवरी 2023, सं. 391)	जितेशा यादव और लेखा चक्रवर्ती

अनुबंध III: एनआईपीएफपी: आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला

क्रमांक	शीर्षक	समन्वयक	तारीख और स्थान
1	विशेष आर्थिक क्षेत्र और स्थानीय आर्थिक विकास: भारतीय नगर पालिका से साक्ष्य ओहनेस गैले (रुहर विश्वविद्यालय बोचुम), डैनियल ओवरबेक (मैनहेम विश्वविद्यालय), नादिन रिडेल (मुंस्टर विश्वविद्यालय), टोबिया द्वारा।	अमेय सप्रे	6 अप्रैल 2022 एनआईपीएफपी
2	जीएसटीआईएन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज दीक्षित द्वारा 'सूचना प्रणालियों द्वारा सक्षम व्यवसायों का कराधान परिवर्तन: भारत में माल और सेवा कर कार्यान्वयन का एक अनुभवजन्य अध्ययन' पर संगोष्ठी।	अमेय सप्रे	21 अक्तूबर 2022 एनआईपीएफपी
3	अलेक्जेंडर क्लेम, डिवीजन चीफ, टैक्स पॉलिसी-2 डिवीजन, एफएडी, आईएमएफ द्वारा 'मुद्रास्फीति से कर विकृतियाँ: वे क्या हैं? उनसे कैसे निपटें?' 'विषय पर संगोष्ठी/चर्चा।	अमेय सप्रे	12 December 2022 एनआईपीएफपी
4	अन्विता महाजन, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में पीएच.डी. छात्रा द्वारा 'कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए सरकारी स्थानांतरण पर न्यूनतम वेतन वृद्धि का प्रभाव' पर संगोष्ठी।	अमेय सप्रे	18 जनवरी 2023 एनआईपीएफपी
5	आईएमएफ के आर अलेक्जेंडर क्लेमन और कोरी हिलियर द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर सुधार' पर संगोष्ठी।	अमेय सप्रे	27 फरवरी 2023 एनआईपीएफपी
6	एनआईपीएफपी – आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला – प्रथम श्रृंखला में, अमरनाथ एच.के, पी.आर. जेना और बी. हज़ारिका द्वारा वार्ता।	अमेय सप्रे	7 अक्तूबर 2022 एनआईपीएफपी
7	एनआईपीएफपी – आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला – द्वितीय श्रृंखला में, मीता चौधरी और मुकेश आनंद द्वारा उनके अनुसंधान पर वार्ता।	अमेय सप्रे	16 दिसम्बर 2022 एनआईपीएफपी
8	एनआईपीएफपी – आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला – तृतीय श्रृंखला में, शिवानी बडोला और राधिका पांडे द्वारा उनके अनुसंधान पर वार्ता।	अमेय सप्रे	3 मार्च 2023 एनआईपीएफपी

अनुबंध IV: शासी निकाय सदस्यों की सूची

शासी निकाय ने अपनी 18 जून, 2020 को हुई बैठक में निकाय का पुनर्गठन आगे और 4 वर्ष के लिए अर्थात 5 अप्रैल, 2020 से 4 अप्रैल, 2024 तक किया।

1 अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार शासी निकाय

डा. उर्जित पटेल — **अध्यक्ष**
एनआईपीएफपी
18/2 सत्संग विहार मार्ग
विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के पास)
नई दिल्ली- 11 0067

नियम 7(ख)(एक) के अंतर्गत
वित्त मंत्रालय के तीन नामिती

श्री संजय मल्होत्रा — **सदस्य**
राजस्व सचिव
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

श्री अजय सेठ, आईएएस — **सदस्य**
सचिव (आर्थिक कार्य)
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

डा. वी. अनंता नागेश्वरन — **सदस्य**
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली 110001

नियम 7(ख)(दो) के अंतर्गत
भारतीय रिजर्व बैंक का एक नामिती

डा. राजीव रंजन — **सदस्य**
कार्यकारी निदेशक
मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
24वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001

नियम 7(ख)(तीन) के अंतर्गत
योजना आयोग का एक नामिती

सुश्री अन्ना रॉय **सदस्य**
वरिष्ठ सलाहकार
नीति आयोग
संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

नियम 7(ख)(चार) के अंतर्गत
प्रायोजक राज्य सरकारों के तीन नामिती

श्री एन. मुरुगनंदम, आईएएस **सदस्य**
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
तमिलनाडु सरकार
सचिवालय
चेन्नई - 600 009

श्री विशाल कुमार देव, आईएएस **सदस्य**
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
ओडिशा सरकार
ओडिशा सचिवालय, लोक सेवा भवन,
भुवनेश्वर-751001

श्री जे.पी गुप्ता, आईएएस **सदस्य**
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
गुजरात सरकार
ब्लॉक नं. 4/5, नया सचिवालय
गांधीनगर - 382 010

नियम 7(ख)(छह) के अंतर्गत
आईसीआईसीआई बैंक का एक नामिती

श्री बी. प्रसन्ना **सदस्य**
प्रधान - ग्लोबल मार्केट्स
आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स
बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा पूर्व
मुंबई-400 051

नियम 7(ख)(सात) के अंतर्गत
संस्थाओं के दो नामिती

श्री सुमंत सिन्हा **सदस्य**

अध्यक्ष
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
5, सरदार पटेल मार्ग
चाणक्यपुरी
(डिप्लोमैट होटल के निकट)
नई दिल्ली-110 021

श्री शुभ्रकांत पांडा **सदस्य**
अध्यक्ष
फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
फेडेरेशन हाउस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली -110 001

नियम 7(ख)(आठ) के अंतर्गत
तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री

डा. माला लालवानी **सदस्य**
प्रोफेसर
मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी
मुंबई विश्वविद्यालय
विद्यानगरी परिसर, कलीना
सांताक्रूज़ (पूर्व)
मुंबई- 400 098

डा. एम. गोविंद राव **सदस्य**
पूर्व सदस्य 14वां वित्त आयोग
निवास: 6बी, शोभा एमेराल्ड, जक्कुर,
बेंगलूर-560064

डा. ज्योत्स्ना जालान **सदस्य**
अर्थशास्त्र की प्रोफेसर
सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेज़, कलकत्ता
आर–1, बाईशनाबघाटा पाटुली टाउनशिप,
कोलकाता – 700 094

नियम 7(ख)(नौ) के अंतर्गत
सहयोगी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि

डा. पूनम गुप्ता **सदस्य**
महानिदेशक
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च
11, परिशिला भवन
आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड
नई दिल्ली – 110 002

सुश्री यामिनी अय्यर **सदस्य**
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110 021

नियम 7(ख)(दस) के अंतर्गत
शासी निकायों से सहयोजित किए जाने वाले दो सदस्य

सीए सुश्री केमिशा सोनी **सदस्य**
आईसीएआई परिषद की सदस्य
मार्फत उप सचिव (परिषद मामले)
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
आईसीएआई भवन
आई.पी. मार्ग
नई दिल्ली-110 002

नियम 7(ख)(ग्यारह) के अंतर्गत
संस्थान का निदेशक (पदेन)

डा. आर. कविता राव **सदस्य**
निदेशक, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली

नियम 7(ख)(बारह) के अंतर्गत
संस्थान का एक प्रोफेसर चक्रानुक्रम में

डा. प्रताप रंजन जेना **सदस्य**
प्रोफेसर, एनआईपीएफपी,
नई दिल्ली

विशेष आमंत्रिती

श्री नितिन गुप्ता **सदस्य**
अध्यक्ष
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110 001

श्री विवेक जैन **सदस्य**
अध्यक्ष
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110 001

अनुबंध V: समूल्य प्रकाशनों की सूची

क्रमांक	समूल्य प्रकाशनों की सूची
1	**भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की घटनाएं 1973-74,**आरजे चेलिया और आरएन लाल (1978) INR 10. हिंदी संस्करण (1981) INR 20
2	**भारतीय संघीय वित्त में रुझान और मुद्दे**,* आरजे चेलिया एंड एसोसिएट्स (एलाइड पब्लिशर्स) (1981) INR 60.
3	**बिहार में बिक्री कर प्रणाली**,* आरजे चेलिया और एमसी पुरोहित (सोमैया प्रकाशन) (1981) INR 80.
4	**राज्य सरकारों के कर प्रयास का मापन 1973-76**, आरजे चेलिया और एन सिन्हा (सोमैया प्रकाशन) (1982) INR 60.
5	**व्यक्तिगत आयकर का प्रभाव**, अनुपम गुप्ता और पवन के अग्रवाल (1982) INR 35.
6	**निजी कॉरिट क्षेत्र में संसाधन जुटाना**, विनय डी. लाल, श्रीनिवास मधुर और केके अत्री (1982) INR 50.
7	**वितीय प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट कर बचत**, विनय डी. लाल (1983) INR 40.
8	**निजी ट्रस्टों का कर उपचार**, के श्रीनिवासन (1983) INR 140.
9	**केंद्र सरकार का व्यय: विकास, संरचना और प्रभाव(1950-51से 1977-78),** केएन रेड्डी, जेवीएम सरमा और एन सिन्हा (1984) INR 80.
10	**चुंगी के विकल्प के रूप में प्रवेश कर**, एमजी राव (1984) INR 40 पेपरबैक, INR 80 हार्डकवर।
11	**सूचना प्रणाली और तमिलनाडु में बिक्री कर की चोरी**, आरजे चेलिया और एमसी पुरोहित (1984) INR 50.
12	**भारत में उत्पाद शुल्क की चोरी: तांबे, प्लास्टिक और सूती वस्त्रों के कपड़े का अध्ययन**, ए बागची एट अल। (1986) INR 180.
13	**भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलू (जिसे 'ब्लैक मनी रिपोर्ट भी कहा जाता है)**, शंकर एन आचार्य एंड एसोसिएट्स, आरजे चेलिया द्वारा योगदान के साथ (1986) पुनर्मुद्रण संस्करण INR 270.
14	**मुद्रास्फीति लेखा और कॉरिट कराधान**, तापस कुमार सेन (1987) INR 90.
15	**पश्चिम बंगाल में बिक्री कर प्रणाली**, ए बागची और एसके दास (1987) INR 90.
16	**ग्रामीण विकास भता (आयकर अधिनियम, 1961की धारा 35CC)**: एक समीक्षा, एचके सोंधी और जेवीएम सरमा (1988) INR 40.
17	**दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली**, आरजे चेलिया और केएन रेड्डी (1988) INR 240.
18	**निवेश भता (आयकर अधिनियम, 1961की धारा 32ए): एक अध्ययन**, जेवीएम सरमा और एचके सोंधी (1989) INR 75पेपरबैक, INR 100 हार्डकवर।
19	**धर्मार्थ योगदान के लिए कर प्रोत्साहन के अनुकरणीय प्रभाव: भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक अध्ययन**,पवन के अग्रवाल (1989) INR 100.
20	**भारत में डाक सेवाओं का मूल्य निर्धारण**, राघवेंद्र झा, एमएन मूर्ति और सत्य पॉल (1990) INR 100.
21	**भारत में घरेलू बचत - रुझान और मुद्दे**,# उमा दत्ता रॉय चौधरी और अमरेश बागची (सं.) (1990) INR 240.

क्रमांक	समूल्य प्रकाशनों की सूची
22	**मध्य प्रदेश में बिक्री कराधान**,# एम गोविंदा राव, केएन बालासुब्रमण्यम और वीबी तुलसीधर (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 125.
23	**मोडवैट का संचालन**,# एवीएल नारायण, अमरेश बागची और आरसी गुप्ता (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 250.
24	**राजकोषीय प्रोत्साहन और संतुलित क्षेत्रीय विकास**: धारा 80 एचएच का मूल्यांकन, # पवन के. अग्रवाल और एचके सोंधी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) INR 195.
25	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर: एक प्रोफ़ाइल (वॉल्यूम I और II)** INR 100.
26	**भारत में एल्युमीनियम उद्योग के लिए प्रभावी प्रोत्साहन मोनोग्राफ श्रृंखला -1**, बी गोल्डर (1991) INR 100.
27	**भारत में राजकोषीय संघवाद पर अनुसंधान का सर्वेक्षण मोनोग्राफ श्रृंखला - II**, एम गोविदा राव आर आरजेचेलिया (1991) INR 100.
28	**राजस्व और व्यय अनुमान: मूल्यांकन और कार्यप्रणाली**,# वीजी राव, अतुल सरमा द्वारा संशोधित और संपादित (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992) INR 195.
29	**भारत में बिक्री कर प्रणाली: एक प्रोफाइल**(1991) INR 150
30	**भारत में राज्य वित्त**#, अमरेश बागची, जेएल बजाज और विलियम ए, बर्ड (सं.) (1992) INR 450.
31	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राजकोषीय नीति**,# महेश सी. पुरोहित, सी. साई कुमार, गोपीनाथ प्रधान और ओ.पी. बोहरा (1992) INR 225.
32	**विनिर्माण क्षेत्र मोनोग्राफ श्रृंखला III में आयात प्रतिस्थापन**, हाशिम एन सलीम (1992) INR150.
33	**भारत में बिक्री कर प्रणाली: एक प्रोफाइल**(1993) INR 150.
34	**नौवां वित्त आयोग: मुद्दे और सिफारिशें (कागजात का चयन) (1993)** INR 4901
35	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर: एक प्रोफ़ाइल (खंड III),**के. कन्नन और ममता शंकर द्वारा संकलित (1993)INR 80.
36	**आर्थिक विकास और जीवन स्तर में अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय बदलाव (मोनोग्राफ सीरीज IV) (1993)**उमा दत्ता रॉय चौधरी INR 200.
37	**विकासशील देशों में कर नीति और योजना**,* अमरेश बागची और निकोलस स्टर्न (सं.) (1994) (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) INR 435.
38	**भारत में घरेलू व्यापार करों में सुधारः मुद्दे और विकल्प अध्ययन दल (1994)** INR 250.
39	**निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र: धन का सृजन और पुनर्जनन**, उमा दत्ता रॉय चौधरी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1996) INR 395.
40	**प्रदूषण को नियंत्रित करना: प्रोत्साहन और विनियम**, शेखर मेहता, सुदीप्तो मुंडले और यू. शंकर (सेज प्रकाशन) (1997) INR 250.
41	**भारत: नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कर नीति (1997-98 से 2001-02),# (वित्तीय संसाधन अध्यक्ष पार्थसारथी शोम पर संचालन समूह की कर नीति पर कार्य समूह की रिपोर्ट)** (सेंटैक्स प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 350.

क्रमांक	समूल्य प्रकाशनों की सूची
42	**भारत में मूल्य वर्धित कर: एक प्रगति रिपोर्ट**,# पार्थसारथी शोम (सं.) (सैंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 250.
43	**राजकोषीय नीति सार्वजनिक नीति और शासन**,# पार्थसारथी शोम (सं.) (सैंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड) (1997) INR 400.
44	**भारत में सरकारी सब्सिडी**, डीके श्रीवास्तव और तापस के. सेन (1997) INR 285.
45	**पर्यावरण स्थिरता के लिए आर्थिक उपकरण**, यू. शंकर और ओम प्रकाश माथुर (1998) INR150.
46	**भारत: शहरी शासन की चुनौती**, ओम प्रकाश माथुर (सं.) (1999) INR 400.
47	**राज्य वित्तीय अध्ययन - असम**, डीके श्रीवास्तव, सौमेन चट्टोपाध्याय और टीएस रंगमन्नार (1999) INR200.
48	**राज्य वित्तीय अध्ययन - पंजाब**, इंदिरा राजारमन, एच. मुखोपाध्याय और एच.के. अमरनाथ (1999) INR 200.
49	**राज्य वित्तीय अध्ययन - केरल**, डीके श्रीवास्तव, सौमेन चट्टोपाध्याय और प्रप रंजन जेना (1999) INR200.
50	**दिल्ली राजकोषीय अध्ययन**, ओम प्रकाश माथुर और टीएस रंगमन्नार (2000) INR 250.
51	**भारत में राजकोषीय संघवाद ग्यारहवें वित्त आयोग के समक्ष समसामयिक चुनौतियां मुद्दे**, डीके श्रीवास्तव (सं.) (हर आनंद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड) (2000) INR 695.
52	**राज्य वित्तीय अध्ययन - हरियाणा**, तापस के. सेन, आर. कविता राव (2000) INR 200
53	**सार्वजनिक धन का नियंत्रण: विकासशील देशों में राजकोषीय तंत्र**,* ए प्रेमचंद (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) (2000) INR 745.
54	**मूल्यवर्धित कर पर प्राइमर**,# आरजे चेलिया, पवन, के अग्रवाल, महेश सी. पुरोहित और आर कविता राव (हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड) (2001) INR 195.
55	**भारत में केंद्रीय बजटीय सब्सिडी**, डीके श्रीवास्तव और एचके अमरनाथ (2001) INR 170..
56	**राज्य नगरपालिका वित्तीय संबंधों के लिए दृष्टिकोण: विकल्प और परिप्रेक्ष्य**, ओम प्रकाश माथुर (2001) INR 200.
57	**व्यापार और उद्योग: एनआईपीएफपी-फोर्ड फाउंडेशन फेलो द्वारा निबंध**,# एके गुहा, केएल कृष्णा और अशोक, के.लाहिरी (सं.) (विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड) (2001) INR 450.
58	**भारत के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और विनियम: अनुमोदन और विकल्प**,# एसपी सिंह और अमरेश बागची आरके बजाज द्वारा योगदान के साथ (यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड) (2002) INR 395.
59	**विदेशी उत्पादों की तुलना में घरेलू का भेदभावपूर्ण कर व्यवहार: एक आकलन**, पवन के. अग्रवाल और वी. सेल्वाराजू (2002) INR 200.
60	**नियमन का अभ्यास और राजनीति: भारतीय विद्युत में नियामक शासन**,* नवरोज के. दुबाशंद डी. नरसिम्हा राव (2007) INR 290.
61	**मानव विकास पर गरीबी की कमी से निपटना: मध्य प्रदेश में वित्तीय रणनीतियाँ (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण)**, तापस के सेन, एचके अमरनाथ, मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी (2007) INR 150.
62	**तमिलनाडु में मानव विकास का वितपोषण: उपलब्धि पर समेकित और निर्माण (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वितपोषण)**, तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी (2008) INR 150.

क्रमांक	समूल्य प्रकाशनों की सूची
63	**भारतीय संघ में स्वास्थ्य व्यय का अंतर-राज्यीय समानता**, एम. गोविंदा राव और मीता चौधरी (2008) INR 75.
64	**भारत में व्यय प्रबंधन के 50वर्षों के इनकार के आराम क्षेत्र में फंस गया**, ए प्रेमचंद (2008) INR 150. (स्टॉक में: 86)
65	**राजकोषीय विकेंद्रीकरण और जेंडर बजटिंग**, एम. गोविंदा राव, लेखा चक्रवर्ती, अमरेश बागची (2008) INR 250.
66	**वित्तीय सुधार, लगातार गरीबी और मानव विकास: उड़ीसा का मामला (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण)**, तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोतिया कुंडू (2008) INR 150.
67	**पश्चिम बंगाल में मानव विकास के सार्वजनिक वित्त पोषण पर वित्तीय बाधाओं से निपटना (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण)** - तापस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोतिवा कुडू (2009) INR 150.
68	**भारत के निम्न कार्बन आर्थिक विकास की संभावनाएं और नीतियां**, रामप्रसाद सेनगुप्ता (2010) INR 150.
69	**भारत में निम्न कार्बन और उच्च विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत साधन,** यू. शंकर (2010) INR 150.
70	**राजस्थान: आर्थिक और मानव विकास को समवर्ती रूप से बढ़ावा देना (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तापस के, सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR 150.
71	**भारत: सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही -सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट,** प्रताप रंजन जेना (2010) INR 150.
72	**हिमाचल प्रदेश में सतत मानव विकास के लिए संसाधन (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तपस के. सेन, एच.के, अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR 150.
73	**एक युवा राज्य का परिपक्वता में तेजी से संक्रमण: छत्तीसगढ़ में मानव विकास के लिए संसाधन (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR, 150.
74	**केरल में मानव विकास का वित्तपोषण: मुद्दे और चुनौतियाँ (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण)**, पिनाकी चक्रवर्ती, लेखा चक्रवर्ती, एचके अमरनाथ, और सोना मित्रा (2010) INRI 150.
75	**अपने आर्थिक विकास के साथ पूरे महाराष्ट्र में मानव विकास का मिलान (मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण),** तापस के. सेन, अमरनाथ एच.के., मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010) INR 150.
76	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अव्ययित शेष और निधि प्रवाह तंत्र,** एनआर भानुमूर्ति, एचके अमरनाथ, अखिलेश वर्मा और आदर्श गुप्ता (2014) INR 200. (स्टॉक में: 98)
77	**राज्य के वित में उभरते मुद्दे चौदहवें वित्त आयोग के बादः राज्य बजट 2016-17 का विश्लेषण**, मनीष गुसा, लेखा चक्रवर्ती और पिनाकी चक्रवर्ती (2018).
78	**राज्य के बजट 2017-18 का विश्लेषण: उभरते मुद्दे (विद्युत क्षेत्र के ऋण का प्रभाव - राज्य के वित्त पर उदय),** पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर (2018) INR 2001.
79	**राज्य के बजट 2018-19 का विश्लेषण - प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ (बजट विश्वसनीयता और वित्तीय पूर्वानुमान त्रुटियाँ)** मनीष गुप्ता, लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर (2020).
80	***आरटीई और संसाधन अपेक्षाएं : भावी मार्ग, सुकन्या बोस, प्रियंका घोष और अरविंद सरदाना*** (2020) INR 200.

*संबंधित प्रकाशकों के साथ सह-प्रकाशित/उपलब्ध।

* सह-प्रकाशित।

ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के खिलाफ प्रकाशन भेजे गए। डाक खर्च INR 80 प्रति प्रति।

टिप्पणी: प्रकाशन क्रमांक 1 से 69 तक, बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इन्हें एनआईपीएफपी लाइब्रेरी से एक्सेस किया जा सकता है

अनुबंध VI: एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री

(पुस्तकें, जर्नल, मोनोग्राफ और अन्य लोकप्रिय लेखन-कार्य)

आर. कविता राव

1. 'जीएसटी, एंड ऑफ कम्पेंशेसन रिजीम एंड स्ट्रेस ऑन स्टेट फाइनेंसेस', (उमा कपिला संपा.) *भारत में आर्थिक विकास*, खंड 258, अकादमिक फाउंडेशन, जुलाई 2022.
2. '4.5% फिस्क एम मे शिफ्ट तो एफवाई27', *इंफ़ॉर्मिस्ट* को साक्षात्कार, 20 जनवरी 2023.
3. '**इनकम टैक्स डेटा एंड फेसेट्स ऑफ ट्रांस्पेरेंसी**', **एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं.** 384, **मई** 2022.

लेखा चक्रवर्ती

1. *''भारत में पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण और राज्य-स्तरीय बजटीय खर्च, फ्लाईपेपर प्रभावों का विश्लेषण (सह-लेखक अमनदीप कौर, रंजन कुमार मोहंती और दिव्य रंगन), इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड: 58(14), **अप्रैल** 2023.*
2. *'लैंगिक समानता और राजकोषीय स्थान पर लिंग बजटिंग की क्षेत्र-विशिष्ट प्रभावशीलता: एशिया प्रशांत से अनुभवजन्य साक्ष्य (सह-लेखक इंग्राम्स मरियम, यादवेंद्र सिंह और कोमल जैन), जर्नल ऑफ इंडियन लॉ एंड सोसाइटी. **खंड**: 13(77), 2022.*
3. *'शहरों का वित्तपोषण: भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को हस्तांतरण का विश्लेषण' (सह-लेखक बालमुरली बी.), अर्बन अपडेट, 2023.*
4. *'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और बालकों के प्रति अपराध: भारत में एक राज्य-स्तरीय विश्लेषण' (सह-लेखक जितेश यादव), , **एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं.** 391, फरवरी 2023.*
5. *भारत के पहले राष्ट्रीय अनुकूलन संचार के लिए कॉप-27 और सार्वजनिक व्यय (सह-लेखक अजय नारायण झा, अमनदीप कौर, जितेश यादव, बालामुरली बी और जितेश यादव),, **एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं.** 389, मार्च 2023.*
6. *बालकों के प्रति अपराध को कम करने में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की प्रभावशीलता (सह-लेखक जितेश यादव), 1009, लेवी इंस्टिट्यूट, अगस्त 2022.*
7. *एशिया-प्रशांत में सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति: जेंडर बजटिंग इन इंडिया, स्प्रिंगर लिंक के अंतर्गत पालग्रेव मैकमिलन 2022.*

अन्य क्रियाकलाप/लोकप्रिय लेखन-कार्य

8. *'हमें पुरानी पेंशन योजना पर बहस करने की आवश्यकता क्यों है' (सह-लेखक जितेश यादव और बालमुरली बी.), दि हिंदू,, 5 अप्रैल 2023.*
9. *'नारी शक्ति: महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए लिंग बजटिंग', मनीकंट्रोल, 8 मार्च 2023.*
10. *'विल एफएम्स बजट 2023 इनेबल 'नारी शक्ति'?' (सह-लेखक बालामुरली बी.), फोर्ब्स, 22 फरवरी 2023.*
11. *'आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के निर्णय', ऑल इंडिया रेडियो का विश्व वायु सेवा प्रसारण, 9 फरवरी 2023.*
12. *'वाई केरलाज़ टैक्स हाइक्स एपीयर कम्पेलिंग', दि हिंदू, 7 फरवरी 2023.*
13. *'केरला बजट : ए प्लान फॉर लैस पेनफुल फिक्स्कल कंसोलिडेशन', मनीकंट्रोल, 6 फरवरी 2023.*

14. *'इज़ दि गवर्नमेंट ऑन ट्रैक ऑन फिस्कल डेफिसिट टार्गेट्स?' दि हिंदू,, 5 फरवरी 2023.*
15. *'बजट 2023 राजकोषीय समेकन पथ पर बना हुआ है, मनीकंट्रोल, 2 फरवरी 2023.*
16. *'बजट गोइंग बियॉन्ड दि जीडीपी' (सह-लेखक बालामुरली बी.), दि हिंदू बिजनिस लाइन, 2 फरवरी 2023.*
17. *'हमारे भविष्य के शहरों को मजबूत करने के लिए यूएलबी का वित्तपोषण' (सह-लेखक बालामुरली बी.), अर्बन अपडेट, 12 जनवरी 2023.*
18. *'बजट 2023: उम्मीद है कि केंद्र राज्यों के सामने आने वाले राजकोषीय तनाव का समाधान करेगा ' (सह-लेखक बालामुरली बी.),, मनीकंट्रोल, 11 जनवरी 2023.*
19. *'बजट को राजकोषीय नीति को उदार बनाए रखना चाहिए; पुनर्प्राप्ति को प्रभावित किए बिना समेकित करें', मनीकंट्रोल, 3 जनवरी 2023.*
20. *'भारत को राजकोषीय परिषद की आवश्यकता क्यों है', (सह-लेखक एमैनुअल थॉमस), दि हिंदू,, 7 जून 2022.*
21. *'महंगाई पर सरकार और आरबीआई एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं', दि हिंदू,, 20 मई 2022.*
22. *'तरलता पर आरबीआई का कठोर रुख', दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 22 अप्रैल 2022.*
23. *'केंद्रीय बजट 2023-24: राजकोषीय घाटा और केपेक्स', डब्ल्यूआईओएन, 1 फरवरी 2023.*
24. *'केंद्रीय बजट 2023-24: राजकोषीय घाटा और चुनावों का आकलन', एशियानेट, 1 फरवरी 2023.*
25. *'केंद्रीय बजट 2023-24: राजकोषीय घाटा, विनिवेश और बजट साख' ऑन प्रोफिट मोटिव, तान्या थॉमस के साथ, 1 फरवरी 2023.*

सुप्रियो डे

1. *'प्रत्यक्ष कर मुकदमेबाजी प्रबंधन और वैकल्पिक विवाद समाधान', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 394, मार्च 2023.*
2. *'भारत की कॉर्पोरेट आयकर व्यवस्था में हालिया सुधार: तर्क, प्रभाव और सुधार', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 393, मार्च 2023.*
3. *डॉ. सी. रंगराजन की 90वीं जयंती के सम्मानार्थ और उत्सव मनाने के लिए 'भारत के समकालीन व्यापक आर्थिक विषय-वस्तु' पर सम्मेलन की कार्यवाही/ 'भारत की कॉर्पोरेट आय में हालिया सुधार', मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई, तमिलनाडु, 21-22 अप्रैल 2022..*

प्रताप रंजन जेना

1. *'भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट गुणवत्ता: बेसल III विनियमों के निहितार्थ' (सह-लेखक डॉली गौड़ और दीप्ति रंजन महापात्रा), जर्नल ऑफ एशिया-पैसिफिक बिजनेस, खंड 23:3(234-253), डीओआई: 10.1080/10599231.2022.2095587*
2. *'भारत में नियोजित बजट को लागू करने के लिए राज्यों की क्षमता: पीईएफए फ्रेमवर्क का उपयोग करके एक आकलन', द इंडियन इकोनॉमिक जर्नल (सेज प्रकाशन), (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)।*

मीता चौधरी

1. *'महामारी के माध्यम से पुनः सीखना: भारत की कोविड-19 स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रतिक्रिया' (सह-लेखक ग्रेस अचुंगुरा, राहुल रेड्डी और जयदेव आनंद),* पी4एच. *https://p4h.world/en/blogs/Indias-COVID-19-health-financing-response*
2. *'स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च के अंतर-राज्य वितरण में समानता: बिहार और तमिलनाडु का मामला' (माइमोग्राफ), 2022*
3. *'कोविड वर्ष में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय: एक राज्य-स्तरीय विश्लेषण' (माइमोग्राफ), 2023*

सच्चिदानंद मुखर्जी

1. *'भारतीय राज्य वित्त पर जीएसटी के राजस्व निहितार्थ', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 388, नवम्बर 2021.*
2. *'भारत के प्रमुख राज्यों के राज्य बजट 2022-23 का विश्लेषण', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 386, अगस्त 2022.*
3. *'भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) का राजस्व आकलन', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 385, जुलाई 2022.*
4. *'भारत में कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर सेक्टर के लिए कार्बन टैक्स के डिजाइन की खोज', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं.. 382, अप्रैल 2022.*
5. *'भारत में केंद्रीय करों पर कर व्यय के रुझान और पैटर्न', एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 380, अप्रैल 2022.*
6. *'राजस्व कमी और जीएसटी मुआवजा: एक आकलन', इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 58(9):4-46,4 मार्च 2023.*
7. *'भारत में अनिगमित उद्यमों की वैट अनुपालन लागत का अनुमान: इकाई-स्तरीय विश्लेषण' (सह-लेखक शिवानी बडोला), इंडियन इकॉनॉमिक रिव्यू,* खंड *57(2):421-441, 28 अक्तूबर 2022. https://doi.org/10.1007/s41775-022-00139-8*
8. *'कॉर्पोरेट कर दरों में परिवर्तन के व्यापक आर्थिक निहितार्थ: एक समीक्षा', ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक समीक्षा, खंड. 56(1):20-41,13 दिसम्बर 2022. https://doi.org/10.1111/1467-8462.12497*
9. *'भारत में कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर सेक्टर पर कार्बन टैक्स के डिजाइन की खोज', रिव्यू ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन वॉल्यूम, खंड. 14(2-3):83-112, 9 जून 2022. https://doi.org/10.1177/09749292221103916*
10. *'कोविड-19 महामारी के समय में भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, खंड. 70(3):452–471,8 जून 2022.https://doi.org/10.1177/ 00194662221104751*

रेणुका साने

1. *'भारतीय वित्तीय बाजारों में उपभोक्ता शिकायत निवारण' (सह-लेखक विमल बालासुब्रमण्यम और सृष्टि शर्मा), द लीप ब्लॉग, 14 मई 2022.*
2. 'सेबी डिसगॉर्जमेंट पर पुनर्विचार' (सह-लेखक विवेक एस.), *द लीप ब्लॉग, जून 2022.*
3. *'नया बाजार, नई समस्याएं - डिजिटल इंडिया के साथ बढ़ती अनुचित व्यापार प्रथाएं', द प्रिंट, 22 जून 2022.*
4. *'एनपीएस को छोड़ना राज्य सरकारों के लिए एक त्रासदी है। डीबी पेंशन तदर्थ हैं, राजकोषीय तनाव में देरी करती हैं', द प्रिंट, 6 जुलाई 2022.*

5. *'इनसॉल्वेंसी कोड भारत की सफलता की कहानियों में से एक है। लेकिन अब इसे एक नए जीवन की जरूरत है', द प्रिंट, 20 जुलाई 2022.*
6. *''भारत के वित्तीय क्षेत्र को उपभोक्ता शिकायतों को संबोधित करने का कोई अर्थ नहीं दिखता', द प्रिंट, 3 अगस्त 2022.*
7. *'मुफ्त वस्तुओं पर बहस में, भारत भूल रहा है कि उसने कल्याणकारी सेवाओं के बदले कानून के शासन का व्यापार किया है', द प्रिंट, 17 अगस्त 2022.*
8. *'एड्रेस प्रूफ' की मांग घर से काम करने के पीएम के दबाव के विरुद्ध है', द प्रिंट, 31 अगस्त 2022.*
9. *'साइरस मिस्त्री त्रासदी से पता चलता है कि सड़क सुरक्षा सीटबेल्ट तक सीमित नहीं है', द प्रिंट, 14 सितम्बर 2022.*
10. *'तीसरे पक्ष के ऋण वसूली एजेंटों पर आरबीआई का प्रतिबंध ठीक नहीं है। यह एपी की माइक्रोफाइनेंस प्रतिबंध गलती की तरह है', द प्रिंट, 28 सितम्बर 2022.*
11. *'यदि केंद्र और राज्य एक साथ आएं तो ई-साइन भूमि बाजारों के लिए वही किया जा सकता है जो डीमैट ने इक्विटी के साथ किया', द प्रिंट, 12 अक्तूबर 2022.*
12. *'केंद्र सरकार के बाद अब राज्य भी अटका रहे हैं बजट' भारत को सीएजी ऑडिट से ज्यादा सच्चे बॉन्ड मार्केट की जरूरत है', द प्रिंट, 26 अक्तूबर 2022.*
13. *'टेलीकॉम बिल भारत की महान सफलता की कहानियों में से एक का गला घोंट देगा, हमें लाइसेंस राज में वापस ले जाएगा', द प्रिंट, 9 नवम्बर 2022.*
14. *'आधार अधिनियम से डेटा संरक्षण विधेयक - संसद कानून बनाने में बड़ी भूमिका नहीं निभा रही है', द प्रिंट, 23 नवम्बर 2022.*

मुकेश कुमार आनंद

1. *ओपीएस, एनपीएस, जीपीएस: वास्तविक पेंशन सुधार गायब है', दि इंडियन एक्सप्रेस,* 6 मार्च 2023. *https://indianexpress.com/article/opinion/columns/ops-nps-gps-the-real-pension-reform-is-missing-8480399/lite/*

रुद्राणी भट्टाचार्य

1. *'नाउकास्टिंग इंडियाज क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ: ए फैक्टर-ऑगमेंटेड टाइम-वेरिंग कोएफिशिएंट रिग्रेशन मॉडल (एफए-टीवीसीआरएम) (सह-लेखक बोर्नली भंडारी (एनसीएईआर) और सुदीप्तो मुंडले), जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, खंड 21:213-234, जनवरी 2023.*
2. *'मैक्रोइकॉनॉमिक पूर्वानुमान और राजकोषीय नीति चुनौतियां (सह-लेखक सुदीप्तो मुंडले और दिनेश कुमार नायक), (सं. उमा कपिला) भारत में आर्थिक विकास - त्रैमासिक अपडेट, खंड 260:165-74, एकेडेमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली, 2022.*
3. *अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए त्रैमासिक आकलन : ईएसी-पीएम के लिए नोट (मिमोयोग्राफ)*
    I. अप्रैल-जून 2022
    II. जुलाई-सितम्बर 2022
    III. अक्तूबर-दिसम्बर 2022
    IV. जनवरी-मार्च 2021
4. *'जीएसटी व्यवस्था में रूपांतरण ने भारत में मंहगाई को किस प्रकार प्रभावित किया है?", (मिमोयोग्राफ) 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव' पर सम्मेलन के लिए, 28-29 नवम्बर 2022.*

सुकन्या बोस

1. *'दिल्ली में सरकारी स्कूलों की अतिरिक्त मांग का अनुमान: कितना क्षमता निर्माण आवश्यक है?' (सह-लेखक प्रियंता घोष), एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 387, सितम्बर 2022.*
2. *'बिहार में स्कूली शिक्षा पर सार्वजनिक व्या : द गैप्स दैट कोविड-19 हाइलाइट्स' (केंद्रीय बजट का विश्लेषण शामिल है) (सह-लेखिका हर्षिता शर्मा), नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन के लिए शोध रिपोर्ट, मार्च 2023.*
3. *'दिल्ली में स्कूली शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च: द गैप्स दैट कोविड-19 हाइलाइट्स', नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन के लिए शोध रिपोर्ट, मार्च 2023.*
4. *'शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी का तृतीय पक्ष ऑडिट', रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी गई, जनवरी 2023.*

अमेय सप्रे

1. *राष्ट्रीय खातों में स्थिति और संकलन मुद्दे', (सह-लेखिका वैशाली भारद्वाज), ईएसी-पीएम के लिए कार्यकारी पत्र, मई 2023.*
2. *'ब्लू इकोनॉमी में गतिविधियों के लिए तरीके और अनुमान ढांचा', ब्लू इकोनॉमी: टिकाऊ, सुरक्षित और लचीली अर्थव्यवस्था के लिए भारत का मार्ग, टेरी-केएएस प्रकाशन, मई 2022.*

सुरांजलि टंडन

1. *'छूट और संशोधित दरें 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को नई कर प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी', द इंडियन एक्सप्रेस, 2 फरवरी 2023.*
2. *'ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट: 'अश्लील' अमीरों पर कर लगाना सही समाधान नहीं हो सकता है, द इंडियन एक्सप्रेस, 23 जनवरी 2023.*
3. *'ऊर्जा परिवर्तन को वित्तपोषित करना: भारत के G20 प्रेसीडेंसी को Cop27 से सबक लेना चाहिए', द इंडियन एक्सप्रेस, 17 दिसंबर 2022.*
4. *'मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए नीति में जलवायु परिवर्तन को शामिल करना महत्वपूर्ण है', द इंडियन एक्सप्रेस, 27 अगस्त 2022.*
5. *'डिजिटल टैक्स चुनौती को संबोधित करना ', द इंडियन एक्सप्रेस, 23 अप्रैल 2022.*
6. *'अंतर्राष्ट्रीय कर विवादों का भविष्य', एशिया प्रशांत कानून समीक्षा, खंड 31(1), 2023.*
7. *'पूंजीगत लाभ छूट को 10 करोड़ रुपये तक सीमित करने से शानदार प्रदर्शन करने वाले लक्जरी आवासीय बाजार पर असर पड़ेगा', बीक्यू प्राइम, 11 फरवरी 2023.*
8. *'केंद्रीय योजना की समस्या', लॉ स्कूल नीति समीक्षा और कौटिल्य सोसायटी ब्लॉग संगोष्ठी, 13 दिसंबर 2022.*
9. *'विकासशील देशों पर स्तंभ एक और दो के प्रभाव का मूल्यांकन (सह-लेखक चेतन राव), साउथ सेंटर, शोध पत्र 165, 4 अक्टूबर 2022.*
10. *'वैश्विक न्यूनतम कर की आवश्यकता: स्तंभ दो सुधार का आकलन, इंटरटैक्स, खंड 50(5):396-413, 2022.*
11. *'स्केलिंग अप सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन द ग्लोबल साउथ', सीईपीआर ई-बुक, 1 नवंबर 2022। 'नीतिगत टिप्पणी: विकासशील देशों पर स्तंभ दो के प्रभाव का आकलन', क्लूवर इंटरनेशनल टैक्स ब्लॉग इंटरटैक्स, खंड 50(12):923-935,* 8 दिसम्बर 2022. *https://doi.org/10.54648/taxi2022094*

12. *'नेटजीरो तक पहुंचने के लिए मौजूदा और आवश्यक वित्त के बीच एक स्पष्ट अंतर बना हुआ है', इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ब्लॉग, 23 जनवरी 2023.*

प्रियाली दास

1. *'राजकोषीय प्रभुत्व और संप्रभु ऋण प्रबंधन' (सह-लेखक चेतन घाटे और सुभादीप हलदर), भारतीय सांख्यिकी संस्थान कार्यकारी पत्र, 9 दिसंबर 2022.*
2. *'ऋण विघटन और मुद्रास्फीति की भूमिका: भारत के लिए एक सुरक्षा-स्तर का विश्लेषण' (सह-लेखक चेतन घाटे), आर्थिक मॉडलिंग, खंड: 113, ISSN 0264-9993, 2022.*

माल्विका महेश

1. *'क्या जमींदार का लिंग स्व-खेती और कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है? एन एनालिसिस फॉर इंडिया (सह-लेखिका बीना अग्रवाल), द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, खंड 59:5:758-777, 2023.* डीओआई: *10.1080/00220388.2022.2162883*

दिनेश कुमार नायक

1. *'भारतीय उप-नागरिकों में आय और सरकारी व्यय के बीच संबंध: एक दूसरी पीढ़ी के पैनल सह-एकीकरण तकनीक' (सह-लेखक भाबेश हजारिका), द जर्नल ऑफ डेवलपिंग एरियाज, खंड 57(1):205-228, 2022.*
2. *'मैक्रोइकोनॉमिक फोरकास्ट्स एंड फिस्कल पॉलिसी चैलेंज' (सह-लेखक सुदीप्तो मुंडले और रुद्राणी भट्टाचार्य), (सं. उमा कपिला) भारत में आर्थिक विकास - त्रैमासिक अपडेट, खंड 260:165-74, अकादमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली, 2022*

भाबेश हजारिका

1. *'भारतीय उप-नागरिकों में आय और सरकारी व्यय के बीच संबंध: एक दूसरी पीढ़ी के पैनल सह-एकीकरण तकनीक (सह-लेखक दिनेश कुमार नायक), द जर्नल ऑफ डेवलपिंग एरियाज, खंड 57(1):205-228, 2022*
2. *'सार्वजनिक खर्च, शासन, और भारतीय उप-राष्ट्रीय में मृत्यु दर संभावना: एक दो-स्तरीय यादृच्छिक अवरोधन विश्लेषण', जर्नल ऑफ़ डेवलपिंग एरियाज़ (प्रेस में), 2022.*
3. *'भारत में बुजुर्गों के बीच खाद्य सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक संकट' (सह-लेखक पल्लबी गोगोई), विकास और परिवर्तन की समीक्षा, खंड: 27(2):214-237, 11 नवम्बर 2022.*

अमनदीप कौर

1. *'कॉप 27 और भारत के पहले राष्ट्रीय अनुकूलन संचार के लिए सार्वजनिक व्यय' (सह-लेखक लेखा चक्रवर्ती, अजय नारायण झा और जितेश यादव),* एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. *389, मार्च 2023.*
2. *'पारिस्थितिकी राजकोषीय हस्तांतरण और भारत में राज्य-स्तरीय बजटीय खर्च: फ्लाईपेपर प्रभावों का विश्लेषण' (सह-लेखक रंजन कुमार मोहंती, दिव्य रंगन और लेखा चक्रवर्ती), इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड: 58(14), अप्रैल 2023.*

राधिका पांडेय

1. *'सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया' (सह-लेखिका इला पटनायक), ग्रास्पिंग ग्रेटनेस (सं. एशले जे. टेलिस, बिबेक रॉय और सी. राजा मोहन), पेंगुइन, मार्च 2023.*
2. *'कॉर्पोरेट मुनाफ़े में असाधारण वृद्धि का विश्लेषण' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड. 57(25), 18 जून 2022.*
3. *'अमेरिकी फेडरल रिजर्व दर वृद्धि का स्पिलओवर प्रभाव' (सह-लेखक प्रमोद सिन्हा), इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड. 57(40), 1 अक्तूबर 2022.*
4. *कार्नेगी इंडिया के लिए 'भारत में मुद्रास्फीति के संकट को समझना' पर पॉडकास्ट, 16 जुलाई 2022.*
5. *'उच्चतर ब्याज दर के लिए स्वयं को तैयार रखें', दि इंडियन एक्सप्रेस, 16 मई 2022.*
6. *'आरबीआई का मुद्रास्फीति प्रबंधन को प्राथमिकता देना सही है। लेकिन यह आसान नहीं होगा', द इंडियन एक्सप्रेस, 12 अप्रैल 2022.*
7. *'एनबीएफसी: एक गहरी नजर' (सह-लेखक रचना शर्मा और प्रमोद सिन्हा), एनआईपीएफपी ब्लॉग, 25 जनवरी 2023.*
8. *विभिन्न विषयों पर 46 लेख, दि प्रिंट. https://theprint.in/author/radhika-pandey/*

अनुबंध VII: 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार स्टाफ सदस्यों की सूची

संकाय

1	डॉ. आर कविता राव	निदेशक (20.06.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
2	डॉ. सुप्रियो डे	प्रोफेसर (आरबीआई चेयर) (11.07.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
3	डॉ. एन.आर. भानुमूर्ति	प्रोफेसर
4	डॉ. लेखा एस. चक्रवर्ती	प्रोफेसर
5	डॉ. प्रताप रंजन जेना	प्रोफेसर (27.10.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
6	डॉ. मीता चौधरी	प्रोफेसर (27.10.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
7	डॉ. सच्चिदानंद मुखर्जी	प्रोफेसर (02.11.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
8	डॉ. एच.के. अमरनाथ	एसोसिएट प्रोफेसर
9	डॉ. रेणुका साने	एसोसिएट प्रोफेसर
10	डॉ. मनीष गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर
11	डॉ. रुद्राणी भट्टाचार्य	एसोसिएट प्रोफेसर
12	डॉ. अमेय सप्रे	एसोसिएट प्रोफेसर
13	डॉ. मुकेश आनंद	सहायक प्रोफेसर
14	डॉ. सुकन्या बोस	सहायक प्रोफेसर
15	डॉ. सुरांजलि टंडन	सहायक प्रोफेसर
16	डॉ. रॉली कुकरेजा	सहायक प्रोफेसर (14.11.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
17	डॉ. पियाली दास	सहायक प्रोफेसर (16.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
18	डॉ. मालविका महेश	सहायक प्रोफेसर (16.11.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
19	डॉ. दिनेश कुमार नायक	अर्थशास्त्री
20	डॉ. श्री हरि नायडू ए.	अर्थशास्त्री
21	डॉ.भाबेश हजारिका	अर्थशास्त्री
22	सुश्री अमनदीप कौर	अर्थशास्त्री

प्रशासनिक स्टाफ

1	सुश्री अलका मट्टा	सचिव (26.10.2022 को कार्यमुक्त)
2	श्री पंकज कुमार सिन्हा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
3	श्री विक्रम सिंह चौहान	निदेशक के निजी सचिव
4	श्री बी.एस.रावत	लेखा अधिकारी
5	श्री प्रवीण कुमार	निजी सचिव (31.05.2022 को सेवानिवृत्त)
6	सुश्री प्रोमिला राजवंशी	आशुलिपिक ग्रेड.I
7	सुश्री कविता इस्सर	आशुलिपिक ग्रेड.I
8	श्री अनुरोध शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड.I
9	श्री दर्शन सिंह पँवार	आशुलिपिक ग्रेड.II (प्रतिनियुक्ति पर)
10	सुश्री अमिता मन्हास	आशुलिपिक ग्रेड.II
11	श्री कपिल कुमार आहूजा	आशुलिपिक ग्रेड.II
12	सुश्री रुचि आनंद	सहायक

13	सुश्री उषा माथुर	आशुलिपिक ग्रेड.II
14	श्री वसीम अहमद	आशुलिपिक-टंकक (प्रतिनियुक्ति पर)
15	सुश्री दीपिका राय	सहायक
16	श्री शुभम् कुमार वर्मा	लिपिक (लेखा)
17	सुश्री मोनिका माथुर	स्वागतकर्ता-सह-टेलीफोन ऑपरेटर
18	श्री परशु राम तिवारी	चालक
19	श्री मोहन सिंह बिष्ट	फोटोकॉपी ऑपरेटर
20	श्री के.एन.मिश्रा	छात्रावास अटेंडेंट
21	श्री किशन सिंह	छात्रावास अटेंडेंट (30.06.2022 को सेवानिवृत्त)
22	श्री शिव प्रताप	माली
23	श्री रमेश कुमार	माली
24	श्री हरीश चंद	संदेशवाहक
25	श्री अजय कुमार	संदेशवाहक
26	श्री मुकेश	संदेशवाहक
27	श्री राजेंद्र कुमार	संदेशवाहक (प्रतिनियुक्ति पर)
28	श्री बिशम्बर पांडे	चौकीदार
29	श्री सुरेंद्र सिंह यादव	चौकीदार

कम्प्यूटर एकक

1	श्री रोबी थॉमस	अधीक्षक (कम्प्यूटर्स)

पुस्तकालय स्टाफ

1	सुश्री सोनम सिंह	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2	सुश्री सारिका गौड़	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)
3	सुश्री मंजू ठाकुर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
4	सुश्री आज़ाद कौर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
5	श्री राजन ढाका	वरिष्ठ पुस्तकालय अटेंडेंट
6	श्री नदीम अली	कनिष्ठ पुस्तकालय अटेंडेंट
7	श्री पूरन सिंह	संदेशवाहक

अकादमिक स्टाफ: संविदात्मक

1	श्री ए एन झा	वरिष्ठ फेलो
2	डॉ. राधिका पांडे	वरिष्ठ फेलो
3	श्री रत्नेश	वरिष्ठ फेलो (30.06.2022 को कार्यमुक्त)
4	श्री प्रमोद सिन्हा	फेलो-II
5	सुश्री रचना शर्मा	फेलो-II
6	श्री प्रीतम दत्ता	फेलो-II
7	श्री जय देव दुबे	फेलो-II (31.05.2022 को कार्यमुक्त)
8	श्री देवेन्द्र दामले	फेलो-II (29.04.2022 को कार्यमुक्त)

9	श्री अशीम कपूर	रिसर्च फेलो
10	श्री राहुल चक्रवर्ती	रिसर्च फेलो (08.07.2022 को कार्यमुक्त)
11	सुश्री सृष्टि शर्मा	रिसर्च फेलो (10.06.2022 को कार्यमुक्त)
12	श्री रोहित दत्ता	रिसर्च फेलो
13	सुश्री सबर्नी चौधरी	रिसर्च फेलो (21.05.2022 को कार्यमुक्त)
14	सुश्री शिवानी बडोल	रिसर्च फेलो
15	सुश्री स्मृति मेहरा	रिसर्च फेलो (22.04.2022 को कार्यमुक्त)
16	सुश्री अनन्या गोयल	रिसर्च फेलो (29.04.2022 को कार्यमुक्त)
17	सुश्री रागिनी	रिसर्च फेलो (31.08.2022 को कार्यमुक्त)
18	सुश्री गरिमा नैन	रिसर्च फेलो (30.06.2022 को कार्यमुक्त)
19	श्री डेनी जॉर्ज	रिसर्च फेलो (30.06.2022 को कार्यमुक्त)
20	सुश्री स्मृति बहल	रिसर्च फेलो (31.12.2022 को कार्यमुक्त)
21	सुश्री सोनल जैन	रिसर्च फेलो (31.10.2022 को कार्यमुक्त)
22	सुश्री ऐश्वर्या गवली	रिसर्च फेलो (31.03.2023 को कार्यमुक्त)
23	सुश्री अर्चिता श्रीधर	रिसर्च फेलो (01.09.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)
24	सुश्री सिमरन कौर	रिसर्च फेलो (17.10.2022 को कार्यमुक्त)
25	सुश्री सोनल अग्रवाल	रिसर्च फेलो (14.03.2023 को कार्यमुक्त)
26	सुश्री प्रियांशी गर्ग	रिसर्च फेलो (08.11.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)
27	सुश्री मार्गी पंड्या	रिसर्च फेलो (10.11.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)
28	सुश्री देवयानी गुप्ता	रिसर्च फेलो (30.11.2022 को कार्यमुक्त)
29	श्री उत्सव सक्सेना	रिसर्च फेलो (10.12.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)
30	सुश्री रितिका सिंह	रिसर्च फेलो (19.12.2022)
31	सुश्री कृति वट्टल	रिसर्च फेलो (05.01.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
32	सुश्री वी. राम्या राजश्री कुमार	रिसर्च फेलो (19.12.2022 को कार्यमुक्त)
33	सुश्री चेतना चौधरी	रिसर्च फेलो (30.01.2023 को कार्यमुक्त)
34	सुश्री अनिंदिता गुप्ता	रिसर्च फेलो (18.01.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
35	सुश्री नैन्सी गुप्ता	रिसर्च फेलो (31.03.2023 को कार्यमुक्त)
36	श्री अशोक भक्कर	रिसर्च फेलो (02.12.2022 को कार्यमुक्त)
37	सुश्री रॉली कुकरेजा	रिसर्च फेलो (11.11.2022 को कार्यमुक्त)
38	सुश्री मिताली गुरदत्ता	रिसर्च फेलो (06.04.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
39	सुश्री हर्षिता शर्मा	रिसर्च फेलो (31.10.2022 को कार्यमुक्त)
40	सुश्री रमनदीप कौर होरा	रिसर्च फेलो (29.11.2022 को कार्यमुक्त)
41	सुश्री ऐश्वर्या महापात्रा	रिसर्च फेलो (15.07.2022 को कार्यमुक्त)
42	श्री जितेश यादव	रिसर्च फेलो (20.03.2023 को कार्यमुक्त)
43	सुश्री स्मृति शर्मा	रिसर्च फेलो (10.06.2022 को कार्यमुक्त)
44	श्री किशन	रिसर्च फेलो (15.02.2023 को कार्यमुक्त)
45	सुश्री आयुषी खुराना	रिसर्च फेलो (16.12.2022 को कार्यमुक्त)
46	सुश्री नित्या चुटानी	रिसर्च फेलो (01.07.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
47	श्री गौरव	रिसर्च फेलो (31.10.2022 को कार्यमुक्त)
48	सुश्री स्मृति बनाती	रिसर्च फेलो (31.01.2023 को कार्यमुक्त)
49	सुश्री प्राची जैन	रिसर्च फेलो (26.10.2022 से 12.01.2023)

50	सुश्री वैशाली भारद्वाज	रिसर्च फेलो (01.09.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
51	सुश्री साक्षी राठी	रिसर्च फेलो (26.10.2022 को कार्यमुक्त)
52	श्री विस्मय बासु	रिसर्च फेलो (15.09.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
53	श्री एडम हुसैन	रिसर्च फेलो (09.09.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
54	सुश्री रिद्धि जैन	रिसर्च फेलो (28.02.2023 को कार्यमुक्त)
55	सुश्री ज्योत्सना छिकारा	रिसर्च फेलो (07.10.2022 से 28.02.2023)
56	सुश्री खुशबू आहूजा	रिसर्च फेलो (10.10.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
57	श्री अंकित सिंह	रिसर्च फेलो (12.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
58	श्री सुशील कुमार मोदी	रिसर्च फेलो (15.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
59	सुश्री राधिका अग्रवाल	रिसर्च फेलो (16.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
60	श्री आशीष राज	रिसर्च फेलो (19.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
61	डॉ. फिरदौस अहमद मलिक	रिसर्च फेलो (26.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
62	श्री प्रवीण सिंह	रिसर्च फेलो (08.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
63	सुश्री अनुकृति चौबे	रिसर्च फेलो (25.11.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
64	सुश्री मयूराक्षी मित्रा	रिसर्च फेलो (16.01.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
65	श्री सार्थक उदयवाल	रिसर्च फेलो (30.01.2023 से 20.02.2023)
66	सुश्री हरसिमर कौर साहनी	रिसर्च फेलो (02.01.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
67	डॉ करण सचदेवा	रिसर्च फेलो (01.02.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
68	सुश्री सौम्या अग्रवाल	रिसर्च फेलो (17.02.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
69	श्री सिराजुल इस्लाम यज़दानी	रिसर्च फेलो (27.02.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
70	सुश्री मधुर मेहता	रिसर्च फेलो (01.03.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
71	श्री अतुल कुमार	रिसर्च फेलो (27.03.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
72	सुश्री सीमा मौर्य	रिसर्च फेलो (27.03.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)

प्रशासनिक स्टाफ : संविदात्मक

1	श्री नवीन भल्ला	परामर्शक
2	श्री हरि शंकर गुप्ता	परामर्शक
3	सुश्री लता बालासुब्रमण्यम	कार्यक्रम सहायक
4	श्री कुलदीप सिंह	डाटा एंट्री ऑपरेटर (15.11.2022 को कार्यमुक्त)
5	श्री रोहित भदोरिया	परामर्शक
6	श्री मानेश वी एम	आईटी (परामर्शक) (30.06.2022 को कार्यमुक्त)
7	श्री सुरेश कुमार	कार्यक्रम सहायक
8	श्री राजू	चालक
9	सुश्री मोनिका	परामर्शक (01.04.2022 से 31.01.2023)
10	श्री रजनेश जून	परामर्शक (01.09.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
11	श्री विपिन कुमार	परामर्शक (07.02.2023 को कार्यभार ग्रहण किया)
12	सुश्री मीना	डाटा एंट्री ऑपरेटर
13	सुश्री मुमताज	डाटा एंट्री ऑपरेटर (06.06.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)

अनुबंध VIII: 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक, निगमित, स्थायी और सामान्य सदस्यों की सूची

क. प्रायोजक सदस्य

राज्य

1. आंध्र प्रदेश	7. उड़ीसा
2. असम	8. पंजाब
3. गुजरात	9. राजस्थान
4. कर्नाटक	10. तमिलनाडु
5. केरल	11. उत्तर प्रदेश
6. महाराष्ट्र	12. पश्चिम बंगाल

अन्य

1. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
2. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
3. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ख. स्थायी सदस्य - राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

1. अरुणाचल प्रदेश
2. गोवा, दमन और दीव
3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. मेघालय
6. मणिपुर
7. नागालैंड

ग. साधारण सदस्य - राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

1. हरियाणा
2. त्रिपुरा सरकार

घ. अन्य

1. मैसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

अनुबंध IX: वित्त और लेखे

मैसर्स अनीश आशीष एंड कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से लेखापरीक्षित संस्थान के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखाओं का विवरण

अनीश आशीष एंड कं.

के-28, तीसरा तल, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076
हैंडसेट:+91-9818395893, +91-9810261432
लैंडलाइन: 011-29942700, 011-41033026

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के आम निकाय के सदस्यगण

वित्तीय विवरण राय की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (इकाई) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा और वित्तीय विवरण की अनुसूचियां शामिल हैं, जिनके साथ उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश भी सम्मिलित है।

हमारी राय में, संलग्न किए गए वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 को संस्था की वित्तीय स्थिति और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन के बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की। उन मानकों के तहत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में आगे वर्णित हैं। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है और तात्विक गलतबयानी से मुक्त होता है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन इकाई की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो इकाई को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

जो शासन द्वारा प्रभारित हैं, वे इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य पूरी तरह से इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण तात्विक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और इसके उपरांत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा सदैव ही किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी, जहां हमेशा यह पता चल सकेगा कि कोई तात्विक त्रुटि मौजूद है या नहीं। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हमने:

- वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्या विवरण के जोखिमों को पहचाना और उनका आकलन किया, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित किया, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने के जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त की।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया है।
- प्रबंधन द्वारा चल रही चिंता के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो इकाई की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण इकाई एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन किया है, और यह देखा है कि क्या वे वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, को दूर करने के लिए शासन द्वारा प्रभारितों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन द्वारा प्रभारित के संबंध में, यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ संवाद करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों का प्रयोग किया है, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपाय भी संचालित किए हैं।

अन्य अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह सूचित करते हैं कि:

i. हमने वह समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
ii. हमारी राय में, जहां तक बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, इकाई द्वारा विधि द्वारा आवश्यक लेखाओं की उचित बहियां रखी गई हैं; और
iii. इस रिपोर्ट द्वारा निष्पादित तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखे, लेखाओं की बहियों के अनुरूप हैं।

अनीष आशीष एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेट
फर्म पंजीकरण सं. 002535N

आशीष गुप्ता
पार्टनर
एम.नं.503829
यूडीआईएन: 23503829BGWQYC6049
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 18 सितम्बर 2023

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि रु. में

	अनुसूची	31 मार्च 23 की स्थिति	31 मार्च 22 की स्थिति
कार्पस/पूंजीगत निधि एवं देनदारियां			
कार्पस/पूंजीगत निधि	**1**	14,29,99,759	13,63,36,103
आरक्षित और अधिशेष	**2**	24,58,10,714	22,08,10,714
आस्थगित आय	**3**	1,72,98,924	1,62,43,516
धर्मादा/विनिश्चित निधियां	**4**	39,96,17,394	35,83,88,507
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	**5**	12,63,07,081	14,39,29,545
कुल		**93,20,33,872**	**87,57,08,385**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	**6**	6,18,24,994	6,02,98,435
निवेश- धर्मादा/विनिश्चित निधियां	**7**	42,80,26,926	39,65,58,451
निवेश - अन्य	**8**	35,59,72,892	31,58,60,073
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**9**	8,62,09,060	10,29,91,426
योग		**93,20,33,872**	**87,57,08,385**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**17**		
लेखाओं पर टिप्पणियां	**18**		

अनुसूची 1 से 18 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के लिए

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(बी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डा. आर.कविता राव)	(डा. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

अनीष आशीष एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002535N

(आशीष गुप्ता)
पार्टनर
एम.सं.: 503829
यूडीआईएन:23503829BGWQYC6049
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक ;18 सितम्बर 2023

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रु. में

	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2023	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2022
आय			
केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान	**10**	8,58,51,283	13,30,92,481
अकादमिक क्रियाकलापों से आय	**11**	11,19,32,342	10,16,42,260
अर्जित ब्याज	**12**	2,21,49,702	1,96,46,661
अन्य आय	**13**	1,60,73,415	1,35,68,318
योग		**23,60,06,742**	**26,79,49,720**
व्युय			
स्थापना व्यय	**14**	7,21,87,220	12,31,63,293
अकादमिक क्रियाकलापों पर व्यय	**15**	9,00,40,685	9,27,10,617
प्रशासनिक व्यय	**16**	3,91,52,960	3,54,97,770
प्रकाशन स्टॉक में कमी		-	71,220
मूल्यह्रास	**6**	29,59,821	35,47,248
योग		**20,43,40,686**	**25,49,90,148**
वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के नाते शेष		3,16,66,056	1,29,59,572
घटाएं : पूर्व अवधि की मदें		2,400	-
व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के नाते शेष		3,16,63,656	1,29,59,572
घटाएं : अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व से अंतरित राशि		1,00,00,000	50,00,000
घटाएं : सामान्य रिजर्व को अंतरित राशि		1,50,00,000	50,00,000
कार्यिक/पूंजीगत निधि से ले जाए गए अधिशेष के नाते शेष		**66,63,656**	**29,59,572**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**17**		
लेखाओं पर टिप्पणियां	**18**		

अनुसूची 1 से 18 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के लिए

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(वी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डा. आर.कविता राव)	(डा. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

अनीष आशीष एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002535N

(आशीष गुप्ता)
पार्टनर
एम.सं.: 503829
यूडीआईएन: 23503829BGWQYC6049
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक ; 18 सितम्बर 2023

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

		31 मार्च, 23 की स्थिति		31 मार्च, 22 की स्थिति
अनुसूची 1 - कार्यिक/पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	13,63,36,103		13,33,76,531	
जोड़ें : आय और व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष	66,63,656		29,59,572	
		14,29,99,759		13,63,36,103
कुल		**14,29,99,759**		**13,63,36,103**
अनुसूची 2 - रिजर्व और अधिशेष				
क. अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व				
पिछले लेखा के अनुसार	9,21,89,863		8,71,89,863	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1,00,00,000		50,00,000	
		10,21,89,863		9,21,89,863
ख. सामान्य रिजर्व				
पिछले लेखा के अनुसार	12,81,20,851		12,31,20,851	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1,50,00,000		50,00,000	
		14,31,20,851		12,81,20,851
ग. मृतक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रिजर्व		5,00,000		5,00,000
योग		**24,58,10,714**		**22,08,10,714**
अनुसूची 3 - आस्थगित आय				
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से अनुदान				
पिछले लेखा के अनुसार	1,58,16,779		1,61,30,658	
घटाएं : आय और व्यय लेखा में अंतरित ऐसी आस्तियों के मूल्यह्रास के समतुल्य राशि	3,13,879		3,13,879	
		1,55,02,900		1,58,16,779
विभिन्न प्रायोजकों से अनुदान पूंजीगत आस्तियों के लिए प्रयुक्त				
पिछले लेखा के अनुसार	4,26,737		6,33,511	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	16,28,340		-	
घटाएं: ऐसी आस्तियों के मूल्यह्रास के समतुल्य राशि आय औरव्यय लेखा को अंतरित	2,59,053		2,06,774	
		17,96,024		4,26,737
योग		**1,72,98,924**		**1,62,43,516**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - धर्मादा/विनिर्धारित निधियां

राशि रु. में

विवरण	फोर्ड फाउंडेशन धर्मादा निधि	सरकारी धर्मादा निधि	भारतीय रिजर्व बैंक धर्मादा निधि	वैज्ञानिक अनुसंधान निधि	आजीवन सदस्यता निधि	विमल बागची अवार्ड निधि	जोखन मौर्य निधि	सरकारी कार्यिक निधि	राजा चेल्लैया वार्षिक व्याख्यान माला और अतिथि प्रोफेसरशिप निधि	कुल
प्रारंभिक निधि	61,77,924	1,00,00,000	10,00,00,000	7,27,406	4,20,000	50,000	29,300	12,00,00,000	2,00,00,000	
(क) निधियों का अथशेष	1,71,02,083	1,00,00,000	7,29,76,121	28,70,722	16,55,032	1,23,419	78,654	21,47,08,499	3,88,73,977	35,83,88,507
(ख) निधियों में अभिवृद्धियां										
(i) अनुदान	-	-	2,70,23,879	-	-	-	-	-	-	2,70,23,879
(ii) निवेश से आय	11,04,020	7,10,609	55,56,669	1,53,973	86,156	6,333	3,922	1,39,51,916	23,69,937	2,39,43,535
योग (क+ख)	**1,82,06,103**	**1,07,10,609**	**10,55,56,669**	**30,24,695**	**17,41,188**	**1,29,752**	**82,576**	**22,86,60,415**	**4,12,43,914**	**40,93,55,921**
(ग) निधि के प्रयोजनों के लिए उपयोग/व्यय	10,58,357	7,10,609	43,94,144	-	-	-	9,000	35,66,417		97,38,527
योग (ग)	**10,58,357**	**7,10,609**	**43,94,144**	-	-	-	**9,000**	**35,66,417**	-	**97,38,527**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख)-(ग)	**1,71,47,746**	**1,00,00,000**	**10,11,62,525**	**30,24,695**	**17,41,188**	**1,29,752**	**73,576**	**22,50,93,998**	**4,12,43,914**	**39,96,17,394**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च, 23 की स्थिति	31 मार्च, 22 की स्थिति
अनुसूची 5 - वर्तमान देनदारियां और प्रावधान		
क. वर्तमान देनदारियां		
1 माल और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	36,56,330	60,01,067
2 बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	9,48,277	11,62,083
3 अप्रयुक्त परियोजना अनुदान (देखिए अनुसूची 5(क))	5,74,70,944	6,72,12,546
5 सांविधिक देय	41,58,902	53,21,498
6 अन्य वर्तमान देनदारियां	1,24,29,168	1,35,81,576
योग	**7,86,63,621**	**9,32,78,770**
ख. प्रावधान		
1 छुट्टी नकदीकरण	4,76,43,460	5,06,50,775
योग	**4,76,43,460**	**5,06,50,775**
सकल योग	**12,63,07,081**	**14,39,29,545**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5(क) - परियोजना अनुदान

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार वसूलीयोग्य	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	योग	प्रयुक्त/प्राप्त की गई और आय और व्यय लेखा में क्रेडिट की गई	प्रयुक्त और आस्थगित आय में क्रेडिट की गई	योग	1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार वसूलीयोग्य	1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त
1	वित्तीय वैश्वीकरण और आर्थिक विकास-आईसीएसएसआर	1,77,433	-	-	1,77,433	-	-	1,77,433	-	-
2	स्वास्थ्य पर अनुसंधान और नीतियों में सुधार और उसका वित्त-पोषण - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	1,00,95,979	-	-	1,00,95,979	-	-	-	-	1,00,95,979
3	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन - स्वास्थ्य पर अनुसंधान और नीतियों में सुधार और उसका वित्त-पोषण - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	61,99,185	-	7,41,381	69,40,566	-	-	-	-	69,40,566
4	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण - यूएनडीपी	5,12,553	-	-	5,12,553	-	-	-	-	5,12,553
5	डिजिटल लैंड का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन - एनसीईएआर उप-अनुदान	9,27,993	-	-	9,27,993	-	-	-	-	9,27,993
6	एनआईपीएफपी - टीएआरआई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम	42,521	-	-	42,521	-	-	-	-	42,521
7	क्या मौद्रिक नीति भारत में वित्तीय स्थायित्व की दिशा में कार्य कर सकती है - आईसीएसएसआर	1,61,916	-	-	1,61,916	-	-	-	-	1,61,916
8	भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण के दृष्टिकोण : भावी मार्ग - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	2,45,91,407	-	4,29,00,546	6,74,91,953	3,38,42,087	9,00,010	3,47,42,097	-	3,27,49,856
9	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन - भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण के दृष्टिकोण : भावी मार्ग - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	28,89,821	-	12,00,483	40,90,304	-	-	-	-	40,90,304
10	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण - यूएनडीपी-II	1,87,710	-	-	1,87,710	-	-	-	-	1,87,710
11	हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए सहयोगी सेवा, हिमाचल प्रदेश - यूएनडीपी	-	21,366	-	(21,366)	-	-	-	21,366	-
12	एनआईपीएफपी - डीईए अनुसंधान कार्यक्रम - आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 2020-21	-	37,64,490	1,39,12,286	1,01,47,796	1,47,92,040	7,28,330	1,55,20,370	53,72,574	-
13	भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	1,71,64,511	-	-	1,71,64,511	1,71,64,511	-	1,71,64,511	-	-
14	भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	20,96,779	-	4,26,460	25,23,239	25,23,239	-	25,23,239	-	-
15	भूमि और संपत्ति अधिकारों पर अनुसंधान को समर्थन - ओमिडियार नेटवर्क-III	-	37,06,289	-	(37,06,289)	-	-	-	नोट-I देखें	-
	कुल अग्रेनीत	**6,50,47,808**	**74,92,145**	**5,91,81,156**	**11,67,36,819**	**6,83,21,877**	**16,28,340**	**7,01,27,650**	**53,93,940**	**5,57,09,398**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

Amount in ₹

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार वसूलीयोग्य	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	योग	प्रयुक्त/प्राप्त की गई और आय और व्यय लेखा में क्रेडिट की गई	प्रयुक्त और आस्थगित आय में क्रेडिट की गई	योग	1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार वसूलीयोग्य	1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त
	कुल अग्रानीत	**6,50,47,808**	**74,92,145**	**5,91,81,156**	**11,67,36,819**	**6,83,21,877**	**16,28,340**	**7,01,27,650**	**53,93,940**	**5,57,09,398**
16	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन:जीवीए और निवेश में अंशदान-एमसीए	1,51,682	49,24,890	1,77,159	3,28,841	3,28,841	-	3,28,841	-	-
17	राज्य वित्त आयोग - यूनिसेफ	1,99,962		99,83,838	1,01,83,800	84,22,254	-	84,22,254	-	17,61,546
18	बाल संरक्षण लोक व्यय समीक्षा-ओडिशा-यूनिसेफ	18,13,546	-	20,72,729	38,86,275	38,86,275	-	38,86,275	-	-
19	सार्वजनिक व्यय शासन और क्षेत्रीय असमानता में सतत विकास का लक्ष्य और उपलब्धियां : असम में एक जिला स्तरीय विश्लेषण-आईसीएसएसआर	-	-	3,00,000	3,00,000	3,02,447	-	3,02,447	2,447	-
20	एनआईपीएफपी-एमओएचयूए अनुसंधान कार्यक्रम-आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	-	-	-	-	14,19,982	-	14,19,982	14,19,982	-
	योग	**6,72,12,998**	**1,24,17,035**	**7,17,14,882**	**13,14,35,735**	**8,26,81,676**	**16,28,340**	**8,44,87,449**	**68,16,369**	**5,74,70,944**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5(ख) : केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान

Amount in ₹

	As at 31-Mar-22	As at 31-Mar-21
अप्रयुक्त अनुदान का आदिशेष	(1,04,57,942)	3,26,36,539
जोड़ें : वेतन और भत्तों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	9,50,00,000	8,88,00,000
	8,45,42,058	**12,14,36,539**
घटाएं : वेतन और भत्तों के लिए अप्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखा में आय के रूप में विचार किया गया)	8,47,51,283	13,18,94,481
योग - अप्रयुक्त/(वसूलीयोग्य) अनुदान	**(2,09,225)**	**(1,04,57,942)**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 6 - स्थायी परिसंपत्तियां

राशि रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 22 के अनुसार	जोड़	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 23 के अनुसार	1 अप्रैल 22 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 22 तक	31 मार्च 23 के अनुसार	31 मार्च 22 के अनुसार
स्वयं की निधियों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
1 पट्टा भूमि	1,88,09,202	-	-	1,88,09,202	-	-	-	-	1,88,09,202	1,88,09,202
2 भवन	3,39,05,360	-	-	3,39,05,360	1,46,67,731	8,35,123	-	1,55,02,854	1,84,02,506	1,92,37,629
3 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	3,08,77,233	10,82,849	2,10,749	3,17,49,333	2,97,90,340	5,10,823	2,00,520	3,01,00,643	16,48,690	10,86,893
4 कार्यालय उपकरण	1,00,21,648	71,071	-	1,00,92,719	94,15,542	2,75,673	-	96,91,215	4,01,504	6,06,106
5 फर्नीचर और जुड़नार	1,25,40,540	60,999	-	1,26,01,539	1,11,80,795	1,94,009	-	1,13,74,804	12,26,735	13,59,744
6 छात्रावास, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	36,41,172		-	36,41,172	36,39,380	406	-	36,39,786	1,386	1,792
7 एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	76,62,766	15,38,781	-	92,01,547	60,29,140	3,47,847	-	63,76,987	28,24,560	16,33,626
8 विद्युत संस्थापनाएं	70,58,615	91,071	-	71,49,686	63,98,577	1,04,883	-	65,03,460	6,46,226	6,60,039
9 वाहन	14,24,148		-	14,24,148	7,64,261	1,15,042	-	8,79,303	5,44,845	6,59,887
## बागवानी उपकरण	1,09,780	23,500	-	1,33,280	1,09,780	3,083	-	1,12,863	20,417	-
योग	**12,60,50,464**	**28,68,271**	**2,10,749**	**12,87,07,986**	**8,19,95,546**	**23,86,889**	**2,00,520**	**8,41,81,915**	**4,45,26,071**	**4,40,54,918**
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
केंद्रीय सरकार										
1 भवन - अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	2,12,89,579	-	-	2,12,89,579	54,72,800	3,13,879	-	57,86,679	1,55,02,900	1,58,16,779
2 विद्युत, अग्निशामक एवं एचवीएसी कार्य-अनुसंधान प्रशिक्षण	69,00,850	-	-	69,00,850	69,00,850	-	-	69,00,850	-	-
योग	**2,81,90,429**	-	-	**2,81,90,429**	**1,23,73,650**	**3,13,879**	-	**1,26,87,529**	**1,55,02,900**	**1,58,16,779**
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	41,56,385	7,28,330	-	48,84,715	40,24,368	23,756	-	40,48,124	8,36,591	1,32,017
2 कार्यालय उपकरण	2,16,380	-	-	2,16,380	2,07,206	-	-	2,07,206	9,174	9,174
3 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आईसीएसएसआर	51,500	-	-	51,500	48,925	-	-	48,925	2,575	2,575
4 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण-एमएमएसएसपीएसवाई, एमपी से साक्ष्य	89,000	-	-	89,000	40,692	28,183	-	68,875	20,125	48,308
5 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आरबीआई	1,06,650	-	-	1,06,650	55,701	33,772	-	89,473	17,177	50,949
योग	**46,19,915**	**7,28,330**	-	**53,48,245**	**43,76,892**	**85,711**	-	**44,62,603**	**8,85,642**	**2,43,023**
स्थायी परिसंपत्तियां - एफसीआरए										-
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	9,880	-	-	9,880	9,880	-	-	9,880	-	-
2 फर्नीचर और जुड़नार	15,23,860	-	-	15,23,860	15,23,860	-	-	15,23,860	-	-
3 बागवानी उपकरण	6,24,980	-	-	6,24,980	6,24,980	-	-	6,24,980	-	-
योग	**21,58,720**	-	-	**21,58,720**	**21,58,720**	-	-	**21,58,720**	-	-
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां - एफसीआरए										
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आईडीआरसी	1,54,571	-	-	1,54,571	1,46,842	-	-	1,46,842	7,729	7,729
2 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - बीएमजीएफ-II	7,80,953	-	-	7,80,953	6,14,285	1,73,239	-	7,87,524	8,93,439	1,66,668
3 कार्यालय उपकरण - एनसीईएआर उप-अनुदान	22,000	-	-	22,000	20,797	103	-	20,900	1,100	1,203
4 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - बीएमजीएफ-III	1,62,250	-	-	1,62,250	1,54,137	-	-	1,54,137	8,113	8,113
योग	**11,19,774**	-	-	**11,19,774**	**9,36,061**	**1,73,342**	-	**11,09,403**	**9,10,381**	**1,83,713**
सकल योग	**16,21,39,302**	**35,96,601**	**2,10,749**	**16,55,25,154**	**10,18,40,869**	**29,59,821**	**2,00,520**	**10,46,00,170**	**6,18,24,994**	**6,02,98,433**
पिछला वर्ष	**16,21,39,303**	**3,58,045**	**5,950**	**16,24,91,398**	**10,18,40,868**	**35,47,248**	-	**9,82,93,620**	**6,02,98,435**	

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

			31 मार्च 2023 की स्थिति		31 मार्च 2022 की स्थिति
अनुसूची 7 - निवेश - धर्मादा/विनिर्धारित निधियां					
दीर्घकालिक निवेश					
सरकारी प्रतिभूतियों में			12,74,04,000		9,70,13,079
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			24,39,82,160		19,26,31,348
वर्तमान निवेश					
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			5,66,40,766		10,69,14,024
योग			**42,80,26,926**		**39,65,58,451**
अनुसूची 8 - निवेश - अन्य					
दीर्घकालिक निवेश					
सरकारी प्रतिभूतियों में			7,04,46,000		9,50,10,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			21,40,64,963		12,95,00,963
वर्तमान निवेश					
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			7,14,61,929		9,12,70,611
प्रतिभूति जमा के विरुद्ध अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा			-		78,499
योग			**35,59,72,892**		**31,58,60,073**
अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि					
क. वर्तमान परिसंपत्तियां :					
1. वस्तु-सूची					
प्रकाशनों का स्टॉक			19,717		19,717
2. विविध लेनदार			2,52,728		2,03,218
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/अप्रदाय सहित)			35,510		24,768
4. बैंक शेष					
अनुसूचित बैंकों के साथ - बचत खाते					
केनरा बैंक जोत सिंह मार्ग खाता सं.1484101001555	3,52,00,983		3,12,44,787		
केनरा बैंक जोत सिंह मार्ग खाता सं. 14841060260094	2,806		3,101		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू खाता सं.10596549875	19,186		18,677		
स्टेट बैंक आफ इंडिया मुख्य शाखा एसबी खाता सं.40070210371	55,580		33,294		
अनुसूचित बैंकों के साथ - चालू खाते					
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू एफ.सी.खाता सं. 10596547368	68,59,688		1,31,47,036		
स्टेट बैंक आफ इंडिया जेएनयू चालू खाता सं. 10596547355	41,360		42,009		
ख..		4,21,79,603			4,44,88,904
ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां :-					
1. अग्रिम और अन्य राशियां नकद अथवा सामान अथवा प्राप्त होने वाला कीमत के रूप में वसूलीयोग्य					
क) पूर्वसंदत्त व्यय	55,17,600		79,64,628		
ख) व्ययों के लिए स्टाफ का अग्रिम	97,388		1,40,198		
ग) अन्य अग्रिम	40,76,701		2,32,176		
घ) प्रतिभूति जमा	5,75,479		5,88,719		
ड) इनपुट कर क्रेडिट	4,57,151		72,550		
		1,07,24,319			89,98,271
2. प्रोद्भूत आय					
क) निवेश आय - विनिर्धारित/धर्मादा निधियां	57,44,642		37,06,316		
ख) निवेश आय - अन्य	22,40,527		19,59,516		
ग) राज्य सरकार का अनुदान	-		1,00,000		
घ) पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	40,37,620		77,62,530		
ड.) परियोजना अनुदान (अनुसूची 5(क) देखें)	68,16,369		74,92,145		
च) अप्रयुक्त/(प्राप्तियोग्य) अनुदान - एमआएफ (अनुसूची 5(ख) देखें)	2,09,225		1,04,57,941		
		1,90,48,383			3,14,75,448
3. प्राप्तियोग्य दावे					
क) प्राप्तियोग्य आयकर		1,39,48,800			1,77,81,100
योग		**8,62,09,060**			**10,29,91,426**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 10 - केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान		
क. **केंद्रीय सरकार से अनुदान**		
वेतन अनुदान (अनुसूची 5(ख) देखें)	8,47,51,283	13,18,94,481
योग (क)	**8,47,51,283**	**13,18,94,481**
ख. **राज्य सरकारों से अनुदान**		
सामान्य सहायता अनुदान		
ओडिशा सरकार	5,00,000	5,00,000
महाराष्ट्र सरकार	1,00,000	98,000
तमिलनाडु सरकार	-	1,00,000
गुजरात सरकार	-	5,00,000
नागालैण्ड सरकार	5,00,000	-
योग (ख)	**11,00,000**	**11,98,000**
सकल योग (क+ख)	**8,58,51,283**	**13,30,92,481**
अनुसूची 11- अकादमिक क्रियाकलापों से आय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय		
प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदान (अनुसूची 5(क) देखें)	2,92,50,666	1,21,60,321
	8,26,81,676	8,94,81,939
योग	**11,19,32,342**	**10,16,42,260**
अनुसूची 12 - अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज - बैंक/वित्तीय संस्थाएं		
अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खातों पर	26,91,621	44,39,783
सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों पर	4,69,255	4,36,464
आयकर वापसी पर ब्याज	1,84,18,558	1,47,03,606
अन्य ब्याज	5,03,460	-
	66,808	66,808
योग	**2,21,49,702**	**1,96,46,661**
अनुसूची 13 - अन्य आय		
प्रकाशनों की विक्री		
वसूलियां	-	200
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	1,48,02,047	1,19,15,528
विविध आय	1,719	1,20,122
मकान किराया वसूलियां	4,43,755	8,30,777
एनआईपीएफपी स्टाफ से प्राप्त परामर्श शुल्क	90,849	1,15,894
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	1,55,570	-
आस्थगित आय से अंतरित राशि (अनुसूची 3 देखें)	6,543	65,144
	5,72,932	5,20,653
योग	**1,60,73,415**	**1,35,68,318**

राष्ट्रीय लाक वित्त एव नाात संस्थान

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग वनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 14 -स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	7,69,66,081	12,43,89,907
पीएफ और पेंशन निधि अंशदान	75,47,188	1,17,95,602
उपदान	22,30,066	29,61,210
छुट्टी वेतन	32,01,000	1,04,14,291
कर्मचारी लाभ और कल्याण	44,47,734	39,60,995
ईडीएलआई और प्रशासनिक प्रभार	1,65,905	2,16,136
परामर्श शुल्क	37,80,373	7,79,075
	9,83,38,347	**15,45,17,216**
घटाएं : अकादमिक क्रियाकलापों के लिए प्रभारित	2,61,51,127	3,13,53,923
योग	**7,21,87,220**	**12,31,63,293**
अनुसूची 15 - अकादमिक क्रियाकलापों पर व्यय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना व्यय	73,59,009	32,28,678
परियोजना अनुदानों का उपयोग (अनुसूची 5(क) देखें)	8,26,81,676	8,94,81,939
योग	**9,00,40,685**	**9,27,10,617**
अनुसूची 16 - प्रशासनिक व्यय		
यात्रा और परिवहन	3,54,895	4,00,638
दरें और कर	11,67,188	11,88,962
विद्युत प्रभार	60,11,985	66,36,218
जल प्रभार	3,79,619	3,33,907
मुद्रण और लेखन-सामग्री	4,94,330	4,02,718
डाकशुल्क और टेलीफोन	8,02,924	8,72,537
मरम्मत और अनुरक्षण	1,39,65,865	1,66,83,867
कार संचालन और अनुरक्षण	2,64,455	1,08,019
लेखापरीक्षा शुल्क	1,66,716	1,87,614
लेखापरीक्षा शुल्क- आंतरिक	1,33,599	1,33,473
लेखापरीक्षा शुल्क (पीएफ न्यास)	24,000	24,962
लेखापरीक्षा शुल्क (उपदान न्यास)	25,960	25,960
विविध व्यय	2,60,733	17,86,080
विधिक व्यय	9,558	4,76,782
विज्ञापन व्यय	2,70,384	4,90,767
पीएफ की परिपक्वता/उपदान न्यास निवेश पर हानि	3,76,057	1,22,580
पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,02,45,198	89,82,164
प्रकाशन की लागत	1,81,678	1,19,680
वैठकें और संगोष्ठियां	1,99,278	1,59,600
सामान्य/शासी निकाय की वैठक	1,32,390	-
वीमा व्यय	1,25,296	1,43,417
वसूलीयोग्य वट्टे खाते में डाला गया	73,44,130	-
व्यावसायिक शुल्क	67,331	1,13,500
25वीं वर्षगांठ पर व्यय	60,000	30,000
	4,30,63,569	3,94,23,445
घटाएं : धर्मादा/निर्धारित निधियों के लिए प्रभारित	7,10,609	7,25,675
घटाएं : धर्मादा/निर्धारित निधियों के लिए प्रभारित	32,00,000	32,00,000
योग	**3,91,52,960**	**3,54,97,770**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 17 - लेखांकन नीतियां

1 वित्तीय विवरणों का निर्माण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक अभिसमय के अधीन उपचय आधार पर और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखाकरण मानकों, यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, के अनुसार किया जाता है। सामान्य सदस्यता शुल्क को नकद आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

2 वित्तीय विवरणिकाएं तयार करने के लिए ऐसे प्राक्कनों और पूर्वानुमानों की अपेक्षा होती है जिनसे प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों, राजस्व और व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित होती है। यद्यपि ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी मित्नताओं को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम परिणत होते हैं।

3. दीर्घावधिक निवेशों को ह्रास, अस्थाई के अलावा, के समायोजन के पश्चात उनकी वहन लागत पर अग्रेनित किया जाता है। चालू निवेश लागत और उचित मूल्य में से न्यूनतर के आधार पर अग्रेनित किए जाते हैं। निवेशों की लागत में, यदि अन्यथा उल्लेय न किया गया हो, प्रीमियम सहित सभी अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई चेयर औफ इंस्टीट्यूट के लिए दी गई कायिक निधि में से प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों, जब इन्हें प्रीमियम पर अधिग्रहीत किया गया हो, का उल्लेख आरबीआई और संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन के नियमों और शती के अनुसार आरबीआई कायिक निधि से उपार्जित ब्याज आय के सापेक्ष किया गया है।

4. प्रकाशनों की मानसूची का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर किया गया है। दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशन और परियोजना अनुदानों से वित्त-पोषित प्रकाशनों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है।

5. अचल परिसम्पतियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया गया है जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल हैं। अचल परिसम्पतियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है।

6. प्रबंधन द्वारा पाँच प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य पर विचार के पश्चात परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर सरल रेखा पद्धति से मूल्यहास प्रभारित किया गया है। परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है-:

परिसम्पति विवरण	उपयोज्यता काल
भवन	60 वर्ष
डेटा संसाधन उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
होस्टल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	8 वर्ष
एयर कंडीनर एवं वाटर कूलर	10 वर्ष
विद्युत संस्थापनाएं	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
बागवानी उपकरण	5 वर्ष

7. प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से किसी परिसम्पत्ति का क्षय होने के संबंध में आकलन किए जाते हैं। ऐसे क्षय के किसी संकेत के मामले में, प्रबंधन द्वारा परिसम्पति के माध्यम से वसूलीयोग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वाहित राशि से कम है, तो परिसम्पत्ति की वाहित राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और अंतर को अक्षमता हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

8. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीद के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. अल्पावधिक कर्मचारी लाभों को आय एवं व्यय के लेखे में छूट न दी गई राशि के व्यय के रूप में सेवाएं प्रदान किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया गया है।

10. रोजगार के बाद के और अन्य दीर्घावधिक लाभों को उस वर्ष के आय व्यय लेखे में छूट न दी गई राशि पर हए व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर स्वीकृति दी गई है। रोजगार-पश्चात और अन्य दीर्घावधिक लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को सामान्यतः संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखा पुस्तिकाओं में लेखाबद्ध किया गया है।

12. चिह्नित/वृत्ति निधियों से निवेशों पर आय का उपयोग निधियों के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशि के शेष को, यदि कोई हो, संबंधित चिह्नित/वृत्ति निधियों में रखा गया है।

13. विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभिक तौर पर देनदारी माना गया है और वर्ष के दौरान उपयोगिता के अनसार समायोजित किया गया है। अनुदानों को, मूल्यहास के योग्य परिसम्पत्तियों के लिए प्रयुक्त सीमा तक, आस्थगित आय माना गया है और इन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक आधार पर आय और व्यय लेखे में स्वीकृति दी गई है। राजस्व व्ययों के लिए प्रयुक्त सीमा तक वेतनों और परियोजना अनुदानों को वर्ष की आय माना गया है। आवर्ती व्ययों के लिए अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

14. प्रावधानों को वहां स्वीकृति दी गई है जब विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारी हो तथा जिसके लिए यह संभव हो कि देनदारी के समाधान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा और विश्वसनीय प्राक्कलन संभव हो सकेगा। देनदारी के समाधान के लिए अपेक्षित प्रावधानों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और जहां देनदारी के चालू सर्वोत्तम प्राक्कलन के लिए आवश्यक हो, समायोजित किया गया है।

15. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया गया है जब एक संभावित देनदारी या वर्तमान देनदारी हो जिसके लिए संसाधनों का वह बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो सकता हो, जो संभावित रूप से अपेक्षित नहीं है। उस वर्तमान देनदारी के संबंध में भी प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो, जहां संबंधित बहिर्प्रवाह का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जाना संभव न हो।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियां

संस्थान के विरूद्ध एवं संस्थान द्वारा दायर किए न्यायिक मामलों के संबंध में देयता : राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियां : शून्य रु. (पिछले वर्ष : शून्य वर्ष)

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संज्ञान की गई और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के खंड 22 में अनुपालन में संस्थान में उपलब्ध देयताएं:

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई मूल राशि।	11,51,083	21,26,158
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज तथा वर्ष के अंत में चुकता न की गई बकाया राशि।	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता को तथा एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की राशि के साथ चुकता किए गए ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान किए जाने में देरी की अवधि के लिए देय एवं बकाया व्याज (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता किया गया है) जिसे एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट व्याज जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उससे संबंधित उद्भूत और चुकता न किया गया ब्याज	-	-
आगामी वर्षों में भुगतान न किए जाने के कारण देय और भुगतान किए जाने योग्य बढ़त ब्याज की राशि जिसे ऐसी तारीख तक, जब ऊपर उल्लिखित ब्याज देय को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को वास्तविक रूप से चुकता किया जाना है।	-	-

4. संस्थान के प्रबंधन के मतानुसार, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कारोबार के सामान्य क्रम में कम से उस राशि के समान है जिस पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान वित्तीय विवरणिका में किया गया है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,39,48,801 रु. के वसूलीयोग्य आयकर में से, 38,77,570 रु. की वसूलीयोग्य आयकर की राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 और पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित है।

बंदोबस्ती/निर्धारित निधि के निवेश में 17,95,14,957 रु. का उद्धृत निवेश और 24,85,11,969 रु. का गैर-उद्धृत निवेश शामिल है, उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य 18,21,40,106 रु. है।

अन्य निधियों के निवेश में 3,82,84,963 रु. के उद्धृत निवेश और 31,76,87,929 रु. के गैर-उद्धृत निवेश शामिल हैं। उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य 3,82,31,364 रु. है।

5. वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त परिभाषित अंशदायी योजना में योगदान का विवरण निम्नानुसार है:

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 68,75,333 रु. (पिछले वर्ष 1,10,36,734.50 रु.)

पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान 6,64,941 रु. (पिछले वर्ष 7,58,867 रु.)

किसी न्यास द्वारा प्रबंधित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना परिभाषित लाभ योजना विद्यमान है। देनदारी के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के रूप में स्वीकृत किया गया है और अंतिम देनदारी निर्मित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा गया है। छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी को इसी तरीके से ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत किया गया है।

6. तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मूल बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार है:

क) आर्थिक अनुमान

मूल पूर्वानुमान इस प्रकार हैं (1) छूट की दर (2) वेतन वृद्धि। छूट वृद्धि लेखाकरण तिथि को सरकारी बंधपत्रों पर उपलब्ध बाजार अर्जन पर उस शर्त पर आधारित है जो देयताओं की शर्तों से मिलती हो और वेतन वृद्धि में मूल्यवृद्धि, वरिष्ठता, प्रोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, अक्षमता के लिए कोई सुस्पष्ट भते का उपयोग नहीं किया गया है।

	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
i)	छूट की दर	7.50% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष
ii)	भावी वेतन वृद्धि	9.75% प्रतिवर्ष	9.50% प्रतिवर्ष
iii)	उपदान के लिए योजना परिसम्पत्तियों की प्रत्याशित प्रतिफल दर (वित्त-पोषित)	7.00% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष
ख)	**जनसांख्यिकी अनुमान**	**31 मार्च 2023**	**31 मार्च 2022**
i)	सेवानिवृत्ति आयु	वर्ष 60	वर्ष 60
ii)	मृत्यु सारणी	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
iii)	निकासी दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%

7. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी इन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक हो, पुनर्निर्मित, पुन:प्रतिशत समूहबद्ध, पुनःव्यवस्थित और पुनःवर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

कृते राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता/-	हस्ता./-
(बी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डॉ. आर. कविता राव)	(डॉ. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार।

अनीश आशीष एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002535N

आशीष गुप्ता
पार्टनर
एम.सं. 503829
यूडीआईएन : 23503829BGWQYC6049
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितम्बर 2023

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

.:18/2, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू), नई दिल्ली, भारत - 110067
.: 011-26569303, 26569780, 26569784
.: https://www.nipfp.org.in